पंचम माला, खंड 60, अंक 21, मंगलवार, 6 अप्रैल, 1976/17 चैत्र, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LX, No. 21, Tuesday, April 6, 1976/ Chaitra 17, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 18-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 60 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. LX contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 21, मंगलवार 6 अप्रैल, 1976/17 चैत्र, 1898 (शक)

No. 21, Tuesday, 6th April, 1976/Chaitra 17, 1898 (Saka)

ता० प्र० संख्या विषय S. Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 401, 402, 406 से 409, 412, 413 और 416	*Starred Questions Nos., 401, 402, 406 to 409, 412, 413 and 416 . .	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS;	
तारांकित प्रश्न संख्या 403, 404, 410, 411, 414, 415 और 417 से 420	Starred Questions Nos. 403, 404, 410, 411, 414, 415 and 417 to 420 . .	18—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 2020 से 2025 और 2027 से 2105	Unstarred Questions Nos. 2020 to 2025 and 2027 to 2105	24—60
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	61
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . .	62
208वां प्रतिवेदन	Two hundred and eighth Report	62
संविधान (32वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Thirty Second Amendment) Bill—	32
संयुक्त समिति में रिक्त स्थान भरने के लिए राज्य सभा के सदस्य नियुक्त करने के लिये राज्य सभा से सिफारिश	Recommendation to Rajya Sabha to appoint Rajya Sabha Members to fill vacancies in the Joint Committee	
अनुदानों की मांगें, 1976-77	Demands for Grants 1976-77 . .	63
रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence . . .	63
श्री शिवाजी राव एस० देशमुख	Shri Shivaji Rao S. Deshmukh .	63
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	64
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	65
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan . . .	66
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh . . .	67
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . . .	68

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi . .	69
श्री वीरेन्द्र दत्त	Shri Biren Dutta	70
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	70
श्री ईराज्मु द सैकैरा	Shri Erasmo de Sequeira . .	71
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . .	72
श्री अनन्त राव पाटिल	Shri Anantrao Patil . . .	72
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari . . .	73
श्री एस० राधाकृष्णन	Shri S. Radhakrishnan . . .	73
श्री रण बहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh . .	74
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R.S. Pandey . . .	75
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	75
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	76
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh . .	77
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh . . .	77
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	78
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Smt. T. Lakshmikanthamma . .	79
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey . .	79
श्री बंसी लाल	Shri Bansi Lal	80

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 6 अप्रैल, 1976/17 चैत्र, 1898 (शक)

Tuesday, April 6, 1976/Chaitra 17, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रेलवे में वस्तु-सूचियों का कम्प्यूटरों द्वारा नियंत्रण

*401. **श्री के० मालन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में वस्तु-सूचियों का नियंत्रण कड़ा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) भारतीय रेलवे में वस्तु-सूचियों की कम्प्यूटरों के माध्यम से नियंत्रण व्यवस्था लागू करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सामान-सूची पर नियंत्रण को कड़ा करने के लिए रेलों ने सामान-सूची नियंत्रण संबंधी आधुनिक तकनीक, जैसे वर्गीकरण, मानकीकरण, किस्म घटाना, मूल्य विश्लेषण, ए०बी०सी० विश्लेषण, आदि लागू की है। 1972 के अन्त तक प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में सामान-सूची नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की गयी थी और इस कक्ष को, अन्य कार्यों के साथ-साथ, कारगर सामान-सूची प्रबन्ध-व्यवस्था के लिए रेलों द्वारा आवश्यक रूप से अपनायी जाने वाली पद्धति और प्रक्रिया निर्धारित करने तथा रेलों पर सामान प्रबन्ध-व्यवस्था के सभी पहलुओं पर चयनात्मक नियंत्रण द्वारा उन्हें क्रियान्वित करवाने का काम सौंपा गया था।

इसके अतिरिक्त, रेलवे राज्य मंत्री, श्री मोहम्मद शफी कुरेशी की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति ने, जो रेलों पर प्रचलित भंडार प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए गठित की गयी थी, भण्डार की खरीद, सप्लाई कर्त्ताओं के बिलों के भुगतान और भण्डारों के निपटारे आदि तथा उत्पादन यूनिटों में सामान प्रबन्ध-व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति की सिफारिशों से, जिन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है, खर्च में किफायत होने की संभावना है जिसके फलस्वरूप सामान-सूचियों में कमी होगी।

(ख) भण्डार का हिसाब-किताब रखने तथा सामान-सूची नियंत्रण के काम को संगणक द्वारा करने का काम मोटे तौर पर चार चरणों में बांट दिया गया है और इस समय इसे कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। नवीनतम स्थिति यह है कि संगणक पर मूल्य बहियों के इन्दराज से संबंधित चारों भाग, सामान की बेहतर व्यवस्था के लिए विभिन्न लेखा विवरणों और अपवाद रिपोर्टों को तैयार करने, सभी क्रयादेशों का हिसाब संगणक द्वारा रखने और कुछ क्रयादेशों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए अपवाद रिपोर्टें तैयार करने, खरीद के पुनरादेश स्तर पर पहुंचते ही खरीद की कार्रवाई शुरू करने के लिए संगणक द्वारा आपूर्ति को स्वतः सूचना देने और प्रबन्धकों के इस्तेमाल के लिए कार्रवाई प्रलेख प्रस्तुत करने तथा कुछ नियंत्रण रिपोर्टें प्रस्तुत करने के काम को कार्यान्वित किया गया है।

खरीद लेखा रजिस्टरों के इन्दराज से संबंधित अगले चरण की कार्रवाई को प्रणाली अभिकल्प और कार्यक्रम लेखन के लिए शुरु कर दिया गया है। सीधे भण्डार नियंत्रक द्वारा दिये जाने वाले सप्लाई आदेशों से संबंधित क्रय लेखे सबसे पहले मध्य और पश्चिम रेलों पर रखने का प्रस्ताव है। इन रेलों पर इनके सफल कार्यान्वयन के बाद, यह व्यवस्था अन्य रेलों पर भी लागू कर दी जायेगी।

श्री के० मालन्ना: सामान-सूची पर नियंत्रण कड़ा करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में सामान-सूची नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। माननीय मंत्री, श्री मोहम्मद शफी कुरेशी की अध्यक्षता में बनी एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने भी भण्डार की खरीद, सप्लाई कर्त्ताओं के बिलों के भुगतान और भण्डारों के निपटारे आदि के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इन सिफारिशों का क्या परिणाम तथा प्रभाव पड़ा है?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: भारतीय रेलवे में, सामान-सूची पर नियंत्रण कड़ा करने के लिए हमने आधुनिक तकनीक, जैसे वर्गीकरण, मानकीकरण, ए०बी०सी० विश्लेषण आदि लागू किए हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में हमने सामान-सूची नियंत्रण कक्षों की स्थापना की है। उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने भी अपना प्रतिवेदन पेश किया है। हमने देखा है कि नए तरीके अपनाने से भारतीय रेलवे में सामान-सूची में काफी कमी हुई है। मैं 1972-73 और 1974-75 के तुलनात्मक आंकडे पेश करता हूं। वर्ष 1972-73 की समाप्ति पर सामान-सूचियां 55 प्रतिशत थी जो कि 1974-75 में घटकर 41 प्रतिशत ही रह गई। नए तरीकों को अपनाकर पर्याप्त सुधार हुआ है।

औषध उद्योग का भारतीय क्षेत्र

*402. **श्री भालजी भाई रावजीभाई परमार:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र की सहायता करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) इस संबंध में लाइसेंस देने, आयात करने तथा अन्य सुविधाओं के बारे में मार्ग-दर्शी सिद्धांत क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र, जिसमें 40 प्रतिशत तक विदेशी साम्य पूंजी वाली कंपनियां शामिल हैं / जहां तक सरकारी क्षेत्र का संबंध है, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० की प्रायोजना विस्तार के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। संभाव्यता रिपोर्ट के आधार पर इन यूनिटों का विस्तार करने की परिकल्पना निम्न रूप में है :—

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०

हैदराबाद के सिन्थेटिक ड्रग्स प्लांट का विस्तार करने में 21.79 करोड़ रुपये का निवेश निहित है जिससे 1988 मी० टन से बढ़कर 3886 मी० टन तक उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जायेगी।

विहार में निकोटिनामाइड संयंत्र की स्थापना करने में 8.58 करोड़ रुपये के अनुमानित पूंजीगत परिव्यय निहित है।

हरियाणा में गुड़गांव में एक नए सूत्रयोग यूनिट की स्थापना करने में 8.10 करोड़ रुपये का अनुमानित पूंजीगत परिव्यय निहित है।

ऋषिकेश में एन्टीबायोटिक्स संयंत्र का विस्तार करने में 15.69 करोड़ रुपये का लगभग निवेश है।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड

पैंसिलीन संयंत्र की क्षमता का विस्तार करने में 2.92 करोड़ रुपये का अनुमानित पूंजीगत परिव्यय निहित है।

स्ट्रेप्टोमाइसिन संयंत्र का विस्तार करने में 2.91 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

सेमि-सिन्थेटिक पैंसिलीन संयंत्र का विस्तार करने में 1.67 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

इरिथ्रोमाइसिन संयंत्र की स्थापना करने में 4.16 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

नए सूत्रयोग संयंत्र की स्थापना करने में 4.46 करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान लगाया गया है।

भारतीय गैर-सरकारी क्षेत्र के संबंध में लाइसेंस देने की उदार नीति अपनाई जा रही है और 1975 में 40 प्रतिशत तक विदेशी साम्यपूंजी वाले फर्मों से 50 से अधिक आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

लाइसेंस देने, आयात आदि से संबंधित मार्ग-दर्शनों को, सरकार द्वारा वार्षिक रूप में प्रकाशित 'गाइड लाइन्स फार इन्डस्ट्रीज़ एण्ड इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल पोलिसी' नामक प्रकाशन में दिया गया है। भारतीय क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र आदि को मजबूत बनाने के लिये हाथी समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं और ये सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

श्री मालजी भाई परमार: जैसा कि प्रायः संसद सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है, हाथी समिति ने अनुमति पत्रों तथा कार्य जारी रखने संबंधी लाइसेंसों को अवैध घोषित कर दिया है। जिन अधिकारियों ने ये पत्र जारी किए हैं, इसके लिए वे दोषी हैं। सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है?

श्री पी०सी० सेठी: जहां तक अनुमति पत्रों का संबंध है, उन्हें वैध दस्तावेज़ समझा जाता है और इसलिए किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मालजी भाई परमार: सूत्रयोग के लिए भारतीय फ़र्मों के कितने औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र अस्वीकार किए गए हैं? उन फर्मों के क्या नाम हैं, कितनी क्षमता के लिए आवेदन पत्र दिया गया, आवेदन पत्र में उस मद की विदेशी फर्म के साथ कहां तक स्पर्धा करने के लिए कहा गया और आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं? क्या सरकार भारतीय क्षेत्र की कंपनियों के सभी अस्वीकृत प्रस्तावों पर पुनर्विचार करेगी और उन्हें तत्काल लाइसेंस जारी करेगी? और क्या सरकार आगे से सूत्र योग के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को अस्वीकार नहीं करेगी?

श्री पी०सी० सेठी: ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हो गई है।

डा० रानेन सेन: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री जी को इस बात का पता है कि हाथी समिति ने लाइसेंस जारी करने वाले उच्च सरकारी अधिकारियों से पूछताछ की हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अधिकांश कार्य जारी रखने संबंधी लाइसेंस, अनुमति पत्र तथा अनापति पत्र अवैध, अनियमित थे और उन्होंने उस समय सरकार से सिफारिश की कि उन्हें रद्द कर दिया जाये और भारतीय कम्पनियों को ऐसी औषधियां, जैसे बाटरबरीज कंपाउण्ड आदि, तैयार करने की अनुमति दी जाये जो कि बहुत आवश्यक हों और जिनके लिए आधुनिकतम जानकारी आवश्यक नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

श्री पी०सी० सेठी: मैं माननीय सदस्य का ध्यान हाथी समिति की पहली सिफारिश की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि आयातित पुंज औषधियों, जिनका कुछ कम्पनियां निर्माण कर रही हैं, पर आधारित सूत्रयोगों के मामले में उन्हें पुंज औषधियों का निर्माण एक निर्धारित अवधि के अन्दर करने के लिए कहा जायेगा। यह पहली सिफारिश है।

दूसरी सिफारिश यह है कि जहां कहीं भारतीय कम्पनियां इनका निर्माण कर सकती हैं वहां विदेशी कम्पनियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इस नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

डा० रानेन सेन: यह गुमराह करने वाला उत्तर है। मैंने विशेषरूप से दो या तीन औषधियों का उल्लेख किया है जो कि आवश्यक नहीं हैं और जिनके निर्माण के लिए भारत में जानकारी उपलब्ध है। इन गैर-आवश्यक औषधियों के निर्माण की क्षमता के विस्तार के लिए विदेशी कम्पनियों को अनुमति क्यों दी जा रही है, जिनके लिए हमारे देश में जानकारी उपलब्ध है?

श्री पी० सी० सेठी : माननीय सदस्य एक या दो औषधियों के विशिष्ठ नाम बता रहे हैं। अब 16,000 सूत्रयोगों में से उस विशेष औषधि का नाम याद रखना कठिन है जिसको कि वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा।

श्री के० एस० चावड़ा : आयातित कच्चे माल पर आधारित सूत्रयोगों के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कार्य जारी रखने संबंधी लाइसेंसों तथा अनुमति पत्रों को हाथी समिति ने अस्वीकार कर दिया है और फिर भी अभी सरकार आयात करने की अनुमति दे रही है। क्या मंत्री जी सभा को आश्वासन देंगे कि 1971 के बाद भारतीय कम्पनियों के सभी अस्वीकृत प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया जायेगा और उन्हें लाइसेंस जारी किए जाएंगे यद्यपि इसमें आयातित कच्चा माल भी सम्मिलित है। जब तक हाथी समिति की सिफारिशें स्वीकार की जाती है क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय कम्पनियों के अस्वीकृत प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया जायेगा और भारतीय उद्योग के हितार्थ तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए और साथ ही विदेशी मुद्रा की बचत के लिए उन्हें लाइसेंस जारी किए जायेंगे।

श्री पी० सी० सेठी : मैं पुनः यह बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न का संबंध प्रश्न संख्या 14 से है। फिर भी यदि आपने आज्ञा दे दी है तो मैं माननीय सदस्य को इसका उत्तर दे देता हूं।

जिन 10 कम्पनियों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उनमें से तीन कम्पनियों में 50 से भी कम व्यक्ति काम कर रहे हैं और इसलिए उन्हें कार्य जारी रखने संबंधी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दो कम्पनियां औषधियों का निर्माण नहीं कर रही हैं इसलिए उन्हें भी इस तरह के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। दो कम्पनियां अपने उत्पादन का ऋण लाइसेंस आधार पर निर्माण करवा रही हैं; इसलिए उन्हें भी इस तरह के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। एक कम्पनी ने 1973 की नीति के अन्तर्गत कार्य जारी रखने संबंधी लाइसेंस प्राप्त किया है। एक कम्पनी ने इस तरह के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र नहीं भेजा इसलिए उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की सोची गई है। एक कम्पनी ने पंजीकरण प्रमाणपत्र सहित एक कारखाना खरीद लिया है। जहां पंजीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध है; वहां विधि संबंधी जटिलताओं पर विचार किया जा रहा है।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या यह हाथी समिति की सिफारिश है कि सभी भारतीय कम्पनियों के प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

श्री पी० सी० सेठी : वास्तव में हम भारतीय कम्पनियों के लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्रों पर उदारता से विचार कर रहे हैं। किन्तु साथ ही हमने कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। पहला प्रतिबन्ध यह है कि भारतीय कम्पनी के उत्पादन का दसवां हिस्सा पुंज औषधि के रूप में होना चाहिए और इस पुंज औषधि उत्पादन का 66 प्रतिशत देशी कच्चे माल से बनना चाहिए। यदि वे इन दो शर्तों को पूरा करेंगे तो हम उन्हें अनुमति दे देंगे।

श्री अनन्त राव पाटिल : जहां तक भारतीय औषधि उद्योग को मजबूत बनाने का सम्बन्ध है, क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार ने एच०ए०एल०, पिम्परी तथा भारतीय औषधि तथा भेषज लिमिटेड, ऋषिकेश, इन दो सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के विस्तार के लिए कोई योजना बनाई है? वे योजनाएं क्या हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने हाल ही में एच०ए०एल० का जो दौरा किया है, उसकी उन पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या एच०ए०एल० कुछ प्रगति कर रहा है अथवा नहीं?

श्री पी० सी० सेठी: हम पांचवीं योजना में एच०ए०एल० तथा भारतीय औषधि तथा भेषज लिमिटेड पर लगभग 70 करोड़ रुपये व्यय करेंगे। एच०ए०एल० पर 30 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। 21.79 करोड़ रुपये हैदराबाद में सिंथेटिक औषधि संयंत्र पर व्यय होंगे। इससे उसकी उत्पादन क्षमता 1938 टन से बढ़कर 3896 टन हो जायेगी। इसी तरह हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के विस्तार के लिए भी विभिन्न योजनाएं हैं।

मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि मैंने एच०ए०एल० का दौरा अभी नहीं किया है।

उत्तर लखीमपुर रेलवे स्टेशन से चोरी गयी धनराशि की वसूली

*406. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर लखीमपुर रेलवे स्टेशन से लगभग दो वर्ष पूर्व गायब हुई दो लाख रुपये से अधिक की राशि बरामद करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) उस स्टेशन पर इतनी बड़ी राशि किस कारण जमा हुई थी; और

(ग) इस मामले में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 13-5-1971 को नार्थ लखीमपुर के स्टेशन मास्टर ने रिपोर्ट की थी कि उसकी रोकड़ पेटी से 1,38,949.70 रुपये की नकद रकम और 85,789.80 रुपए के सैनिक जमा-पत्रों के वाउचर चुरा लिये गये हैं। वाउचरों की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर 49,835.80 रुपए एकत्र किये जा चुके है और शेष 35,954 रुपये विभिन्न सैनिक और अन्य यूनिटों से एकत्र किये जा रहे हैं। बाकी रकम वसूल करने की कार्रवाई उस समय की जायेगी जब जिन कर्मचारियों का पुलिस ने चालान किया है उनके विरुद्ध अदालत में चल रहे मामले को अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

(ख) स्टेशन पर इतनी बड़ी रकम के जमा हो जाने का कारण यह था कि स्टेशन मास्टर ने स्टेशन की आमदनी समय पर नहीं भेजी थी।

(ग) पुलिस ने जिन कर्मचारियों का चालान किया है उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अधीन जांच पूरी कर ली गयी है लेकिन चूंकि मामला अदालत में है इसलिए अभी विभागीय कार्रवाई निलम्बित रखी गयी है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : विवरण में बताया गया है कि स्टेशन पर इतनी बड़ी रकम के जमा होने का कारण यह था कि स्टेशन मास्टर ने स्टेशन की आमदनी समय पर नहीं भेजी थी।

रेलवे के वर्गीकरण के अनुसार, नार्थ लखीमपुर स्टेशन 'घ' श्रेणी का स्टेशन है और यहां पर 1,38,949.70 रुपये जमा होने में एक सप्ताह से अधिक समय लगता है। मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे इस संबंध में क्या तरीका अपनाती है। क्या रेलवे स्टेशन की आय दूसरे दिन जमा करा दी जाती है या यह कई सप्ताहों तक रेलवे स्टेशन में ही पड़ी रह सकती है और क्या जांच अधिकारी के लिये यह जरूरी नहीं है कि वह यह सुनिश्चित करे कि रेलवे स्टेशन पर आय अधिक लम्बे समय तक रेलवे स्टेशन के पास ही नहीं पड़ी रहे।

श्री बूटा सिंह : इस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर 16 दिन बाद नकदी जमा कराता था जबकि नियम 24 घंटे बाद जमा कराने का है। जांच प्राधिकारी डिवीजन के यातायात विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं।

श्री विश्वनारायण सिंह : क्या यातायात विभाग के यह प्राधिकारी भी स्टेशन मास्टर से मिले हुए थे और इस प्रकार उन्होंने 1,38,000 रुपये का गबन कर लिया ? यदि हां तो फिर उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू करने से पहले, उन्हें सेवा से बर्खास्त या मुअत्तिल क्यों नहीं किया गया ?

श्री बूटा सिंह : हमने उत्तर सीमान्त रेलवे के महा-प्रबन्धक से विस्तृत जांच करने और लोगों को जिम्मेदार ठहराने के लिये कहा है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अवश्य होगी ?

श्री बालकृष्ण वेकंन्ना नायक : हैरानी की बात है कि गबन 13 मई, 1971 को यानि पांच साल पहले हुआ और विवरण में कहा गया है कि कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अधीन जांच पूरी कर ली गई है लेकिन चूंकि मामला अदालत में है इसलिये अभी विभागीय कार्रवाई निलम्बित रखी गई है। पांच साल के बाद भी आपने उस स्टेशन मास्टर को बर्खास्त नहीं किया। अभी भी उससे कुछ रकम लेनी है। क्या विभागीय जांच में यह साबित नहीं हो गया कि इस आदमी ने धोखा दिया है और यह किसी की मिली भगत से हुआ है ? फिर इसमें छः वर्ष क्यों लगे ?

श्री बूटा सिंह : निसंदेह इस संबंध में देरी हुई है लेकिन जब मामला अदालत में है तो हम जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं वह अदालत के फैसले के अधीन होगी। इस अधिकारी को मुअत्तिल कर दिया है और अनुशासनात्मक कार्यवाही हो रही है।

श्री डी० बसुमन्तर : क्या इस शिकायत का एक कारण यह भी है कि इस डिवीजन में रेलवे जनरल मैनेजर का तबादला जल्दी जल्दी होता रहता है और नया आने वाला जनरल मैनेजर भ्रष्ट अधिकारियों पर काबू पाने में असमर्थ रहता है ? इस प्रकार थोड़े-थोड़े समय बाद होने वाले स्थानांतरण के बारे में बहुत सी शिकायतें आई हैं जिनका भ्रष्ट लोग फायदा उठाते हैं। मेरे विचार में यह मामला भी इसलिये हुआ कि सारा नियंत्रण केवल दो अधिकारियों के हाथों में ही है। जनरल मैनेजर को किसी भी बात का पता नहीं। मैं उनसे मिला था और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कुछ नहीं मालूम।

श्री बूटा सिंह : इस बात का प्रश्न से कोई संबंध नहीं है जनरल मैनेजर को थोड़े थोड़े समय बाद स्थानान्तरित नहीं किया जाता। मैं माननीय सदस्य के इस आक्षेप को नहीं मानता।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं स्टेशन मास्टर के इस कुकृत्य पर हैरान नहीं हूं। जब मैं रेल अभिसमय समिति में था तो मैंने रेलवे की समस्त लेखा पद्धति की छानबीन की थी। क्या रेलवे अभिसमय समिति ने तीन साल पहले यह नहीं कहा था कि समस्त लेखा पद्धति बहुत ही पुरानी है ? यह पद्धति अंग्रेज लाये थे और इस पद्धति में मिलान की व्यवस्था नहीं है। रेलवे अधिकारियों को लेखा-पद्धति आधुनिक तरीकों का ज्ञान नहीं है और वे नये तरीकों और विचारों को अपनाना ही नहीं चाहते। क्या माननीय मंत्री ने पांच वर्ष के दौरान लेखा पद्धति की आन्तरिक जांच की उन मौलिक कमियों को जानने की कोशिश की है जिसके कारण इस प्रकार का गबन होता है ? दूसरे, रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन पर, जिसमें रेलवे की लेखा-पद्धति के पूर्ण आधुनिकीकरण की मांग की गई है, क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य के इस सुझाव के बारे में मुझे यह कहना है कि रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया है और हम रेलवे की लेखा पद्धति में सुधार कर रहे हैं।

श्री डी० एन० तिवारी : प्रश्न लेखा पद्धति अथवा लापरवाही का नहीं है। प्रश्न यह है कि धनराशि एक या दो सप्ताह तक जमा नहीं कराई गई। रेलवे अधिकारियों ने स्टेशन मास्टर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया और उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया ? क्या स्टेशन मास्टर को उसी दिन पुलिस को सौंपा गया और उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया ?

श्री बूटा सिंह : स्टेशन मास्टर को जी०आर०पी० द्वारा गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। उसके बाद उसे जमानत पर रिहा किया गया और अब उसका मामला अदालत में है।

श्री डी० एन तिवारी : क्या वह काम कर रहा है।

श्री बूटा सिंह : नहीं, उसे मुअत्तिल कर दिया गया है।

तेल उद्योग के लिये नियंत्रक कंपनी की स्थापना का प्रस्ताव

*407. **श्री डी०डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उद्योग के लिये एक नियंत्रक कम्पनी स्थापित करने तथा इण्डियन आयल कम्पनी, भारत रिफाइनरीज और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी को एक ही प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन लाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्री डी० डी० देसाई : सरकार के तेल की खोज, उत्पादन और शोधन के अपने डिवीजन हैं। भारत रिफाइनरीज़ और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को भी हमने अपने हाथ में ले लिया है। अब जबकि तेल की कीमत काफी अधिक है क्या सरकार कार्यचालन और नियंत्रण को एक साथ मिलाकर फीड-स्टाक लागत, प्रोसेसिंग लागत और विपणन लागत में बचत करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है जबकि सरकार ने कालटैक्स का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : बर्मा शैल और ऐस्सो के सरकारी नियंत्रण में आने के बाद तेल उद्योग के कार्यकरण में कुछ मूलभूत परिवर्तन हो गये हैं। कालटैक्स और आसाम तेल कम्पनी से भी बातचीत चल रही है और ये दोनों कम्पनियां भी शीघ्र ही सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आ जायेंगी। इन तेल कंपनियों के सरकारी नियंत्रण में आने के बाद इनका कुछ पुनर्गठन आवश्यक होगा। उनके कार्यों को देश के सर्वोत्तम हितों में लगाना होगा। किन्तु साथ ही हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित नहीं होना चाहते और राष्ट्रीय हित को भी ध्यान में रखेंगे।

श्री डी०डी० देसाई : यह प्रतिस्पर्धा दो या तीन डिवीज़नों को एक ही प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत लाकर कायम रखी जा सकती है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह देखें कि विपणन में कितनी बचत हो सकती है। यदि विभिन्न तेल शोधनशालाओं के उत्पादों के विभिन्न ग्रेडों के स्टाक पर और बयाज पर, जो कि

काफी अधिक होता है और जिसे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है और प्रोसेसिंग तथा जमा करने में विदेशी मुद्रा की कितनी हानि होती है आदि पर विचार किया जाये तो पता चलेगा कि यह बचत 10 प्रतिशत तक हो सकती है। सो क्या माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे ?

श्री केशव देव मालवीय : तकनीकी कारणों और यातायात की समस्याओं के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। विभिन्न शोधनशालाओं की व्यवस्था में चाहे यह अमरीकी प्रबन्ध के अधीन हो अथवा ब्रिटिश प्रबन्ध के अधीन, काफी अन्तर है। इन सभी प्रश्नों पर विचार करना होगा और ये सभी कंपनियां सरकारी क्षेत्र में रहेंगी। प्रतिस्पर्धा भी बहुत जरूरी है। अतः इन प्रश्नों पर विचार करते समय हम एक निश्चित ढांचा बनायेंगे।

श्री राजा कुलकर्णी : समाचार पत्रों में बताया गया है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, इण्डियन आयल और भारत रिफाइनरीज़ के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और वितरण के तरीकों के मामले में एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई है।

अब आपने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत रिफाइनरीज़ के लिये एक ही चैयरमैन बना दिया है। इस अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिये क्या आप इन तीनों कम्पनियों के लिए केवल एक ही चैयरमैन बनाना चाहते हैं। इससे इन कम्पनियों के बीच अच्छा तालमेल हो सकेगा।

श्री केशव देव मालवीय : मैं सरकार की ओर से यह नहीं कह सकता कि इन तीनों कम्पनियों का केवल एक ही चेयरमैन होगा। किन्तु इनका पुनर्गठन होगा। और इससे सम्बन्धित नई और पुरानी सभी समस्याओं पर विचार करना होगा। हो सकता है कि इनके बीच कुछ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। यह तो निहित कमजोरियां हैं जिन्हें ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने कहा है कि इन कम्पनियों के बीच कुछ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। इन कम्पनियों के बीच तालमेल बिठाने हेतु सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

श्री केशव देव मालवीय : मैंने यह नहीं कहा कि इनके बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। मैंने तो यह बात सामान्यतः कही थी। हम तीनों कम्पनियों के कार्यचालन के लिये एक नई व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कम्पनियां सरकारी क्षेत्र में आ जायेंगी। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि ये कम्पनियां सुचारू रूप से कार्य करें और अनावश्यक वस्तुओं पर कम धन खर्च करें।

उत्तरी क्षेत्र में तेल की खोज की योजना

*408. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र में तेल की खोज करने की सरकार की कोई योजनायें हैं; और

(ख) क्या सरकार ने पंजाब में कोई भूकम्पीय सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का उत्तरी क्षेत्र, इसमें जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश शामिल हैं, में तेल के लिये अन्वेषण करने का विचार है। इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में रामशहर, हिमाचल प्रदेश में अन्वेषण व्यधन कार्य प्रारम्भ किये जाने की आशा है। हो सकता है यह कार्य इससे भी पहले आरम्भ किया जाये।

(ख) जी हां । तथापि भूकम्पीय सर्वेक्षणों में संरचनात्मक बातों का पता नहीं चला है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: यह एक प्रमुख प्रश्न है कि उत्तर भारत के मैदानों में तेल है अथवा नहीं । परन्तु हाल में एक भू-वैज्ञानिक ने हमें मार्ग दिखाया है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भू-वैज्ञानिक सिद्धांतों से यह पता चला है कि उत्तरी क्षेत्र में 3,000 से 4,000 फुट मोटी सैडीमेंट मौजूद है और यदि हां, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री के० डी० मालवीय: तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वैज्ञानिक विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं, जिन से इस क्षेत्र में तेल की संभाव्यता की जांच की जा सके । मैं किसी ऐसे विशिष्ठ स्थान के बारे में नहीं कह सकता, जहां सैडीमेंट (गाद) की मोटाई के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सके, परन्तु यह 3,000 से 4,000 फुट मोटी नहीं है । इन क्षेत्रों में जहां मोटी तह मौजूद है, वहां तेल अथवा गैस के भंडार होने की सम्भावना है । इन सब प्रश्नों की विस्तारपूर्वक जांच की गई है और इन जांचों के परिणामस्वरूप हमने उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों का पता लगाया है, जहां आगामी महीनों में हमारा अन्वेषक छिद्रण करने का प्रस्ताव है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि भारतीय भू-वैज्ञानिकों तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वैज्ञानिकों से उन क्षेत्रों का संयुक्त सर्वेक्षण कराया जाये, जहां तेल मिलने की संभावना है ? क्या देश में तेल का पता लगाने के लिये स्थायी आधार पर कोई संयुक्त तन्त्र बनाया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय: मेरा तात्पर्य तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के भू-वैज्ञानिकों से था, किन्हीं अन्य वैज्ञानिकों से नहीं । मुझे किन्हीं अन्य भू-वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के बारे में जानकारी नहीं है । उन के सिद्धांतों में कोई नई बात नहीं है । यह खतरा उठाने का प्रश्न है ।

Shri Narsingh Narain Pandey: While addressing Birbal Sahani Institute, he has stated that methane gas has been found in considerable quantity in Shahjahanpur, Badaun etc. in U.P. and he would like the Geo-Scientists and others to conduct a survey of the area in consultation with O.N.G.C. It appears that the possibility of finding methane gas in northern area is increasing. All of the Indo-Nepal border sphere is oily area. The entire Indo-Nepal border from Bihar to UP is only belt and exploration should be done there by the Geo-scientists. Has ONGC made any attempt in this regard?

Shri K. D. Malaviya: I do not know of any other place except Jawalamukhi, where methane gas deposits might be found and there too perhaps the gas deposits are not in commercial quantity. As a result of the drilling in Badaun, Shahjahanpur and Hoshiarpur traces of gas were found and required work is being done at these places.

हल्दिया तेलशोधक कारखाने का विस्तार

*409. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया तेल-शोधक कारखाने के विस्तार-कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस तेल-शोधक कारखाने की क्षमता को बढ़ाकर 70 लाख टन कर देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री श्री जियाउर्रहमान अंसारी : (क) व (ख) इस समय हल्दिया शोधनशाला की क्षमता के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अर्जुन सेठी : पूर्वी भारत में स्थित तेलशोधनशालाओं की कुल क्षमता कितनी है तथा क्या यह क्षमता पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध अशोधित तेल के लिये पर्याप्त है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : पूर्वी भारत में चार तेलशोधनशालायें हैं—एक बरौनी में जहां 30 लाख मीटरी टन अशोधित तेल का शोधन किया जाता है, दूसरी हल्दिया में जहां की प्रतिस्थापित क्षमता 25 लाख मीटरी टन है, तीसरी नुनमती में जहां मोटे तौर पर 8 लाख मीटरी टन तेल का शोधन किया जाता है और चौथी एक छोटी शोधनशाला डिगबोई में है, जहां 5 लाख मीटरी टन का शोधन किया जाता है । ये सब मिल कर पूर्वी क्षेत्र की पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई को पूरा करने के लिये काफी हैं । जब कभी थोड़ा असंतुलन हो जाता है तो इसको को पूरा करने के लिये हम या तो विदेशों से अधिक मिट्टी के तेल का आयात करते हैं अथवा देश के पश्चिमी भागों से पैट्रोलियम उत्पाद मंगाते हैं ।

माननीय सदस्य को एक बात पर ध्यान देना चाहिये कि यदि हम राज्य विशेष अथवा क्षेत्र विशेष की इच्छाओं के अनुसार शोधनशालाओं का विस्तार करें, तो इसे अशोधित तेल के आयात से जोड़ना होगा । हमें जितनी मात्रा में अशोधित तेल उपलब्ध होता है, उसका सब शोधनशालाओं में समन्वित रूप से वितरण किया जाता है । हम इस प्रश्न को सदा ध्यान में रखते हैं और यदि आवश्यक एवं सम्भव हुआ तो अवश्य हल्दिया शोधनशाला का विस्तार किया जायेगा ।

श्री अर्जुन सेठी : कुछ दिन पहले माननीय मंत्री ने सभा में कहा था कि आसाम स्थित शोधनशालाओं की क्षमता आसाम में उपलब्ध अशोधित तेल के लिये पर्याप्त नहीं है । इस संदर्भ में क्या उनका विचार हल्दिया तक अशोधित तेल को पाइपलाइन से लाने का है, ताकि उसकी वर्तमान क्षमता का उपयोग किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो निकट भविष्य में उस का विस्तार किया जा सके ?

श्री के० डी० मालवीय : आसाम का अशोधित तेल तकनीकी तौर पर हल्दिया शोधनशाला जैसी शोधनशाला के उपयोग के लिये नहीं है, क्योंकि यह लयूब तेल पर आधारित है । आसाम के तेल से लयूब तेल नहीं बनाया जा सकता । इस लिये आसाम के अशोधित तेल का नुनमती/डिगबोई बोंगाईगांव अथवा बरौनी में शोधन किया जाता है । हल्दिया आयाधित अशोधित तेल पर आधारित है, जिस का आयात इरान तथा इराक से किया जाता है ।

श्री राजा कुलकर्णी : मुख्य प्रश्न यह है कि क्या 25 लाख मीटरी टन की हल्दिया की वर्तमान क्षमता देशी और आयातित दोनों प्रकार के अशोधित तेल पर आधारित है ? यह प्रश्न बोनगाइगांव शोधनशाला के पूरा हो जाने की संभावना से पैदा हुआ है, जो कि आसाम के कच्चे तेल पर आधारित होगी । इससे यह भय उत्पन्न हो गया है कि हल्दिया शोधनशाला देशी अशोधित तेल से अपनी शत-प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं कर सकेगी । इस लिये यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या वर्तमान क्षमता का उपयोग देशी अशोधित तेल से किया जाता है अथवा आयातित अशोधित तेल से ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य ने सही कहा है कि हल्दिया शोधनशाला इस समय आसाम अशोधित तेल पर आधारित नहीं है और न ही निकट भविष्य में होगी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हल्दिया की वास्तविक क्षमता कितनी है तथा इस समय कितनी क्षमता का उपयोग किया जाता है ? यदि पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता, तो इस के कारण क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : हल्दिया शोधनशाला की प्रतिस्थापित क्षमता 25 लाख मीटरी टन है । परन्तु हम पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाये हैं । इस में कई समस्यायें हैं, कुछ तकनीकी कठिनाइयां हैं । अशोधित तेल के मूल्य बढ़ रहे हैं, इस लिये खरीद की भी कठिनाई है ।

डा० रानेन सेन : प्रश्न यह है कि वहां कितना उत्पादन होता है ?

श्री के० डी० मालवीय : हम समझते हैं कि जल्दी ही जून में या इस से भी पहले मई में ही लयूब तेल का उत्पादन लगभग पूरी क्षमता के अनुसार होगा ।

बहुराष्ट्रिक निगमों का पूंजी-निवेश

*412. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रिक निगमों का औद्योगिक क्षेत्र, औषध क्षेत्र तथा उर्वरक क्षेत्र के अन्तर्गत भारत में स्थित उनकी सहायक कम्पनियों की शेयर पुंजी में पूंजी निवेष वर्ष 1972-73 की तुलना में वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 में बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) उनकी सहायक कम्पनियों के क्या नाम हैं और उपरोक्त अवधियों में उनका पूंजी निवेश कितना रहा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरणपत्र प्रस्तुत है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 10630/76**]

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विवरण के अनुसार 1974 में भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रदत्त पंजी 129 करोड़ रुपये से बढ़कर 144.6 करोड़ हो गई । यह वृद्धि चिंताजनक है । आज दिन तक बहुराष्ट्रीय निगमों की 137 सहायक कम्पनियों में से केवल 63 ने सरकार के समक्ष तुलनपत्र प्रस्तुत किये हैं । बहुराष्ट्रीय निगमों को देश में पूंजी निवेश की अनुमति देने के लिये क्या सिद्धांत नियत किये गये हैं । इस बारे में, वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों का तो मुझे पता है लेकिन व्यापक रूप से एक आरोप यह लगाया जाता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों ने गैर-जरूरी क्षेत्र में निवेश किया है । क्या सरकार बहुराष्ट्रीय निगमों को धन लगाने की अनुमति देते समय इस पहलू पर विचार करती है ? बहुराष्ट्रीय निगमों की शेष सहायक कम्पनियों के तथ्य उपलब्ध होने पर क्या सरकार उन्हें सभा पटल पर रखेगी ?

श्री बेदव्रत बरूआ : सदस्य महोदय ने वर्ष 1974-75 और 1975-76 सम्बन्धी प्रश्न किया था इसलिये मुझे उत्तर देना पड़ा । हमारे पास वर्ष 1973-74 और उनसे पूर्व वर्षों के आंकड़े हैं । चूंकि कम्पनी अधिनियम में तुलन-पत्र सम्बन्धी नियम उल्लिखित हैं । ये सहायक

कम्पनियां उन नियमों का पालन करती हैं । उन्हें वर्ष के दौरान इस समय तुलन-पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं । मैंने 63 कम्पनियों के बारे में आंकड़े दिये हैं, मुझे आशा है कि कुछ महीनों में 74 कम्पनियों के आंकड़े और उपलब्ध हो जायेंगे । बहुराष्ट्रीय निगमों को बड़े औद्योगिक गृह ही माना जाता है । अतः फरवरी, 1973 की औद्योगिक लाइसेंस नीति में निवेश संबंधी जो नियम बड़े औद्योगिक गृहों के लिये हैं वे ही बहुराष्ट्रीय निगमों पर भी लागू होते हैं । यदि उनमें विदेशी शेयर बहुमत में हैं तो वे निबंधनकारी उद्योगों की श्रेणी में आ जाते हैं । सदस्य महोदय के अनुसार ये निगम गैर-जरूरी क्षेत्र में धन लगाते हैं । लेकिन ये निगम 100 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत निर्यात वाले उद्योगों में ही धन लगा सकते हैं । वे अपने उत्पाद का निर्यात करते हैं और स्थानीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते । मैं मानता हूं कि 63 कम्पनियों में विदेशी पूंजी और प्रदत्त पूंजी दोनों बढ़ी हैं लेकिन बहुराष्ट्रीय निगमों की कुल निधि वही रही है । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के लागू होने पर सभी विदेशी कम्पनियों को 40% तक शेयर रखने होंगे । कुछ बड़े जटिल और आधारभूत उद्योगों में यह 74% तक हो सकता है ।

श्री सी० के० चन्द्रपन : पिछले सप्ताह कोका कोला में निवेश पर चर्चा करते समय हमने इस पहलू पर भी विचार किया था । जब इस क्षेत्र में उन्हें कार्य करने की अनुमति दी थी तो सरकार इसे किस हद तक अनिवार्य मानती थी ? अब यह बात ध्यान में रखते हुए कि ये बहुराष्ट्रीय निगम विभिन्न देशों में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेती हैं, क्या सरकार इन बहुराष्ट्रीय निगमों की सहायक कम्पनियों में निदेशक नियुक्त करने पर विचार करेगी ? कम्पनी अधिनियम की धारा 408(1) में अधिकारों का वर्णन है । क्या सरकार ऐसे कदम उठायेगी जिससे यह सुनिश्चित हो कि हमारे हितों के विरुद्ध कुछ न होने पाये और हमारी जानकारी के बिना वे कोई बात न कर सकें ?

श्री बेदव्रत बरूआ : जहां तक सभा में कोका कोला पर हुई चर्चा का प्रश्न है, इन गैर-जरूरी चीजों के लिये अब लाइसेंस नहीं दिये जाते । लेकिन जब वह कम्पनी पहले ही भारत में चल रही है तो उसके कार्यों को विनियमित करने का प्रश्न रह जाता है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वे अपने कार्य का विस्तार कर रहे हैं ।

श्री बेदव्रत बरूआ : मेरी जानकारी के अनुसार मंत्रालय द्वारा आवेदनों पर विचार किये जाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों का पूर्ण अधिपत्य न हो । ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जाते । उन्होंने अलग क्षेत्रों में कार्य-विस्तार किया है । उदाहरण के लिये एक कम्पनी बिस्कुट या सिगरेट या मछली पालन या मशीनें बनाने के धंधे में लग सकती है । देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन को देखते हुए इन निगमों का योगदान निरन्तर कम होता जा रहा है । जहां तक तोड़-फोड़ का प्रश्न है, यह काम मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं है । धारा 408 राजनीतिक गतिविधियों पर लागू नहीं होती । धारा 408 में वैसे स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी कम्पनी में निधि का दुरुपयोग या कुप्रयोग किया जाता है और सरकार के पास इस विश्वास का कारण है कि शेयर-होल्डरों के साथ धोखा हुआ है तो नये निदेशकों की नियुक्ति की जा सकती है । लेकिन यह कार्य सरकार का न होकर कम्पनी विधि बोर्ड का है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : विवरण से पता चलता है कि 51 बहुराष्ट्रीय निगम और उनकी सहायक कम्पनियां भारत में कार्य कर रही हैं । मैं जानना चाहता हूं कि लॉकहीड षड्यन्त्र का यह पता चलने

पर कि बहुत से लोगों को धन दिया गया क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि विभिन्न संघों और हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड से सम्बद्ध संघ से उन्हें शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है, क्या जांच कार्य चल रहा है ।

श्री बेदव्रत बरूआ : मैं बिना जानकारी प्राप्त किये आप को कुछ नहीं बता सकता । मुझे श्रमिक वर्ग, मजदूर कार्मिक संघों से कतिपय मामलों के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं । हमने कुछ बातों की जांच कराई है लेकिन कोई आक्षेपणीय बात नहीं नजर आई । मुझे और ज्यादा जानकारी नहीं ।

श्री बी० के० दास चौधरी : माननीय मंत्री जी ने बहुराष्ट्रीय निगमों की एक लम्बी सूची दी है । मैं सभी की बात नहीं करता । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार सहकारी क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र का विकास करने के लिये कुछ कृत संकल्प है तो, सरकार की बहुराष्ट्रीय निगमों सम्बन्धी निर्धारित नीति क्या है क्योंकि इन निगमों की गतिविधियों से सहकारी और लघु क्षेत्र की वृद्धि में रुकावट पड़ती है । उदाहरणार्थ देश में माचिस का जितना उत्पादन होता है उसका ८० प्रतिशत विमको द्वारा तैयार किया जाता है । अतः माचिस बनाने वाली छोटी कम्पनियों का उतना विकास नही हो पाता जितना होना चाहिये । क्या मंत्री जी को जानकारी है कि विश्व के अनेक देशों--यहां तक कि इंगलैंड में भी यह विधि लागू की गई है कि बहुराष्ट्रीय निगम ऐसी चीजों का उत्पादन न करें । इसलिये सरकार का इरादा क्या है ? क्या इन निगमों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया जायेगा ?

श्री बेदव्रत बरूआ : सरकार की नीति यह है कि बड़े उद्योगों, विशेषकर बहुराष्ट्रीय निगमों, को सहकारी तथा लघु उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति न दी जाये । प्रत्येक उद्योग के बारे में विवरण देना सम्भव नहीं है । विमको ने एक लाइसेंस के लिये आवेदन किया है लेकिन वह माचिस उद्योग के विस्तार के बारे में नहीं है ।

आन्ध्र प्रदेश में रेलवे लाइनों के लिए नई योजनाएं

***413. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में नई रेलवे लाइनों के लिये सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) उन रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं जो इस समय राज्य में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और उनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान उस राज्य में किन नई लाइनों का निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध पर रामगुंडम से निजामाबाद तक (160 कि०मी० लम्बी) बड़ी लाइन के निर्माण के लिये सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिये गये थे। अब राज्य सरकार ने करीमनगर के रास्ते और काजीपेठ में वर्तमान रेलवे लाइन से मिलने वाली लाइन के वैकल्पिक संरेखण की जांच करने का सुझाव दिया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) 150 किलोमीटर लम्बी बीबीनगर-नडिकुडि लाइन के निर्माण-कार्य की मंजूरी दी जा चुकी है और प्रथम चरण में 74 किलोमीटर लम्बे बीबीनगर-नलगोंडा खण्ड का निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस काम के अप्रैल, 1980 तक पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध होता रहा। गुंटूर से माचेरला तक 130 किलोमीटर लम्बी आमान-परिवर्तन परियोजना को भी स्वीकृत किया जा चुका है किन्तु नडिकुडि-बीबीनगर लाइन पर निर्माण-कार्य की भली-भांति प्रगति होने पर ही इस काम को शुरू किया जायेगा।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नयी रेलवे लाइन को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : विवरण में कहा गया है कि बीबीनगर-नाडिकुदे लाइन पर कार्य अप्रैल, 1980 तक पूरा हो जाने की संभावना है। लेकिन उसके लिये पर्याप्त निधि उपलब्ध होनी चाहिये। लेकिन मंत्रालय जिस तरीके से चला रहा है उससे लगता है कि कार्य इस शताब्दी के अन्त तक भी पूरा नहीं होगा। मेरे विचार से 30 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान था पर इस वर्ष केवल 38 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। लगता है इस का भी विशाख इस्पात संयंत्र जैसा ही हाल होगा। वहां 800 करोड़ रुपये का अनुमान था लेकिन केवल 1 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। क्या मंत्री जी हमें आश्वासन देंगे कि कार्य को 1980 तक पूरा करने के लिये सभी आवश्यकता उपाय किये जायेंगे।

श्री बूटा सिंह : निःसंदेह निधि के उपलब्ध होने पर विवरण में दी गई निर्धारित तिथि तक परियोजना को पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जायेंगे। निधि की उपलब्धता हमारे बस की बात नहीं। यदि हमें पैसा मिल जाये तो हम परियोजना को निर्धारित तिथि तक अवश्य पूरा कर लेंगे।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ननदियाल से कुद्दापा के रास्ते कटपड़ी तक एक अन्य बड़ी लाइन के निर्माण का प्रस्ताव किया है। इसे रायलसीमा क्षेत्र से गुजरना है। यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस वर्ष कम-से-कम सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री बूटा सिंह : राज्य सरकार से एक प्रस्ताव मिला है अर्थात् रामगुंडम से निजामाबाद (160 कि०मी०) तक लाइन बिछानी है । उसके लिये सर्वेक्षण किया जाना सम्भव है ।

औषध उद्योग

*416. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध उद्योग को वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 में कुल कितना लाभ हुआ; और

(ख) वर्ष 1975-76 के दौरान औषधियों का कुल कितना आयात हुआ ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) देश में 2500 से अधिक औषध यूनिटें कार्य कर रही हैं । इनमें से 119 यूनिटें संगठित क्षेत्र में हैं । औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं तथा जैसा कि गत वर्ष में रिकार्ड किया गया 50 लाख रुपये तक की वार्षिक कुल बिक्री वाले औषध उत्पादक एककों को कथित आदेश के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई है । औषध उद्योग द्वारा उपर्जित लाभ के आंकड़े नहीं रखे गये हैं तथा सूचना को एकत्रित करने में लगने वाला समय तथा श्रम प्राप्त होने वाले परिणामों से मेल नहीं खाते ।

(ख) वर्ष 1975-76 के दौरान औषधों के आयात के पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । वर्ष 1974-75 में 45.60 करोड़ रुपये के औषध एवं भेषज का आयात किया गया ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि भारत में औषध उद्योग विशेष कर विदेशी तथा गैर-सरकारी कम्पनियों को भारी मुनाफा हो रहा है और वे कोई हिसाब-किताब भी नहीं रखतीं, और उनके लाभ को नियंत्रित नहीं किया जाता ।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : बहुराष्ट्रीय तथा अन्य कम्पनियों से कुछ जानकारी ली गई है लेकिन पूरी जानकारी के लिये कुछ समय लगेगा । हमारे पास 1973 तक के आंकड़े हैं । वर्ष 1969-73 की अवधि के दौरान विदेशी औषध फर्मों द्वारा भेजी गई कुल राशि का, जिसमें 50% इक्विटी है, वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है (व्यवधान)······

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि इन सभी कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत विचार किया जाये । वे तुलन पत्र बनाती हैं और लाभ दिखाया जाता है । यदि सरकार आंकड़े नहीं रखती तो क्या इन आंकड़ों को कम्पनियों से एकत्र नहीं किया जा सकता । ये आंकड़े बेशक एक वर्ष पुराने हों पर उपलब्ध तो कराये जा सकते हैं ।

श्री सी० पी० माझी : माननीय सदस्य सभी कम्पनियों द्वारा कमाये गये लाभ के बारे में पूछ रहे हैं । हमारे पास उन कम्पनियों के आंकड़े नहीं होते जिनमें विदेशी इक्विटी बहुमत में होता है । वर्ष 1974-75 के लिये उनका कुल उत्पादन 230 करोड़ रुपये का हुआ था और टैक्स देने से पूर्व लाभ 16.6 करोड़ रुपये था और लाभ 7.37 प्रतिशत आंका गया । भारतीय कम्पनियों द्वारा 51.95 करोड़ रुपये का उत्पादन किया गया और लाभ 91.43 लाख रुपये हुआ जो 6.23% बैठता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : वर्ष 1974-75 और 1975-76 में विदेशी कम्पनियों द्वारा कुल कितनी राशि बाहर भेजी गई ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : हमारे पास 1969 के बाद से पिछले वर्ष तक के आंकड़े हैं । लाभांश, तकनीकी जानकारी आदि के लिये बाहर भेजी गई राशि 4.52 करोड़ रुपये से 5.5 करोड़ तक बैठती है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह राशि वार्षिक है या ये कुल आंकड़े हैं ?

श्री पी०सी० सेठी : यह वार्षिक आंकड़े हैं । औसत प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये बैठती है ।

Shri Ramavtar Shastri: I would like to know from the hon-Minister the number of drugs imported and exported by multinational companies in India separately and what is the need for the imports and why they have allowed the imports,

श्री पी०सी० सेठी : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अब आयात-निर्यात की स्थिति में काफी सुधार हुआ है । उदाहरण के लिये 1972-73 में इस संबंधी कुल राशि 30.54 करोड़ रुपये थी ।

श्री रामावतार शास्त्री : बहुराष्ट्रीय निगमों के सम्बन्ध में राशि कितनी है ?

डा० रानेन सेन : निर्यात सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पहले सदस्य महोदय मंत्री जी की बात सुन लें । वह बाद में प्रश्नों के उत्तर देंगे ।

श्री पी०सी० सेठी : हमारे पास कुल आयात-निर्यात के समेकित आंकड़े हैं। यदि कोई निश्चित प्रश्न पूछा जायेगा तो मैं जानकारी दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी विशिष्ट जानकारी के लिये सूचना चाहते हैं । आप एक अलग प्रश्न पूछिए ।

डा० रानेन सेन : यह आयात सम्बन्धी विशिष्ट प्रश्न है ।

श्री पी०सी० सेठी : विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने पर मैं जानकारी देने के लिये तैयार हूं । 1972-73 में आयात 35 करोड़ रुपये और निर्यात केवल 10.33 करोड़ रुपये का हुआ । 1974-75 में जब आयात 45.60 करोड़ रुपये का हुआ तो निर्यात बढ़ कर 43.13 करोड़ रुपये का हो गया । अतः अब अन्तर केवल 2 करोड़ रुपये का रह गया है । जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है 1973 में 15.13 करोड़ रुपये की दवाइयों का आयात हुआ और 9.5 करोड़ रुपये मूल्य की दवाइयां निर्यात की गईं।

डा० रानेन सैन : मैं इसी बारे में जानकारी चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कांडला में फास्फोरिक एसिड संयंत्र की स्थापना

*403. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक फास्फेट उत्पादन एशियाई देश में सहयोग से कांडला में फास्फोरिक ऐसिड संयंत्र की स्थापना करने का हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) और (ख) जी नहीं, तथापि सरकार केन्द्रीय पैसेफिक में एक द्वीप, नौरु के सहयोग से भारत में एक संयुक्त उद्यम फास्फोरिक ऐसिड प्लांट की स्थापना करने की संभावना पर विचार कर रही है और इस संबंध में एक सम्भाव्यता अध्ययन किया जा रहा है । यह प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक स्तर पर है और प्रायोजना स्थल, इसके आकार और सहयोग की शर्तों आदि के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

Production of Coaches and Diesel Engines of New Design

*404. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are manufacturing 2nd class coaches and diesel engines of new designs;

(b) whether orders for them have been received from abroad also ; and

(c) if so, from which countries ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Currently coaches and diesel locos are being manufactured for export to Tanzania.

प्रस्ताविक हावड़ा शिखाला रेलवे लाईन का भविष्य

*410. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा रेल मंत्री ने वर्ष 1975-76 के रेलवे बजट पर अपने वक्तव्य में बताया था पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा आंशिक व्यय के लिए धन देने में जिस पर पूर्व स्वीकृति हो गई थी, अपनी असमर्थता प्रकट किये जाने के बाद प्रस्तावित हावड़ा-शिखाला रेलवे लाईन का क्या भविष्य होगा; और

(ख) क्या ब्राड गेज लाइन बिछाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया जायेगा अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके लिए कार्यवाही किये जाने तथा जमीन अभिगृहीत किये जाने के उपरान्त केन्द्र सरकार उसका व्यय वहन करेगी ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1976–77 का रेलवे बजट पेश करते समय रेल मंत्री संसद को संशोधित वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में बता चुके हैं, जिसके अनुसार, रेल मंत्रालय, भूमि की लागत को छोड़कर, इस परियोजना के खर्च को वहन करेगा। भूमि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

औषधियों के उत्पादन के लिये पांचवीं योजना में लक्ष्य

*411. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में 'बल्क' औषधियों और 'फार्मूलेशनों' के उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और औषध उद्योग में कितनी पूंजी लगाये जाने की आशा है ; और

(ख) इस उद्योग के सार्वजनिक क्षेत्र तथा भारतीय क्षेत्र को प्रमुख भूमिका देने के लिए सरकार की क्या योजना है तथा किन मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जायेगा ;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) प्रपुंज औषधों के लिए पांचवीं योजना लक्ष्य को औषध और भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट के अध्याय–2 के परिशिष्ट-1 में दिया गया है। रिपोर्ट की प्रति 8-5-75 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी। यद्यपि सूत्रयोगों का मदवार आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया गया है तथापि कार्यकारी दल ने 1978–79 तक उनकी आवश्यकता का अनुमान 600 करोड़ रुपये लगाया है। पांचवीं योजना के अन्त तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुल निवेश अनुमान सुत्रयोगों के लिए 100 करोड़ रुपये तथा प्रपुंज औषध उत्पादन के लिए 150 करोड़ रुपया है।

(ख) विस्तार करके अथवा नये औषधों का उत्पादन करने के द्वारा सरकारी क्षेत्र को एक मुख्य कार्य देने का प्रस्ताव है। सरकार ने सिन्थेटिक ड्रग्स प्लांट का विस्तार कार्यक्रम स्वीकृत कर दिया है जिसमें 21.79 करोड़ रुपये का निवेश निहित है इससे 1988 मी टन से 3886 मी टन तक उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। 8.58 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी परिव्यय वाले निकोटिनामाइड संयंत्र की बिहार में स्थापना के बारे में पी आई बी द्वारा स्वीकृति दी गई है। आई डी पी एल ने भी नये सूत्रयोग एकक की स्थापना तथा ऋषिकेश में एन्टीबायोटिक्स संयंत्र के विस्तार के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

इसी प्रकार हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० ने पेनसिलीन, स्टैप्टोमाइसीन, सेमी सिन्थैटिक पेनसिलीन क्षमताओं, अर्थोमाइसीन संयंत्र की स्थापना तथा नये सूत्रयोग यूनिटों के विस्तार के लिए 16.12 करोड़ रुपये के पूंजी लागत के प्रस्ताव पेश किये हैं। आशा है कि जब सरकारी क्षेत्र के यूनिटों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनायें अथवा प्रस्तुत की जाने वाली योजनाओं पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है अथवा स्वीकृति दी जाती है तब औषध उद्योग में सरकारी क्षेत्र मुख्य भूमिका निभाता है।

जहां तक भारतीय क्षेत्र का संबंध है लाइसेंस देने के सम्बन्ध में एक सरल लाइसेंसिंग नीति को लागू किया जा रहा है तथा 1975 के दौरान 40% तक विदेशी साम्यपूंजी वाले फर्मों को 50 आशयपत्र/लाइसेंस जारी किये गये हैं। उद्योग के संबंध में सामान्य मार्गसूचक बातें सरकार द्वारा वर्ष में प्रकाशित उद्योग के लिए "मार्गदर्शन" नामक पुस्तिका में दी गयी हैं। भारतीय क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र आदि के बारे में हाथी समिति अनेक सिफारिशें की हैं तथा इन सिफारिशों पर विचार हो रहा है।

सी०ग्रो०वी० लाइसेंस प्राप्त किये बिना फर्मूलेशनों का निर्माण

*414. **श्री नानूभाई एन० पटेल:** क्या **रसायन श्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही 10 कम्पनियां, जिन्होंने ग्रब तक सी०ग्रो०बी० लाइसेंस प्राप्त नहीं किये हैं, ग्रायातित समूह-ग्रौषधियों पर ग्राधारित ग्रनेक फार्मूलेशनों का उत्पादन कर रही हैं ;

(ख) क्या इसी प्रकार के फार्मूलेशनों के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा ग्रौद्योगिक लाइसेंस की मन्जूरी के लिए दिये गये कोई ग्रावेदन पत्न पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा ग्रस्वीकार कर दिये गये हैं; ग्रौर

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी कि भारतीय कम्पनियों की तुलना में विदेशी कम्पनियां ग्रसीमित ग्रायात ग्रौर क्षमताग्रों का ग्रधिक लाभ न उठाने पायें ?

रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) ग्रौर (ख) : 10 विदेशी कम्पनियों जिनके ग्रौद्योगिक (विकास एवम् विनियमन) ग्रधिनियम के संदर्भ में ग्रंतर मंत्रालीय ग्रध्ययन ग्रुप द्वारा विभिन्न पहलुग्रों की जांच की गई थी, के नाम नीचे दिये गये हैं :—

(1) एग्लो थाई कारपोरेशन

(2) जी डब्ल्यू कार्नरिक क० (एशिया)

(3) चेसबौरा पांडस इन्क (फ्रेंच)

(4) कापर लेबोरेटरीज

(5) इथनार लिमिटेड

(6) सी ई फुलफोर्ड

(7) इण्डियन शेयरिंग लि०

(8) जान बैथ (ब्राम)

(9) निकलसन ग्राफ इण्डिया लि०

(10) मैसर्स रूसल फार्मास्यूटिकल्स लि०

2. इन कम्पनियों में से दो कम्पनियां ग्रर्थात चेस बौरा पांडस इन्क तथा मैसर्स एग्लो थाई कारपोरेशन ग्रौषधों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। ग्रन्य कम्पनियां ग्रायातित प्रपुंज ग्रौषधों के साथ साथ देशी प्रपुंज ग्रौषधों पर ग्राधारित सूत्नयोगों का उत्पादन कर रहे हैं। ग्रन्तरमंत्रालीय ग्रध्ययन ग्रुप की सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों की विभिन्न ग्रवस्था में जांच हो रही है।

इन कम्पनियों द्वारा उत्पादित किये जा सके ग्रनेक ग्रौषध मदों की संख्या 160 से ग्रधिक है जो विभिन्न संघटकों से मिले हैं। गत तीन वर्ष के दौरान ग्रनेक भारतीय कंपनियों द्वारा विभिन्न ग्रौषध सूत्रयोगों का उत्पादन किया जा रहा है। इन दो कम्पनियों के सूत्नयोगों के सह उत्पादों के प्रयोग में न केवल समय लगेगा ग्रपितु ऐसे सूत्नयोगों के सह उत्पादों में यथार्तता लाना भी कठिन होगा।

(ग) समय-समय पर लागू किये गये आयात व्यापार नियंत्रण नीति द्वारा कच्चे माल के आयात का विनियमन किया जाता है।

रेलवे उपकरणों का स्वदेश में बनाया जाना

*415. **श्री धामनकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा अपनी मदसूची में उल्लिखित बड़ी संख्या में उपकरणों को, जिनका पहले आयात किया जाता था; तेजी से देश में बनाये जाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका व्यौरा क्या है ?

(ख) गत तीन वर्षों में रेलवे की कुल खरीद में से इन वस्तुओं का देश में कितनी प्रतिशत उत्पादन होने लगा है तथा कितनी विदेशी मुद्रा की बचत की गई है ; और

(ग) रेलवे विभाग अपने उत्पादन एककों को कब तक पूर्णरूप से आत्म निर्भर बना लेगा ताकि वे आयातित उपकरणों पर निर्भर न रहे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मुहम्मद शफी कुरेशी

(क) आयात किये जाने वाले उपस्कर को तेजी से देश में बनाने के लिए रेलों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) उच्चतम स्तर पर आवधिक बैठकें बुलाकर देश में उत्पादन की प्रगति की नियमित रूप से जांच की जाती है। इसके अलावा प्रत्येक उत्पादन कारखाने तथा रेल मंत्रालय में बने विकास कक्ष आयात के स्थान पर देश में उत्पादन करने के विषय पर सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रहे हैं।

(ii) देशी उपस्कर के विकास के लिए उद्योगपतियों से सम्पर्क बनाये रखने के वास्ते केन्द्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर रेलवे उपस्कर परामर्श समितियां काम कर रही हैं।

(iii) देशी उत्पादन का विकास तेज करने के लिए डायरेक्टोरेट जनरल आफ टेक्नीकल डेवलपमेंट तथा स्माल स्केल सर्विस इन्स्टीट्यूटों जैसी अन्य एजेंसियों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

(iv) आयात की सभी मांगों की सभी स्तरों पर कड़ी जांच-पड़ताल की जाती है और प्रत्येक मद के आयात के लिए अंतिम स्वीकृति महानिदेशक तकनीकी विकास से प्राप्त की जाती है।

(v) जो मदें आयात की जा रही हैं, उनकी समय-समय पर प्रदर्शनी लगायी जाती है। हाल ही में दो डिब्बों में ऐसी मदें सजायी गयी हैं और यह चलती-फिरती प्रदर्शनी इस समय सारे देश में औद्योगिक केन्द्रों पर घूम रही हैं।

(ख) 1974–75 में आयातित भण्डार, रेलवे द्वारा खरीदे गये कुल सामान का 11.96 प्रतिशत था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा खरीदे गये देशी और आयातित सामान का मूल्य नीचे दिया गया है :--

वर्ष	कुल खरीद	आयातित खरीद	देशी खरीद
		(आंकड़े करोड़ रुपयों में)	
1972-73	485.85	59.74	426.11
1973-74 . . .	506.74	60.26	446.48
1974-75	590.90	70.70	520.20

(ग) सरकार उपयुक्त और उपलब्ध देशी उपस्करों का पहले ही रेलों में पूरा इस्तेमाल कर रही है। यद्यपि आयात माल के स्थान पर देशी माल इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में एक ज़ोरदार अभियान निरन्तर चलाया जा रहा है, तथापि ऐसी समय-सीमा बता पाना कठिन है जब शेष महत्वपूर्ण और परिष्कृत मदों का देश में ही विकास हो जायेगा।

भारतीय तेल निगम का अबू धाबी नेशनल आयल कंपनी के साथ अशोधित तेल का आयात करने के लिये करार

*417. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल की सप्लाई हेतु भारतीय तेल निगम और अबू धावी नेशनल आयल के बीच कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या वर्ष 1976 में तेल की सप्लाई के लिए अन्य अनेक देशों के साथ भी प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : **(क) और (ख)** : इंडियन आयल कारपोरेशन और आबू धावी नेशनल आयल कंपनी के मध्य 1976 के दौरान 1 मिलियन मी टन कच्चे तेल की सप्लाई करने के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिन वाणिज्यिक शर्तों पर इंडियन आयल कारपोरेशन विदेशों से अपनी खरीद करती है उन शर्तों का प्रकट न करना एक स्वीकृत परिपाटी है।

(ग) इण्डियन आयल कारपोरेशन और पेट्रोमिन के बीच 1.1 मिलियन मी टन कच्चे तेल का 1976 में साऊदी अरबिया से आयात करने के वास्ते एक संविदा की गई है। कुछ अन्य तेल उत्पादन देशों से 1976 में कच्चे तेल का सप्लाई करने के करार वार्तालाप की विभिन्न अवस्थाओं में है।

पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव

*418. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस परियोजना के लिए केन्द्र से कोई सहायता मांगी गई है और यदि हां, तो कितनी ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के०डी० मालवीय) : (क) हल्दिया में एक पेट्रो केमिकल कम्प्लेक्स (यह आवश्यक नहीं कि सरकारी क्षेत्र में) की स्थापना करने और इस उद्देश्य के लिए वांछित नेफ्था की व्यवस्था करने के वास्ते हल्दिया शोधनशाला का विस्तार करने के लिए समय-समय पर पश्चिम बंगाल सरकार से प्रस्ताव आए हैं।

(ख) दिसम्बर 1972 में किया गया प्रस्ताव में 150,000 मी० टन/प्रत वर्ष ऐथिलीन की क्षमता वाले एक नेफ्था क्रेकर, अनेक डाउनस्ट्रीम यूनिटों की स्थापना करने की परिकल्पना थी। अगस्त 1975 में एक सुझाव दिया गया था कि पहले प्रस्तावित एक प्रमुख पैट्रोकेमिकल्स परियोजना के स्थान पर प्राथमिक रूप से पीवीसी का उत्पादन करने के लिए एक उसी प्रकार के नेफ्था क्रेकर की स्थापना करने का विचार किया जा सकता है।

(ग) अपेक्षित केन्द्रीय सहायता की कोई विशिष्ट मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया था।

गुजरात में उर्वरक संयंत्र

०419. **श्री अरविन्द एम० पटेल**

श्री एन०आर० वेकारिया

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कितने उर्वरक संयंत्र हैं ?

(ख) उनका वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(ग) क्या उनका उत्पादन गुजरात राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) से (ख) : एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10631/76]

तालचर उर्वरक संयंत्र

*420. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचर उर्वरक संयंत्र को चालू करने की मूल लक्ष्य तिथि क्या थी ;

(ख) इस लक्ष्य तिथि को कितनी बार आगे बढ़ाया गया है और अब इसमें उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा ; और

(ग) परियोजना के मूल अनुमान क्या थे और पुनरीक्षत अनुमान क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) जुलाई 1975

(ख) आरम्भिक स्तरों में सीमेंट की कमी तथा क्षेत्रीय तथा आयातित दोनों प्रकार के विभिन्न उपकरणों की डिलीवरी में विलम्ब के कारण सिविल कार्य के निष्पादन में कमी को ध्यान में रखते हुए प्रायोजना के कार्यान्वयन के कार्यक्रम में तीन बार संशोधन करना पड़ा था। अब आशा है कि जुलाई, 1977 में प्रायोजना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर देगी।

(ग) प्रायोजना की अनुमानित लागत अब 161.9 करोड़ रुपये है जबकि मूल अनुमान 70.49 करोड़ रुपये थे।

कटरी पम्प हाउस, धनबाद में बिजली के एक ट्रांसफार्मर की चोरी

2020. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटरी पम्प हाउस, धनबाद से बिजली के ट्रांसफार्मर की चोरी के संबंध में विभागीय जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मूल्यवान वस्तु का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विभागीय जांच समिति ने इस चोरी के लिए किसी रेल कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं पाया।

कटराम की सिविल पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया था और उसने ट्रांसफार्मर के चुराये गए हिस्सों को बरामद करने का प्रयास किया था लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका।

Supply of Apple Alcohol to Madhya Pradesh

2021. Shri G.C. Dixit: Will the Minister of **Chemicals and Fertilisers** be pleased to state whether Government propose to supply apple alcohol to Madhya Pradesh State from surplus States?

The Deputy Minister in the Ministry of Chemicals & Fertilisers (Shri C.P. Majhi):

It is presumed that Hon'ble Member is referring to supply of industrial alcohol to Madhya Pradesh.

It is estimated that Madhya Pradesh will be self-sufficient in industrial alcohol during the current season. No allocation of industrial alcohol has, therefore, been made in favour of Madhya Pradesh from the surplus States.

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में महानगरीय भूमिगत रेलवे

2022. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों में महानगरीय भूमिगत रेलवे के लिए 200 करोड़ रुपये नियत किए गए हैं : और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है तथा इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क): पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख के मसौदे में, महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल की गयी थी। तथापि, 1975-76 तक वार्षिक योजनाओं के माध्यम से पांचवीं योजना अवधि में तदनुरूपी आवंटन केवल 17.68 करोड़ रुपये ही किया गया है।

(ख) कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के नगरों में महानगर परिवहन योजनाओं पर जनवरी 1976 तक कुल लगभग 19.37 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। इसमें चौथी योजना अवधि में किया गया खर्च शामिल है।

कलकत्ता को दमदम-टालीगंज द्रुत परिवहन लाइन के अलावा, किसी अन्य निर्माण कार्य की मंजूरी अभी नहीं दी गयी है। साधनों की वर्तमान कठिनाई के कारण कलकत्ता परियोजना को पूरा करने की 1979 की मूल लक्ष्य-तिथि की समीक्षा की जा रही है।

कानपुर और लखनऊ स्टेशनों के बीच यात्रियों के सामान की चोरी

2023. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कानपुर और लखनऊ स्टेशनों के बीच यात्रियों के सामान की चोरी के अनेक मामले हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी 1976 के प्रथम सप्ताह के दौरान 84 डाउन दिल्ली-लखनऊ गाड़ी में ऐसे कितने मामले हुए तथा कितने अवसरों पर अपराधियों को पकड़ा जा सका ; और

(ग) स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जनवरी, 1976 के पहले सप्ताह में कानपुर-लखनऊ, खण्ड पर 84 डाउन गाड़ी में यात्रियों के सामान की चोरी की केवल एक घटना हुई।

(ग) ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं :--

1. रात में चलने वाली सवारी डाकगाड़ियों में सशस्त्र सरकारी रेलवे पुलिस के दलों को अनुरक्षी के रूप में चलाया जाता है।

2. अपराधियों पर निगाह रखने और आसूचना इकट्ठी करने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।

3. सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान के समय सरकारी रेलवे पुलिस के व्यक्तियों द्वारा गश्त लगायी जाती है।

Late Running of Sabarmati Express

2024. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) Whether Sabarmati Express arrives quite late at the stations and junctions like Baroda, Ratlam, Nagda, Ujjain, Bhopal and Itarsi;

(b) Whether Government have received complaints in this regard from passenger agencies and passengers;

(c) Whether the passengers travelling by this train often miss other connecting trains as a result of which they experience lot of inconvenience; and

(d) if so, the action being taken by Government for improving the position in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) 165/166 Sabarmati Express ran late on a few days.

(b) No.

(c) No. except on one occasion when 165 DN Ahmedabad-Faizabad/Varanasi missed connections with 22 Up Dakshin Express at Bhopal.

(d) Running of these trains is being closely watched to ensure punctual running.

मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड का निदेशक बोर्ड

2025. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास के निदेशक बोर्ड के पुर्नगठन का कोई प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : कम्पनी के संघ के नियमावली में निहित व्यवस्थाओं के अनुसार उनका निदेशक मंडल तीन वर्षों में एक बार गठित किया जाता है। तदनुसार बोर्ड 13 दिसम्बर, 1975 में पुनः गठित किया गया था। बोर्ड में 8 सदस्य हैं जिसमें से चार सदस्य जिनका कम्पनी में मूल साम्य पूंजी का 51% भाग है भारत सरकार द्वारा मनोनीत हैं। शेष चार जिनमें से प्रत्येक की मूल साम्य पूंजी 24½% है में से दो सदस्य एमोको इंडिया इंक, यू एस ए और दो सदस्य नेशनल इरानियम आयल कम्पनी द्वारा मनोनीत हैं। भारत सरकार ने बोर्ड में पहले ही तीन व्यक्तियों को मनोनीत किया है। चौथे व्यक्ति का मनोनयन शीघ्र किए जाने की संभावना है।

मध्य प्रदेश में रेल लाइनों के लिए काम चलाऊ सर्वेक्षण

2027. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विद्यमान रेल व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से गत तीन वर्षों में विभिन्न रेलवे लाइनों के लिए कितने काम चलाऊ इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किये गये ; और

(ख) जिन लाइनों का सर्वेक्षण किया गया उनकी आय (डिस्काउन्टेड कैशफ्लो रिटर्न) कितनी है और इस बारे में क्या निर्णय किये गये ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित सर्वेक्षण किये गये जिनका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	सर्वेक्षण का नाम	डी०सी०एफ० द्वारा प्रतिफल	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	ढल्ली राजहरा से जगदलपुर तक एक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण ।	7.84% (भाप कर्षण से) 7.97% (डीजल कर्षण से)	रिपोर्टों की जांच की जा रही है ।
2.	रीवा होकर सतना से ब्योहारी तक नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिए यातायात सर्वेक्षण ।	2.3%	अपर्याप्त यातायात-औचित्य को देखते हुए परियोजना को स्थगित कर दिया गया है ।
3.	रायापुर-धमतरी छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए टोह इंजीनियरी सर्वेक्षण ।	9.84%	रिपोर्टों की जांच की जा रही है ।
4.	सतपुड़ा छोटी लाइन रेल प्रणाली के उत्तरी खंड के आमान-परिवर्तन के लिए यातायात सर्वेक्षण ।	0.5%	सतपुड़ा क्षेत्र की सम्पूर्ण छोटी लाइन प्रणाली को बड़ी लाइन में बदलने के लिए पहले किये गये सर्वेक्षणों से पता चला है कि यातायात तथा वित्तीय दृष्टि से इस परियोजना का औचित्य नहीं होगा । अब, 1976–77 में, केवल जबलपुर-गोंडिया खंड के आमान-परिवर्तन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ।

भारतीय औषध फर्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया जाना

2028. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से कम विदेशी इक्विटी शेयर वाली कितनी फर्मों को समेकित क्षमता के सी० ओ० बी० लाइसेंस दिए गए हैं तथा कितनी फर्मों को उनकी अलग-अलग क्षमता के सी० ओ० बी० लाइसेंस दिए गए ; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी में ऐसी फर्मों के क्या नाम हैं तथा उनको इस समय दिए गए सी० ओ० बी० लाइसेंस की क्षमताओं का क्या ब्यौरा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) और (ख) : 26 प्रतिशत से कम विदेशी साम्य पूंजी वाले भारतीय कम्पनियों के सम्बन्ध में नाम तथा क्षमता के ब्यौरे जिन्हें एकत्रित क्षमता सहित सी०ओ०बी० लाइसेंस दिये गये हैं, युक्त विवरण पत्र I तथा 26% से कम विदेशी साम्य पूंजी वाले भारतीय कम्पनियों के नाम, जिन्हें अलग अलग क्षमता सहित सी०ओ०बी० लाइसेंस दिये गये हैं, युक्त विवरण पत्र II संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी–10632/76]

अलग अलग क्षमताओं के साथ 26% से कम विदेशी साम्य पूंजी वाले भारतीय कम्पनियों को दिये गये सी०ओ०बी० लाइसेंस में क्षमताओं के सम्बन्ध में ब्यौरे औषध और भेषज उद्योग समिति पर रिपोर्ट के अध्याय V के परिशिष्ट III में बताये गये हैं [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी–10632/76] रिपोर्ट की एक प्रति 8.5.75 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी ।

Shortage of Teachers in Schools in Ratlam Division (Western Railway)

2029. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of teachers by which each school functioning in Ratlam Division is short and the arrangements made to meet the shortage;

(b) whether several schools have been short of teachers of compulsory subjects and this shortage is not being met for a long time; and

(c) whether the school in Ratlam proper itself is short of teachers in each subject and if so, the time by which teachers are likely to be recruited there to make up the shortage?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) to (c) There is a shortage of two teachers in the school at Ratlam, 'Ad hoc' arrangements have been made to fill up these two vacancies pending the availability of candidates selected by the Railway Service Commission. A duly selected candidate is expected to take over one of the posts very shortly. The Service Commission have not yet completed their selection for the other post.

There is no shortage in any schools of teachers of compulsory subjects.

The Western Railway Administration have assessed that 12 additional teaching posts would be required for Ratlam Division due to increase in the number of students and changes in the education pattern. This is being processed.

अदरा डिवीजन के निकाले गए रेल कर्मचारियों की पुर्नविलोकन याचिकाएं

2030. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदरा डिवीजन के उस अमले सहित सभी निकाले गये कर्मचारियों ने, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय नहीं गया था, पुर्नविलोकन याचिकाएं प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सेवा से बर्खास्त किये गये 463 स्थायी कर्मचारियों में से, 383 को सेवा में वापस लिया गया है और समीक्षा के 80 मामले रद्द कर दिये गये हैं। सेवा से निकाले गये 468 अस्थायी कर्मचारियों में से 467 को सेवा में बहाल किया गया है और समीक्षा का एक मामला रद्द कर दिया गया गया है।

व्यय में कटौती करने के लिए ज्ञापन

2031. **श्री समर गुहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन ने पिछली रेल हड़ताल से पूर्व अथवा उसके दौरान रेलवे अधिकारियों को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें व्यय में कटौती करने तथा रेलवे की आय बढ़ाने के बारे में सुझाव दिये गये थे ;

(ख) क्या सरकार ने ज्ञापन में दिए गए सुझावों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हड़ताल के दौरान अथवा उसके तत्काल बाद रेलों का खर्च कम करने या आमदनी बढ़ाने के बारे में कोई ठोस सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों से बकाया राशि की वसूली

2032. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुत से सरकारी उपक्रमों की ओर इस्पात, कोयले तथा अन्य वस्तुओं की ढुलाई के लिये रेलवे को देय भारी रशियों को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या उन उपक्रमों की ओर से चरणबद्ध वसूली की अनुमति देने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां तो उन पर क्या निर्णय किये गये ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से कहा गया है कि वे रेलवे की सभी देय राशि का शीघ्रता से भुगतान करें तथा रेलवे की बकाया राशि के भुगतान की अनिवार्यता के बारे में दबाव डालने हेतु विभिन्न स्तरों पर बैठकें की गयी हैं। नियंत्रक मंत्रालयों के साथ मंत्री स्तर पर भी बैठकें हुई हैं।

क्षेत्रीय रेलों को ये हिदायतें भी दी गयी हैं कि वे सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को बुक किये गये माल के लिये आवश्यक भाड़े की पहले ही अदायगी कर दें, जो मामले को उच्च स्तर पर उठाये जाने के बावजूद रलवे की बकाया राशि का भुगतान नहीं करते।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम में तेल की खोज

2033. **श्री नूरुल हुडा** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के विभिन्न भागों में किन-किन स्थानों में तेल की संभावना पाई गई है ;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कछार जिले तथा आसाम के अन्य स्थानों पर तेल के लिये खुदाई का कार्य आरम्भ किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य की वर्तमान प्रगति क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) ओ० एम० जी० सी० द्वारा असम में रूद्रासागर लकवा, गैलेकी, बोरहोला, आमगुड़ी और चैरालो पर तेल पाया गया है।

1950 से 1960 के बीच पता लगाये गये नाहरकटियां और मोरान तेल क्षेत्रों के अतिरिक्त आयल इंडिया लि० (ओ०आई०एल०) ने आसम में (कम मात्रा में) जयपुर, सांती, लंगकासी, कथलगुडी कुसीजान, जोराजान, ताराजान, नागाजान, जालोनी, मबुटिंग-ट्रिप्लिंग, तिनाली और तगाखाट में तेल की खोज की है।

(ख) और (ग) : जहां ओ०एम०जी०सी द्वारा कचार जिले में 1976-77 के दौरान खुदाई की योजना है वहां रूद्रामागर, लकवा, गैलेकी, बोरहोला, और आमगुडी आमगुडी जोरहाट में खुदाई जारी है। रुद्रासागर लकवा और गैलेकी क्षेत्रों से इस समय प्रतिवर्ष लगभग 1.1 मिलियन मी टन कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है।

सोनीपत/पानीपत से दिल्ली तक दोहरी रेलवे लाइन बिछाना

2034. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री सोनीपत/पानीपत से दिल्ली तक दोहरी रेलवे लाइन बिछाने के बारे में 26 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 973 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जी मंडी और गनौर के बीच 56.35 किलोमीटर दोहरी रेलवे लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) इस काम को पहले ही बजट में शामिल कर लिया गया है और इस निर्माण-कार्य से सम्बन्धित अनुमान को स्वीकृत किया जा रहा है। इस काम के पूरा होने में लगभग तीन वर्ष लग जाने की संभावना है बशर्ते की इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होती रही।

कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना

2035. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन कर्मचारियों की पदोन्नति को रेलवे हड़ताल के दौरान रोक दिया गया था वे ग्रभी भी पदोन्नति के पात्र नहीं हैं ; ग्रौर

(ख) यदि हां तो क्या सरकार इस तथ्य को देखते हुए कि लगभग सभी कर्मचारियों को माफी देकर सेवा में वापस ले लिया गया है, पदोन्नति पर लगे प्रतिबंध को हटाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) ग्रौर (ख) हड़ताल में भाग लेने पर पदोन्नति रोकने के बारे में कोई हिदायत जारी नहीं की गयी थी। तथापि, सामान्य नीति के ग्रनुसार, यदि किसी कर्मचारी को ग्रनुशासन ग्रौर ग्रपील नियमों के ग्रधीन कोई दण्ड दिया गया हो तो दण्ड की ग्रवधि में कर्मचारी पदोन्नति पाने का पात्र नहीं होता।

बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाएं

2036. **श्री एस० ग्रार० दामाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर कितनी दुर्घटनाएं हुई; ग्रौर

(ख) उनको चौकीदार वाले फाटकों में परिवर्तित करने संबंधी क्रमिक कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ग्रौर दुर्घटनाएं रोकने के लिये क्या सुरक्षात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1-4-1973 से 29-2-1976 तक की ग्रवधि के दौरान भारत की सरकारी रेलों पर चौकीदार-रहित समपारों पर गाड़ियों के सड़क यातायात से टकरा जाने की 259 घटनाएं हुई।

(ख) समपारों पर चौकीदार तैनात करने की ग्रावश्यकता के बारे में समीक्षा करने के लिए, रेलें समपारों पर से होकर गुजरने वाले यातायात की ग्रावधिक गणना करती हैं, लेकिन इस काम में प्राथमिकता उन समपारों को दी जाती है जहां दुर्घटनाएं होने की ग्रधिक संभावना हो। राज्य सरकार के साथ परामर्श करके प्रस्तावों को ग्रंतिम रूप दिया जाता है ग्रौर उन्हें योजना बद्ध ग्राधार पर शुरू किया जाता है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। 1972-73 से 1974-75 के दौरान विभिन्न राज्यों में बिना चौकीदार वाले 169 समपारों पर चौकीदार तैनात किये गये थे।

बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं कम करने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं, जैसे सड़क उपयोगकर्त्ताग्रों को चेतावनी देने के लिए कि ग्रागे समपार है, 'स्टाप बोर्ड' लगाना; गाड़ी के ड्राइवरों को सीटी बजाने का ग्रादेश देने के लिए 'व्हिसल बोर्ड' लगाना, समपारों पर चौकीदार तैनात करने की ग्रावश्यकता का पता लगाने के लिए यातायात की ग्रावधिक गणना; इश्तहार, सिनेमा-स्लाइड, लाउड-स्पीकरों पर घोषणा, रेडियो वार्ता ड्राइवरों ग्रौर परिवहन संघों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके सड़क उपयोगकर्त्ताग्रों के बीच शिक्षात्मक ग्रभियान चलाना; समपारों पर ग्राकस्मिक जांच करना ग्रादि। ग्रधिकांश राज्य सरकारों ने मोटर वाहन नियमों के ग्रन्तर्गत कानून बनाकर मोटर वाहनों के ड्राइवरों के लिए यह जरूरी कर दिया है कि बिना चौकीदार वाले समपारों से पीछे ही रुक जायें ग्रौर रेलवे लाइन को केवल तभी पार करें जब उनके मोटर वाहन के ग्रागे-ग्रागे संवाहक चल रहा हो । यह सुनिश्चित

करने के लिए कि उड़क उपयोगकर्त्ताओं द्वारा मोरट वाहन नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके जांच भी की जाती है। सब राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को भी हिदायतें दी गयी हैं कि मोटर वाहन नियमों की धाराओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

झारिया स्टेशन यार्ड पर कोयले की राख के ढेर के नीचे महिलाओं का जिन्दा दब जाना

2037. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में धनबाद के निकट झारिया रेलवे स्टेशन यार्ड पर 18 मार्च, 1976 को कोयले की राख के ढेर के नीचे दो महिलायें किन परिस्थितियों में दब कर मर गई थीं;

(ख) दुर्घटना के लिये किन व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है और महिलाओं के नजदीकी रिश्तेदारों को क्या क्षतिपूर्ति दी गई है; और

(ग) रेल प्रधिकारियों का भविष्य में रेलवे यार्डों में उक्त प्रकार को दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) : यह दुर्घटना झारिया में फतेहपुर की पुरानी बन्द साइडिंग के निकट हुई जो कि बी०सी० सी०एल० कोयला खान की कोयला लादने और उतारने के लिए लीज पर दी गयी थी। तीन व्यक्ति (दो महिलाएं और एक पुरुष) कोयले के ढेर से अनाधिकृत रूप से कोयला उठा रहे थे, उसी समय कोयले का ढेर ज़मीन में धंस गया जिसके अचानक ढह जाने से दो महिलाएं नीचे दब गयी और एक पुरुष को चोटें आयीं।

(ख) इस मामले में रेलवे किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं है। इस मामले की छानबीन राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेल यातायात (दक्षिण रेलवे) में वृद्धि करने के विचार से किरायों की रियायती दरें

2038. **श्री हरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे ने रेल यातायात में वृद्धि करने के विचार से हाल ही में कोई रियायतें दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन रियायतों का रेल यातायात पर क्या प्रभाव पड़ा है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दक्षिण रेलवे द्वारा हाल ही में कोई रियायती किराये शुरू नहीं किये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन से मदुरै तक नई रेलवे लाइन बनाने की मांग

2039. **श्री बरके जार्ज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इड्डिकी को कोचीन के साथ मिलाने वाली कोचीन से मदुरै तक एक नई रेलवे लाइन बनाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में केपरोलेक्टम का नियतन

2040. **श्री बसंत साठे** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य में सूत्र (ट्वाइन) के निर्माता को "सिंथेटिक मोनोफिलामेंट" के लिए नायलोन सूत्र (ट्वाइन) और "हाई डेंसिटी पोलीथिलीन" हेतु पर्याप्त मात्रा में केपरोलेक्टम का नियतन करने और साथ ही राज्य की कुल आवश्यकता के कम से कम 25 प्रतिशत भाग का आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्र अन्सारी) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने नायलोन टिवाइन के लिए केप्रोलेक्टम के आबंटन तथा सिन्थेटिक मोनोफिलामेंट के लिए एच डी पी या राज्य की कुल आवश्यकता के कम से कम 25 प्रतिशत तक के आयात के लिए हाल ही में कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक एककों के लागत ढांचे संबंधी समिति का प्रतिवेदन

2041. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पूंजी पर समुचित लाभ सुनिश्चित करने हेतु उर्वरक एककों के लागत ढांचे की जांच करने के लिए नियुक्त समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डनलप, सिएट, फायरस्टोन और गुडईयर कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ

2042. **श्री वयालार रवि** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डनलप, सिएट, फायरस्टोन और गुडईयर कम्पनियों ने कुल कितने मूल्य की बिक्री की तथा उन्होंने कितना लाभ अर्जित किया तथा विदेशियों ने इन कम्पनियों में कितने शेयर खरीदे हुए हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी ने इस अवधि के दौरान अपने शेयर धारियों को कुल कितना लाभांश दिया; और

(ग) प्रत्येक कम्पनी को इस अवधि के दौरान विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भारत से बाहर कुल कितना धन भेजने की अनुमति दी गई ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) 1972-73 से 1974-75 तक के तीन वर्षों के मध्य, डनलप इंडिया लि०, सीट टायर्स आफ इंडिया लि० फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, तथा गुडईयर इण्डिया लि० के व्यापारावर्त्त, लाभ (करों से पहले) उनमें विदेशियों/अन्यत्र वासियों द्वारा धारित हिस्सों, तथा उनमें प्रत्येक द्वारा हिस्सेधारियों को दी गई कुल लाभांशों की राशि से संबधित सूचना संलग्न विवरण पत्र I में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०-10633/76]

(ग) इन चारों कम्पनियों द्वारा, 1971-72 से 1973-74 तक के तीन वर्षों के मध्य, विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा यथा सूचित, बाहर भेजी गई राशि की बाबत आंकड़ें संलग्न विवरण-पत्र 2 में दिये गये हैं।

रांची-हावड़ा एक्सप्रेस

2043. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रांची-हावड़ा एक्सप्रेस के मार्ग को बदलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के गैस एजेंट

2044. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी के दिल्ली नई दिल्ली स्थित उन गैस एजेंटों के नाम और पते क्या हैं जिन की सूची में कुकिंग गैस के लिए 1000 से अधिक उपभोक्ताओं के नाम हैं ;

(ख) क्या उन में से कुछ एजेंटों ने उपभोक्ताओं को गैस-सिलेण्डरों की सप्लाई के लिए अपने सब एजेंट नियुक्त कर रखे हैं; और

(ग) क्या ये एजेंट खाली गैस सिलेंडरों के स्थान पर भरा हुआ सिलेन्डर देने में लगभग 10-15 दिन लगा देते हैं; और यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क), (ख) मैसर्स कोसंगैस कंपनी दिल्ली में ईंधन गैस के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के प्रमुख वितरक हैं। उन्होंने दिल्ली में मैसर्स दिल्ली गैस कंपनी को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। मैसर्स दिल्ली गैस कंपनी ने संलग्न विवरण पत्र में दिए गए क्रम सं० 2 से 16 तक उपवितरकों के रूप में नियुक्त किया है [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०-10634/76]

(ग) उपभोक्ताओं को कभी कभी अत्यधिक कमी और यातायात के प्रबन्ध में अप्रत्याशित गड़बड़ी होने के अवसरों को छोड़कर गैस की सप्लाई तत्काल की जाती है।

आसाम उच्च न्यायालय के त्रिपुरा न्यायपीठ में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं

2045. **श्री बीरेन दत्त:** : क्या **विधि न्याय और** कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान आसाम उच्च न्यायालय के त्रिपुरा न्यायपीठ में कितनी बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं स्वीकार की गई हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जायगी।

दीवा-बसेन रेल लाइन पर कार्य

2046. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीवा-बसेन रेल लाइन पर चल रह निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह लाइन कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस नयी लाइन के कार्य को कुल मिलाकर प्रगति 22 प्रतिशत हुई है।

(ख) इस लाइन को पूरा करने की निर्धारित तिथि मार्च 1980 है।

गोरखपुर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायपीठ की स्थापना

2047. **श्री नरसिंह नारायण पाण्डे** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुकदमा लड़ने वाले गरीब लोगों के लिए गोरखपुर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायपीठ की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : जी नहीं।

आन्ध्र प्रदेश में बिना चौकीदार वाले लेविल क्रासिंग

2048. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में बिना चौकीदार वाले कितने लेविल क्रासिंग हैं; और

(ख) 1974 और 1975 के दौरान इन क्रासिंगों पर कितनी दुर्घटनायें हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश में 31-3-75 को 1,833 'सी' श्रेणी के समपार थे।

(ख) नौ।

Incidents of Theft and Robbery on Trains

2049. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the zone-wise number of persons killed and injured in the incidents of theft and robbery in trains during the last six months and the value of goods and cash thus looted ; and

(b) the effective measures being taken by his Ministry for the safety of the passengers?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Number of persons killed and injured and value of goods and cash looted in cases of thefts and robbery in trains during the last six months (i.e. 1-9-75 to 29-2-76) zone-wise are given below:

Railway Zones	Number of persons		Value of goods and cash looted (in rupees)
	Killed	Injured	
Central		..	7,912
Western		..	1,472
Northern	..	2	13,39,432
North-Eastern	1	8	2,31,514
Southern		..	1,44,183
Eastern		2	5,84,193
South-Eastern			6,630
South-Central			4,02,372
Northeast-Frontier	..	..	1,09,446
	1	12	28,27,154

(b) 1. Protection of passengers and their personal property is the sole responsibility of the State Government/Government Railway Police. They are taking the following steps in this regard:—

(i) Armed police guards are provided in trains for the safety of passengers.

(ii) Plain clothed Government Railway Police staff are detailed on affected sections.

(iii) Frequent surprise checks are made by Government Railway Police supervisory staff.

(iv) In some States, Government Railway Police Mobile Outposts have been provided on important trains for quick registration and investigation of cases.

2. (i) Railways have provided armed R.P.F. personnel on selected long distance trains to supplement the Police escorts.

(ii) Assistance of Railway Protection Force is given to Government Railway Police for escorting duties, when needed.

(iii) Safety devices in coaches are strengthened, where required.

(iv) Coordination meetings are held by Railway Protection Force with the State Police and Government Railway Police and prevention, detection and investigation of such cases are pursued.

(v) The Minister for Railways is keeping constant touch with Chief Ministers of the affected States and has been urging them to take vigorous preventive and detective measures to ensure safety of passengers and their property while they are travelling in railway trains.

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अंतर्गत कोकाकोला निर्यात निगम तथा पामोलिव के विरुद्ध मामले

2050. **श्री प्रिय रंजनदास मुंशी:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोकाकोला निर्यात निगम और पामोलिव के विरुद्ध एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों से उच्च न्यायालय में मामले विचाराधीन पड़े हैं और सरकार द्वारा निर्देश के विरुद्ध उन्होंने निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : हां, श्रीमान् जी। मैं० कोकाकोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन तथा मैं० कालगेट पामोलिव इण्डिया लिमिटेड के मामलों में, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 31(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे दिये गये क्रमशः दिनांक 28-7-73 तथा 28-3-74 के निर्देशों की बाबत, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष कार्यवाहियां, संबंधित कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित याचिकाओं में, क्रमशः दिनांक 28-9-73 तथा 24-6-74 के दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित 'रोकादेशों' के कारण अनिर्णीत हैं।

औषधियों का आयात

2051. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 की तुलना में वर्ष 1975 में औषधियों के आयात में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आंकड़ें क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान औषध एवं भेषज का आयात 45.60 करोड़ रुपये का था जब कि वर्ष 1965-66 के दौरान 13.90 करोड़ रुपये का था।

मैसर्स बर्ड एंड कंपनी कलकत्ता

2052 **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में कथित कुप्रबन्ध और अनिर्यमित कार्यों के संबंध में जारी किये गये "कारण बताओ" नोटिस का मैसर्स बर्ड एण्ड कंपनी कलकत्ता के प्रबन्धकों ने कोई संतोषजनक उत्तर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में आगे कार्यवाही करने का है अथवा उसे यहीं समाप्त कर देने का है; और

(ग) क्या बर्ड एण्ड कम्पनी के बोर्ड में कुछ सरकारी निदेशक नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) से (ग) बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को, दिनांक 24 जनवरी, 1976 को प्रेषित यह कारण बताने का आह्वान करते हुये कि इस कम्पनी में, कम्पनी अधिनियम, की धारा 408 (1) द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड को सौंपी गई शक्तियों के अनुसरण में निदेशक, क्यों नहीं नियुक्त करने चाहिए, 'कारण बताओ' नोटिस के प्रत्युत्तर में कम्पनी ने अपना उत्तर, कम्पनी विधि बोर्ड को भेज दिया। संबंधित पक्षों को, कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष वैयक्तिक सुनवाई के लिये बुलाया गया है एवं पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् कम्पनी विधि बोर्ड मामले का निर्णय करेगा।

हुबली बंगलौर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2053. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुबली और बंगलौर के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी सर्वेक्षण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इसे बड़ी लाइन में बदलने का कार्य प्रारंभ करने के लिए उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मिरज-हुबली-होसपेट मीटर लाइन खण्ड के आमान-परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और उसकी रिपोर्ट की जांच की जा रही है। गुन्तकल्लू से बेंगलुरू तक लाइन का आमान-परिवर्तन पहले से ही किया जा रहा है। अरसीकेरे के रास्ते हुबली से बेंगलूरु तक की मीटर लाइन के आमान-परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस लाइन के आमान-परिवर्तन के लिए राज्य सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए, फिलहाल इस आमन-परिवर्तन के संबंध में विचार करना संभव नहीं होगा।

कर्नाटक राज्य में रेलवे फाटक

2054. **श्री के० लकप्पा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 3702

(क) कर्नाटक राज्य में ऐसे कितने फाटक हैं जिन पर चौकीदार नहीं हैं;

(ख) वर्ष 1975 के दौरान इन फाटकों पर कितनी दुर्घटनायें हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे बिना चौकीदार वाले फाटकों की संख्या कम करने का है; और

(घ) यदि हां, इस उद्देश्य हेतु वर्ष 1976-77 में कितनी धनराशि मंजूर की गई है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कर्नाटक राज्य में 'सी' श्रेणी के, बिना चौकीदार वाले 1,116 समपार हैं।

(ख) एक।

(ग) बिना चौकीदार वाले ऐसे समपारों को जहां सड़क और रेल यातायात भारी मात्रा में होता है या जहां से आगे देखने में रुकावट पड़ती है और जहां दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है, योजनाबद्ध आधार पर की गयी यातायात की आवधिक गणना को ध्यान में रखते हुए चौकीदार वाले समपारों में बदलने के लिए कार्रवाई की जाती है।

(घ) इस प्रयोजन के लिए कम से कम 6.2 हजार रुपये (लगभग) की रकम निर्धारित की गयी है।

दिल्ली अहमदाबाद लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलना

2055 श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-अहमदाबाद मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है और दिल्ली रिवाड़ी लाइन को ब्राड गेज लाइन में कब तक बदला जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली-रेवाड़ी-अहमदाबाद मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण किये गये हैं और सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्टों से पता चला है कि 925 कि०मी० लम्बी इस लाइन पर 108 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस आमान-परिवर्तन के संबंध में निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच पूरी हो जाने और पर्याप्त धन उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

उर्वरकों के लिए मूल्य नीति समिति

2056. **श्री एम० कतामुतु :**

श्री भान सिंह भौरा :

श्री राजदेव सिंह :

श्री रामसहाय पांडे :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के लिए मूल्य नीति बनाने हेतु कोई समिति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) समिति का प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) से (ग) 8 जनवरी, 1976 को सरकार ने उर्वरक मूल्य समिति नामक एक समिति की जो वर्तमान आधार पर उर्वरकों के मूल्य के अध्ययन करने तथा सतत् आधार पर के निवेशों पर उचित वसूली को सुनिश्चित करने के लिए मूल्य नीति की सिफारिश करने के लिए स्थापना की गई है। समिति को अपने स्थापित होने की तिथि से 6 महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

उर्वरकों का आयात

2057. **श्री शंकर राव सावन्त :**

श्री वयालार रवि :

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 में उर्वरकों का कितना स्वदेशी उत्पादन हुआ और किन किन देशों से कितनी कितनी मात्रा का आयात किया गया ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10635/76]**

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के लिए स्वीकृत राशि

2058. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) इन परियोजनाओं पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है;

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के लिये नियुक्त राशि का क्या अनुपात है; और

(घ) क्या पिछड़े क्षेत्रों के लिए धन के आबंटन में वृद्धि की जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके और नगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण-क्षेत्रों के बीच असंतुलन दूर किया जा सके ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) पिछड़े क्षेत्रों में नयी लाइनों के निर्माण के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है। तथापि, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी लाइनों के निर्माण के लिए, जिसमें पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए रेलवे लाइनें शामिल हैं, 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसमें से अब तक लगभग 34 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। यातायात की जरूरतों और देश के समग्र विकास की आवश्यकताओं के आधार पर नयी लाइनों के निर्माण की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रयत्न किये जाते हैं।

Setting up of new flag stations in Ratlam Division

2059. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of cases under consideration of Government for setting up new flag stations in Ratlam railway division indicating the names of such stations; and

(b) the number of such cases as are expected to be decided in the near future?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Nil.

(b) Does not arise.

धनबाद में एक नया रेलवे उच्चतर माध्यमिक स्कूल

2060. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद (पूर्व रेलवे) में एक रेलवे उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने का एक प्रस्ताव था और उसके लिये निधि भी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव अभी तक क्रियान्वित क्यों नहीं हो पाया है; और

(ग) क्या रेलवे प्रशासन का विचार कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिये अब धनबाद स्थित डिवीजनल मुख्यालय में एक द्विभाषीय (हिन्दी तथा बंगाली माध्यम) उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, 1964-65 में।

(ख) बाद में यह पता चला कि धनबाद में एक हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने के संबंध में पर्याप्त औचित्य नहीं है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल रेल प्रशासन के विचाराधीन नहीं है।

धनबाद स्थित रेलवे अस्पताल का दर्जा बढ़ाया जाना

2061. **श्री चंद्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद रेलवे अस्पताल का दर्जा बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ और विकलांग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, ई०एल०टी० तथा पूर्णकालिक दंत चिकित्सिक की व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या धनबाद रेलवे अस्पताल को प्लास्टर आफ पेरिस सहित औषधियों तथा अन्य उपकरणों की सप्लाई वहां की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) अंतरंग रोगियों तथा बहिरंग रोगियों को अलग-अलग प्रति व्यक्ति, प्रति दिन कितने मूल्य की औषधियां दी जाती हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक चिकित्सा अधीक्षक की व्यवस्था की गयी है। स्त्री रोग चिकित्सक और दन्त चिकित्सक आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। अन्य विशिष्ट रोगों की चिकित्सा के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) ऐसी लागत का हिसाब नहीं लगाया गया है।

Railway Lines Under Construction in Madhya Pradesh

2062. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of the railway lines under construction in Madhya Pradesh;

(b) the amount sanctioned for each railway line; and

(c) the prescribed time for the completion of each line?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) (b) & (c) The following rail links are under construction/approved for construction in the State of Madhya Pradesh.

Name of the line	Anticipated cost (Rs. in crores).	Amount allotted (Rs. in crores) in 1976-77	Target date of completion
1. Guna-Maksi new BG line.	10.51	0.25	April, 1976
2. Hirdagarh-Damua new BG line.	2.25 (Approved work not yet sanctioned).	1.00	Not yet fixed

Quarters for Class IV Sanitary Employees (Central Railway)

2063. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Class IV sanitary employees working in the Central Railway ; and

(b) the number out of them provided with railway staff quarters?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) 4997,

(b) 1941

Inadequate Supply of Wagons in Khandwa in Madhya Pradesh

2064. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Chambers of Commerce in East Nimad in Madhya Pradesh have represented to his Ministry about inadequate supply of railway wagons in Khandwa ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

Amount allocated to Madhya Pradesh from Railway Safety Works Fund

2065. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the amount allocated from the Railway Safety Works Fund to Madhya Pradesh State during the financial year ending 31st March, 1976 ;

(b) the amount of fund which remained unutilised in Madhya Pradesh during the current financial year ; and

(c) whether the amount so allocated from the fund to Madhya Pradesh during the last three years has lapsed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Rs. 17 lakhs (Approx.).

(b) Rs. 175 lakhs (Approx.).

(c) No.

बदरपुर-लुमडिंग हिल सैक्शन (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) का रखरखाव

2066. **श्री नूरुल हुडा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के बदरपुर-लुमडिंग हिल सैक्शन में भूस्खलन दूर करने या रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या इस सेक्शन में सुरंगों और मार्गों का उचित रखरखाव किया गया है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) बदरपुर-लुमडिंग पहाड़ी खण्ड पर भूस्खलन समाप्त करने/रोकने के लिए किये गये उपाय इस प्रकार हैं--रेल की पटरी के साथ पहाड़ी ढलानों के कमजोर स्थलों पर लंगीचा क्रेट बनाना, खाली पत्थरों की चिनाई वाली दीवारें बनाना, वर्तमान सुरंगों के मुहानों का नियमित अनुरक्षण करना और पहाड़ी ढलानों को खोखला करने वाले भूगत जल की निकासी के लिए पहाड़ी पर आवश्यक समझी जाने वाली नयी सुरंगों की व्यवस्था करना, पुलों की नीव को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए पानी की नालियों की सप्लाई और नालियों के पहलुओं का बचाव-कार्य नियमित रूप से करना।

(ख) 12.192 मीटर के वर्तमान स्पैन को चौड़ा करके 30.48 मीटर कर दिया गया था और पहाड़ी ढलान को पुख्ता करने और फिसलने से रोकने के लिए व्यापक बचाव-कार्य किये गये हैं।

(ग) जी हां।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रिक्त स्थान

2067. **श्री वयालार रवि** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के अनेक स्थान अभी भी रिक्त पड़े हैं; और

(ख) और विलम्ब किये बिना इन स्थानों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--10636/76]

(ख) रिक्त स्थानों को यथासंभव शीघ्र भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त हो चुके प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जिन राज्यों के प्राधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे उन्हें शीघ्र भेज दें।

केरल तट पर तेल के लिये खोज

2068. **श्री व्यालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस वर्ष के दौरान केरल तट पर तेल के लिये खोज प्रारम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फिलिप्स लिमिटेड के क्रियाकलापों की जांच

2069. **श्री वयालार रवि** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग फिलिप्स लिमिटेड के क्रियाकलापों की जांच कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग, वर्तमान में, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 10(क)(3) के अन्तर्गत, रजिस्ट्रार, निबंधनकारी व्यापार अनुबन्ध द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर मै० फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा निरत रहने के आरोपों युक्त निबन्धकारी व्यापार प्रथाओं की जांच कर रहा है। आयोग की, 1974 की 12 व 13 संख्यक जांचें, लिखित याचिकाओं के परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालयों द्वारा रोक दी गई हैं। 1975 की 18 व 26 संख्यक अन्य दो जांचों की बाबत, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने नोटिस प्रेषित किये हैं, एवं ये जांचें अब अभिवचनों के प्रक्रम पर हैं।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के कार्यकरण के परिणाम

2070. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974-75 में "इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड" के कार्यकरण के क्या परिणाम रहे;

(ख) आरम्भ से लेकर अब तक इस कंपनी को कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस को लाभप्रद उपक्रम बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) 1974-75 वर्ष के लिए भारतीय औषध एवं भेषज के कार्य की समीक्षा सहित वार्षिक रिपोर्ट 19 जनवरी, 1976 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

(ख) 1973-74 के अन्त तक कंपनी की कुल एकत्रित हानि 40.08 करोड़ रुपए थी। तथापि कम्पनी ने वर्ष 1974-75 के दौरान 248.56 लाख रुपये का शुद्ध लाभ उठाया जिससे 31-3-75 तक एकत्रित हानि में 37.60 करोड़ रुपए की कमी हुई।

(ग) कम्पनी को हुई हानि के निम्नलिखित कारण है:--

(1) आई डी पी एल की एन्टीबायोटिक संयंत्र, सिन्थैटिक औषध संयंत्र और शल्य-चिकित्सा उपकरण संयंत्र की स्थापना करने के लिए यू एस एस आर सरकार की सहायता से 1961 में औपचारिक रूप में स्थापना की गई थी। उपस्कर, तकनीकी रूप रेखाओं और देशी उपस्कर तथा मशीनरी की सप्लाई में कुछ देर होने के कारण आई डी पी एल को ऋण लेना पड़ा था जिससे व्याज के रूप में उन्हें काफी व्यय करना पड़ा था ।

(2) दोनों सिन्थैटिक औषध संयंत्र और एन्टीबायोटिक संयंत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बड़े सुधार और संशोधन किए जाने थे।

(3) एन्टीबायोटिक्स संयंत्र ऋषिकेश में बिजली की बाधाएं होती रही हैं । लगातार बिजली की कमी के कारण अब तक संयंत्र अपने उत्पादन को स्थिर न कर सका है ।

(4) एन्टीबायोटिक संयंत्र ऋषिकेश को दिए गए स्ट्रेन, भारत में वर्तमान अन्य संयंत्रों को दिए गए स्ट्रेनों से कम उत्पादन करने वाले स्ट्रेन है ।

(5) अपेक्षित कच्चे माल के मूल्य और अन्य खर्चे जैसे वेतन, बिजली ईंधन 1970-71 से 1974 के मध्य तक कई गुणा बढ़ गए थे। बिक्री मूल्य वैसे के वैसे रहने से कंपनी को काफी हानि उठानी पड़ी थी।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित के अनुसार आई डी पी एल को 1974-75 के दौरान 248.56 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। 1975-76 के दौरान लगभग 266 लाख रुपये का शुद्ध लाभ होने की संभावना है।

गाहासंद में रेलगाड़ी की छत पर यात्रा कर रहे पांच यात्रियों की मृत्यु

2071. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 22 मार्च, 1976 को हुई उस घटना के तथ्य क्या है जिसमें साजनवा रेलवे स्टेशन के निकट गाहासंद में रेलगाड़ी की छत पर यात्रा कर रहे पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) क्या गार्ड तथा अन्य रेल कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी की छत पर यात्रा करने से न रोक कर अपने कर्त्तव्य में लापरवाही की; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यह सही नहीं है कि 22-3-76 को सहजनवा स्टेशन के पास पांच व्यक्ति गाड़ी की छत पर यात्रा करते हुए मारे गये थे किन्तु 21-3-76 को 23.30 बजे जब 17 अप वैशाली एक्सप्रैस गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-गोंडा खण्ड पर स्थित खलीलाबाद स्टेशन पर पहुंची तब ड्यूटी वाले सहायक स्टेशन मास्टर ने दो अलग-अलग बोगियों की छत पर दो व्यक्तियों को सख्त घायल और बेहोश पड़े हुए देखा । ये दोनों व्यक्ति बिना टिकट थे। सम्भवतः इन दोनों व्यक्तियों को उस समय चोटें लगी थी जब गाड़ी जगतबेला और सहजनवा स्टेशनों की बीच रापती नदी पर बने हुए गर्डर पुल सं० 49 के ऊपर से गुजर रही थी । स्टेशन के रेल कर्मचारियों ने तुरंत उनका प्रथमोपचार किया और उन्हें तुरंत खलीलाबाद के जिला बोर्ड अस्पताल ले जाया गया जहां 22-3-1976 को उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी । दूसरा व्यक्ति 22-3-76 को जिला सिविल अस्पताल बस्ती में भेज दिया गया था और उसकी हालत में सुधार होने की सूचना मिली है ।

(ख) जब यह गाड़ी 21-3-1976 को 22.25 बजे गोरखपुर से रवाना हुई तब सोलह बोगी वाली इस गाड़ी के किसी भी डिब्बे की छत पर कोई यात्री नहीं था। गाड़ी सीधी खलीलाबाद आयी और ऐसा मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति गोरखपुर स्टेशन से गाड़ी के रवाना होने के बाद अंधेरे में छत पर चढ़ गये थे। ड्यूटी की लापरवाही के लिए किसी रेल कर्मचारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुकिंग गैस के लिए प्रतिक्षा सूची

2072. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुकिंग गैस कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा करने वालों की एक लम्बी सूची है; और

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1976 को प्रतीक्षा करने वालों की संख्या कितनी थी और इन लोगों को शीघ्र गैस उपलब्ध कराने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जयाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) एल० पी० जी०/ खाना पकाने वाली गैस के प्रयोग में सुविधा के कारण उसकी बहुत बड़ी मांग है। शोधनशालाओं से एल०पी०जी० की उपलब्धता, शोधित किए हुए विभिन्न कच्चे तेल से उत्पादन और शोधन करने वाले कच्चे तेल की कुल मात्रा की उपलब्धता पर आधारित है। कच्चे तेल के आयात में विदेशी मुद्रा की कठिनाईयों के कारण एल०पी०जी० की सप्लाई सीमित है और मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः मांगते ही गैस कनेक्शन का मिल जाना संभव नहीं है। गैस कनेक्शन लेने के लिए प्रतीक्षा अवधि एक स्थान से दूसरे स्थान से भिन्न है। उत्पादन और एल०पी०जी० की सप्लाई में वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं फिर भी एल०पी०जी० की सप्लाई और मांग में विभिन्नता रहेगी। तथापि, इन कठिनाइयों के बावजूद इण्डियन आयल कारपोरेशन के लिए 1975 के दौरान देश में लगभग 2,40,000 नए उपभोक्ताओं को कनेक्शन देना संभव हो पाया है।

एल०पी०जी० की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रख कर नए मिट्टी के तेल के स्टोव का निर्माण किया गया है। नए स्टोव में इस समय मार्कीट में स्टोव से अधिक थर्मल कुशलता और अधिक ताप उत्पन्न करने की शक्ति है। नए स्टोव को एल०पी०जी०स्टोव की तुलना में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

जहां तक दिल्ली क्षेत्र का संबंध है मथुरा शोधनशाला के आरंभ होने से सप्लाई में पर्याप्त सुधार होने की संभावना है।

प्रत्येक राज्य में प्रत्येक एक लाख लोगों के लिए रेलवे लाइन की लम्बाई

2073. **श्री के० मलन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में एक लाख लोगों के लिये कितने मील लम्बी रेलवे लाइन उपलब्ध है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-- 10637/76]**

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड द्वारा 'बल्क' औषधियों का उत्पादन

2074. **श्री भालजी भाई रावजीभाई परमार :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, मद-वार इण्डियन ड्रग्स एण्ड. फार्मेस्युटिकल लिमिटेड में 'बल्क' औषधियों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) सरकार ने इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मेस्युटिकल लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली 'बल्क' औषधियों के लिये क्या मूल्य निर्धारित किये हैं;

(ग) कितने मामलों में कम्पनी ने मूल्य निर्धारित किये थे और कितने मामलों में सरकार की मंजूरी ली गई थी; और

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम और इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मेस्युटिकल लिमिटेड द्वारा 'बल्क' औषधियों के अधिक मूल्य लिये जाने के कारण देश में औषधियों के मूल्य अधिक हैं; और यदि हां, तो सरकार इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मेस्युटिकल लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली प्रत्येक औषधि की लागत निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 (फरवरी 1976 तक) के दौरान आई० डी० पी० एल० द्वारा विभिन्न औषधों का उत्पादन दिखाने वाला विवरण-पत्र-I संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--10638/76]**

(ख) से (घ) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत स्वीकृत आई० डी० पी०एल० द्वारा निर्मित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रपुंज औषधों के मूल्य दिखाने वाला विवरण पत्र-II संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--10638/76]** औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 व्यापक है। आई डी०पी०एल० द्वारा निर्मित औषधों के मूल्य, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यौरों द्वारा अपेक्षित छानबीन/जांच के बाद उक्त आदेश के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित/स्वीकृत किए गए हैं ।

प्रपुंज औषधों के सभी विषयों के बारे में आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा सारणीबद्ध है और मूल्य बी० आई० सी० पी० द्वारा लागत की छानबीन करने के बाद सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

चूंकि मूल्य औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश के अनुबंधों के अन्तर्गत निर्धारित किए जाते हैं और उसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि एक बार निर्धारित मूल्यों को सरकार की पूर्व अनुमति लिए बिना उनको संशोधित नहीं किया जा सकता, इसलिए एम० टी० सी०/आई० डी० पी० एल० द्वारा अधिक मूल्य लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Private buildings hired by Railways in Kota (Rajasthan)

2075. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of private buildings hired in Kota, Rajasthan by the Railways ; and

(b) the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Six.

(b) These buildings have been hired for the residential use of Officers of the Construction Organisation. Owing to shortage of railway accommodation at Kota, these Officers could not be housed in Railway Quarters.

These posts, being work-charged, are of short-term nature, and construction of regular quarters against these posts is, therefore, not justified.

भदोही रेलवे स्टेशन

2076. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में भदोही देश में कालीन बनाने का एक बड़ा केन्द्र है: और यूरोपीय, अमरीकी तथा अरब देशों को कालीनों का निर्यात कर रही हैं ;

(ख) क्या भदोही रेलवे स्टेशन निम्न स्तर का है और वहां विदेशियों के लिये, जो सामान्यतय ई का गाड़ी से भी दौरा करते हैं, वस्तुतः पहली श्रेणी का कोई उपयुक्त प्रतीक्षालय नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार स्टेशन की एक नई इमारत बनाने की है जिसमें आधुनिक सुविधायें दी जायेंगी और प्रतीक्षालय भी होंगे ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं । भदोही में पहले दर्जे के यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, जिसका उपयोग गाड़ी से भदोही आने वाले विदेशियों द्वारा भी किया जाता है ।

(ग) भदोही में स्टेशन की नयी इमारत बनाने का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है । तथापि, स्टेशन पर दो बिस्तर वाले एक जनता विश्राम---कक्ष की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

इटानगर को टिपलिंग से रेल द्वारा जोड़ने के लिए सर्वेक्षण

2077. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटानगर को टिपलिंग से रेल द्वारा जोड़ने के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा किया जा रहा सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हों, तो इस लाइन पर काम कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) टिपलिंग और इज्जतनगर के बीच एक नयी मीटर लाइन बिछाने के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद् के खर्च पर यातायात एवं इंजीनियरी टोह सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसके अक्तूबर 1977 तक पूरा कर लिये जाने की आशा है । इस प्रस्तावित रेलवे लाइन के संबंध में आगे विचार, सर्वेक्षण के पूरा हो जाने और उसके परिणामों की जानकारी हो जाने के बाद ही किया जायेगा।

नार्थ लखीमपुर और सिलपत्थर स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुविधायें

2078. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्थ लखीमपुर और सिलपत्थर रेलवे स्टेशनों पर उतरने और चढ़ने वाले यात्रियों की औसत संख्या जनवरी, 1976 में प्रतिदिन क्या रही है; और

(ख) उन रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को रेलवे द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जनवरी, 1976 में चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों की औसत संख्या क्रमशः 560 और 369 थी जबकि सिलपत्थर में यह संख्या क्रमशः 350, और 300 थी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

नार्थ लखीमपुर

दूसरे दर्जे का प्रतीक्षालय, यात्री प्लेटफार्म (अंशतः छतदार), 2 नल-कूप, प्लेटफार्म पर एक नल, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग मूत्रालय व शौचालय, प्लेटफार्म पर और प्रतीक्षालय में बेंचें खान-पान सुविधाएं।

सिलपाथर

प्रतीक्षालय, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग मूत्रालय व शौचालय, पानी के दो नल और प्लेटफार्म पर बेंचें।

वातानुकूलित रेलगाड़ियों के दूरगामी यात्रियों के लिये सोने के लिये स्थान की व्यवस्था करने की योजना

2079. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वातानुकूलित रेलगाड़ियों में श्रेणी दो की चेयर कारों द्वारा यात्रा करने वाले दूरगामी यात्रियों को सोने के लिये स्थान देने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब और किस प्रकार क्रियान्वित की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, वातानुकूल कुर्सी यान के स्थान के अलावा, लम्बी दूरी के यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक डीलक्स एक्सप्रेस गाड़ी में वातानुकूल 2-टियर शयन-यान की व्यवस्था की गयी है, जिसमें पहले दर्जे का किराया देना होता है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उपकरणों का देश में ही निर्माण

2080. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग प्रमुख सामग्री का निर्माण करने और उपकरणों का आधुनिकीकरण करने के लिए अपेक्षित तकनीकी जानकारी का देश में ही विकास करने के लिये कदम उठा रहा है ;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग "ड्रिलिंग रिगों" के लिये पहले ही भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड को क्रयादेश दे चुका है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को 7 डीजल इलेट्रिक रिगों के लिए आर्डर दे दिया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूकम्प सूचक यंत्रों का निर्माण

2081. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 'डिजिटल' भूकम्पीय कार्य सूचक और "वैल लागिंग" के लिये अपेक्षित भूकम्प सूचक यंत्रों तथा अन्य उपकरणों के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी हां। पहले आयोग ने डिजिटल भूकम्पीय तथा वैल लागिंग कार्य के लिए अपेक्षित एनालाग टाइप भूकम्पीय संयंत्रों, रशियन टाइप वैल लागिंग उपस्कर और विभिन्न सहायक उपकरणों जैसे एनालाग मैगनेटिक टेप्स, रिकॉर्डर पेनल्स, रेक्टीफाइयर पेनल्स, फ्रीक्वेन्सी मॉडूलेटेड टाइप ब्रेक ट्रान्समिशन सिस्टम आदि का उत्पादन किया है। हाल ही में आयोग ने, न्यूनतम डिजिटल भूकम्पीय पद्धति के प्रकार और साफिस्टीकेटेड वैल लागिंग उपस्कर के देशी विकास/निर्माण के लिए प्रायोजनाओं को ले लिया है। डिजिटल भूकम्पीय संयंत्रों का इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इण्डिया हैदराबाद में उत्पादन किया जाता है और आधुनिक वैल लागिंग पद्धति का भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर, बम्बई में उत्पादन किया जायेगा।

रेलगाड़ियों में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बों की संख्या में कमी

2082. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिक लोगों को स्थान दिलाने तथा दुर्बल वर्गों के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से रेल गाड़ियों में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बों की संख्या में कमी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) सवारी गाड़ियों में उपलब्ध वातानुकूल पहले दर्जे सहित सभी दर्जों के स्थान के उपयोग पर कड़ी निगाह रखी जाती है और आवधिक समीक्षा की जाती है। यात्री जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए जहां आवश्यक समझा जाता है, गाड़ियों के दर्जे-वार डिब्बों में समुचित समायोजन कर दिया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के एककों में उत्पादित औषधियां

2083. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के एककों में इस समय तैयार की जाने वाली औषधियां कुल आवश्यकता के कितने प्रतिशत है; और

(ख) औषधियों के कुल उत्पादन की कितने प्रतिशत औषधियां इस समय गैर सरकारी एककों में बनाई जाती हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) औषधों की वर्ष-वार आवश्यकताओं से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। औषध और भेषज उद्योग समिति ने बताया है कि 1973 में 75 करोड़ रुपए के कुल उत्पादन की तुलना में सरकारी क्षेत्र में 24 करोड़ रुपये का प्रपुंज औषधों का उत्पादन किया। अनुमान है कि इस समय भी सरकारी क्षेत्र देश में कुल प्रपुंज औषधों का 1/3 भाग उत्पादन करता है तथा शेष मात्रा गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित की जा रही है।

दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा तथा राजस्थान के नगरों के बीच तेज चलने वाली विद्युत रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

2584. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जनसंख्या के दबाव को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा एवम् राजस्थान के विभिन्न नगरों के बीच तेज चलने वाली विद्युत रेलगाड़ियाँ चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव सम्भवतः कब क्रियान्वित किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) हावड़ा-दिल्ली मुख्य मार्ग का बिजलीकरण पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप, मुगलसराय के रास्ते हावड़ा-दिल्ली मुख्य लाइन पर स्थित उत्तर प्रदेश और बिहार के अनेक नगर बिजलीकर्षण के द्वारा दिल्ली से जुड़ जायेंगे। हावड़ा गाजियाबाद खण्ड का बिजलीकरण पूरा हो चुका है और शेष खण्ड अर्थात् दिल्ली गाजियाबाद का बिजलीकर्षण दिसम्बर, 1976 तक कर दिये जाने की आशा है।

उपनगरीय गाड़ियां चलाने के संबंध में, जिसमें दिल्ली के चारों ओर बिजली गाड़ियां चलाना भी शामिल है, अध्ययन किये गये हैं और इन अध्ययनों की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

बिहार में रेलगाड़ियों में बिजली की व्यवस्था

2085. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष कर बिहार राज्य में रात को चलने वाली अधिकांश रेलगाड़ियों में बिजली की व्यवस्था नहीं है और इसके फलस्वरूप यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने भी इस संबंध में केन्द्र सरकार को लिखा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। बिहार राज्य में चलने वाली गाड़ियों सहित सभी रेल गाड़ियों के डिब्बों में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। तथापि, बदमाशों की कार्रवाइयों के कारण कुछ डिब्बों में बिजली के सामान की कमी के फलस्वरूप कभी-कभी अपर्याप्त रोशनी के बारे में यात्रियों से शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। बदमाशों की कार्रवाइयों द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों के बावजूद यात्री सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से विशेष जांच की जाती है। आपात-स्थिति से पहले की अवधि में हुई सभी प्रकार की कमी का हिसाब लगाने के लिए प्रबंध किये गये हैं और इस प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए 1976-77 के बजट में 3.5 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुमति-पत्रों के आधार पर विदेशी औषधि फर्मों द्वारा उत्पादन

2086. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**: क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी फर्मों को कितने अनुमति-पत्र जारी किये गये, उनमें से कितने अनुमति-पत्रों को सी० ओ० बी० अथवा अन्य लाइसेंसों में बदल दिया गया है और इन अनुमति पत्रों के आधार पर गत तीन वर्षों के लिए मदवार एवं कम्पनीवार उत्पादन और आयातित अंश का क्या ब्यौरा है; और

(ख) इन अनुमति-पत्रों और सी० ओ० बी० लाइसेंसों को गैर-कानूनी बना देने के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) (i) 26% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाले औषध फर्मों तथा (ii) उनको जारी किये गये अनुमति/अनापत्ति पत्रों के ब्यौरे औषध एवं भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट के पांचवीं अध्याय क्रमशः परिशिष्ट IV तथा परिशिष्ट II में दिये गये हैं । इस रिपोर्ट की एक प्रति 8/5/75 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी। 1970 में संशोधित लाइसेंसिग नीति के अनुसरण में विविधीकरण और/अथवा लाइसेंसिंग में छूट से संबंधित पूर्व योजना के अन्तर्गत स्थापित कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए सी० ओ० वी० लाइसेंस जारी किये गये थे । उपरोक्त, रिपोर्ट के अध्याय 5 के परिशिष्ट 111 में ऐसे लाइसेंसों के ब्यौरे दिये गये हैं, अनुमानित/अनापत्ति-पत्रों में दिये गये मदों की संख्या तथा गत तीन वर्षों से उनके आयात, मात्रा तथा वास्तविक उत्पादन से सम्बन्धित आंकड़ों में एकत्रित करने में नीहित समय तथा श्रम संभावित परिणामों के साथ मेल नहीं खाते ।

औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति ने समस्त मामले की जांच की है तथा इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं जिन पर जांच की जा रही है।

विदेशी औषध फर्मों को 'सी० ओ० बी०' लाइसेंसों की स्वीकृत

2087. **श्री नानूभाई एन० पटेल** :

श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली कुछ विदेशी फर्मों को 'सी० ओ० बी०' लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं और उनकी समेकित क्षमताएं क्या हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं और गत दो वर्षों में स्वीकृत किये गये 'सी० ओ० बी०' लाइसेंसों का, उनकी क्षमता और वास्तविक उत्पादन सहित ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) और (ख) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी कम्पनियों के नाम जिनको एफ० ओ० बी० लाइसेंस दिये गये हैं, उनकी समेकित क्षमताओं को दर्शाने वाला विवरण पत्र-I संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०--10639/76]

मैसर्स रुसल फार्मास्यूटीकल्स लि० को छोड़कर अन्य कम्पनियों को दिये गये, सी० ओ० बी० लाइसेंस और उनकी क्षमताओं के ब्यौरे, औषध और भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट के अध्याय 5 में दिये गये हैं, जिसकी एक प्रति 8-5-75 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी । जहां तक मैसर्स रुसल फार्मास्यूटीकल (इंडिया) लि० का संबंध है, उनको दी गई क्षमताओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

सी०ओ०बी० लाइसेंस संख्या और तिथि	प्रतिमास निर्माण की मद और क्षमता
आई० एल० 55/(75)	1. 475.36 लाख गोलियां प्रति वर्ष
दिनांक 27-12-75	2. 25,377 किलोग्राम मरहम प्रति वर्ष

3. 22,680 लिटर; पेय तरल प्रति वर्ष

4. 11.98 लाख वायल्स प्रति वर्ष

5. 7.19 लाख एम्पल्स प्रति वर्ष

5. 1000 सोफ़ातुला प्रतिवर्ष

मैसर्स मे एण्ड बेकर को गत 2 वर्षों के दौरान सी० ओ० बी० लाइसेंसों के अन्तर्गत दी गई समेकित क्षमता वाले मदों का उत्पादन संलग्न विवरण पत्र II' में दर्शाया गया है। अन्य कंपनियों के बारे में इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन

2088. **श्री नरसिंह नारायण पांडे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय भारतीय रेलवे अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अधिनियम में संशोधन करने के लिए तैयार किए गए पहले मसौदे का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) रेलवे बोर्ड के वर्तमान ढांचे में किसी प्रकार के मौलिक परिवर्तन करने का अभी कोई विचार नहीं है।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में भूकम्पीय प्रक्रिया कम्प्यूटर केन्द्र

2089. **श्री पी० गंगा देव : क्या पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 फरवरी, 1976 को भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून में एशिया का सबसे बड़ा भूकम्पीय प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) कम्प्यूटर केन्द्र चालू किया गया था ;

(ख) क्या उक्त केन्द्र के कारण तेल के खोज-कार्य की गति में तीव्रता आयेगी ; और

(ग) क्या इससे भूकम्पीय आंकड़ों की जानकारी में अन्य देशों पर भारत की निर्भरता भी समाप्त हो जाएगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :

(क) जी हां, देहरादून में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का पेट्रोलियम अन्वेषण संस्थान में।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

तेल की खुदाई के लिए जहाज

2090. **श्री पी० गंगा देव** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को हिन्दुस्तान शिपयार्ड में निर्मित जहाज हाल में प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इन जहाजों में आधुनिक उपकरण लगे हुए है; और

(ग) यदि हां, तो खुदाई अभियानों में ये जहाज किस प्रकार उपयोगी होंगे ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) ये पोत अपतटीय व्यवधनरिगो को व्यधन सामग्री आदि का परिवहन करने के लिए इस्तेमाल की गई सप्लाई बोट है ।

Creation of Division at Mughalsarai (Eastern Railway)

2091. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether one more Railway Division at Mughalsarai on the Eastern Railway is proposed to be created;

(b) whether in view of the proposed Division the payment to a number of railway employees working in Mughalsarai are now being made in Mughalsarai itself ; and

(c) if so, the time by which the Division is proposed to be created at the said station?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) Payment to railway staff working at Mughalsarai has all along been made at Mughalsarai itself.

(c) The definite time for the establishment of the Division has not yet been finalised.

Supply of Uniform to T.T.E. Porters

2092. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Government propose to provide T.T.E. porters with uniforms like that of coach attendents in view of the fact that both categories of employees are on duty in the same trains?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : The criteria adopted for determining a particular category of staff eligible for uniforms are the identifiability by the public, recognition of one category of staff by another, in a limited number of cases on grounds of safety and security and the nature of duties performed. As the T.T.E. Porters do not fulfil the criteria laid down, they are not eligible for the supply of uniforms.

Looting of Sabarmati Express near Kanpur

2093. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Sabarmati Express was looted near Kanpur in the first week of March, 1976;

(b) if so, the number of persons injured and killed, separately and the amount looted in cash as also the value of the goods looted;

(c) the number of persons arrested in this connection ; and

(d) whether G.R.P. and R.P.F. personnel were on duty in the train at that time and if so, action taken by them?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (d) Yes. Two dacoities were committed in the Sabarmati Express near Kanpur during first week of March, 1976.

The first incident which took place between Kanpur and Unnao on 29-2-1976/1-3-1976, cash amounting to Rs. 3,560 and other belongings of passengers worth about Rs. 1,040 were looted. No person was killed. However one person received injuries.

The train was not escorted either by Government Police or Railway Protection Force Personnel.

The second incident took place between Paman and Kanpur on 1/2-3-1976 in which one Sub-Inspector of Police was killed and two passengers were injured. Only personal belongings of passengers worth about Rs. 650 were looted, out of which property worth Rs. 500/- has been recovered.

This train was escorted by two constables of Government Railway Police, who were five bogies away from the affected coach. On receipt of the information they tried to apprehend the culprits but in vain.

Both these incidents of dacoities are reported to have been committed by the same gang and seven suspects have so far been arrested by the Police.

मैकेनिकल वर्कशाप, झांसी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति

2094. **श्री नाथू राम ग्रहिरवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकेनिकल वर्कशाप झांसी में गत तीन वर्षों के दौरान कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति की गई है; ग्रौर

(ख) उनमें से पृथक-पृथक कितने कर्मचारी ग्रनुसूचित जातियों ग्रौर ग्रनुसूचित जन जातियों के हैं ग्रौर ग्रनुसूचित जनजातियों के लिए ग्रारक्षित कितने पदों को ग्रागे ले जाया गया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) :

(क)	(1)	1973-74	171
	(2)	1974-75	72
	(3)	1975-76	117

(ख) 1973-74, 1974-75 ग्रौर 1975-76 में ग्रनुसूचित जातियों के क्रमशः 49, 28 ग्रौर 56 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया था। ग्रनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं था । ग्रनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए जो पद ग्रग्रानीत किए गए वे 1973-74 में 11, 1974-75 में 3 ग्रौर 1975-76 में 10 थे।

बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929

2095. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के अधीन अपराध केवल गुजरात राज्य में ही संज्ञेय अपराध है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०वी०ए० सईद मुहम्मद) :(क) जी हां।

(ख) 15 जुलाई, 1964 से ।

गया-साहिबगंज यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना

2069. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के गया किऊल सेक्शन पर वजीरगंज रेलवे स्टेशन के निकट हाल में 338 डाउन गया-साहिबगंज यात्री गाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया था; और

(ख) यदि हां, तो इंजन पटरी से उतरने के क्या कारण थे, इसके परिणामस्वरूप कितनी रेल सम्पत्ति की क्षति हुई और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि, 21-2-1976 को, 324 डाउन गया-साहिबगंज सवारी गाड़ी का इंजन मानपुर और वजीरगंज स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गया था ।

(ख) यह दुर्घटना बदमाशों द्वारा पटरी पर रखी पत्थर की गिट्टी के कारण हुई। रेल सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई। बदमाशों द्वारा की जाने वाली ऐसी कारवाई को रोकने के लिए पटरी पर गहन गश्त शुरु की गई है ।

बिहार के सन्थाल परगना के लिये रेल लाइनें

2097. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सन्थाल परगना जिले के मुख्य शहरों/नगरों को जोड़ने वाली नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है और उसे यातायात के लिए कब तक खोला जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) संथाल परगना में पड़ने वाले प्रस्तावों की मुख्य बातें, जिनका अभी हाल में सर्वेक्षण किया गया है, इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	प्रस्ताव का नाम	लम्बाई (कि० मी० में)	लागत लाख रुपयों में)
1.	मन्दरहिल-दुमका	64.00	707.21
2.	दुमका-साइंथिया	56.00	551.00
3.	दुमका-वैद्यनाथधाम .	63.00	695.95
4.	दुमका-रामपुर हाट	54.00	518.40
5.	दुमका-मधुपुर .	59.00	650.73
6.	हजारीबाग-टाउन-हजारीबाग रोड	78.00	1207.00
7.	हजारीबाग रोड-गिरिडीह .	56.00	861.58
8.	हजारीबाग टाउन-रांची रोड	40.00	618.00

सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है। इन रिपोर्टों की जांच कर लिए जाने के बाद, धन-राशि की उपलब्धता के आधार पर, इन परियोजनाओं को शुरु करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जाएगा।

फोर्बसगंज में बरौनी-जोगबनी ट्रेन और बस की दुर्घटना

2098. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 फरवरी, 1976 को फोर्बसगंज के बिना चौकीदार वाले रेलवे क्रासिंग पर बरौनी-जोगबनी यात्री गाड़ी के इंजन से एक बस की टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके परिणामस्वरूप कितने यात्रियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए; और

(ग) ऐसे क्रासिंग पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बस ड्राइवर ने बिना चौकीदार वाला समपार उस समय पार करने की कोशिश की थी जब गाड़ी निकट पहुंच गई थी। इस दुर्घटना में बस के अन्दर बैठे हुए 3 व्यक्तियों को चोटें आई।

(ग) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए गए हैं, जैसे आगे के बिना चौकीदार वाले समपार को पार करने वाले सड़क उपयोगकर्त्ताओं को चेतावनी देने के लिए 'रुको पट्ट' लगाना; गाड़ी चालकों को सीटी बजाने का आदेश देने वाले "सीटी पट्टों" की व्यवस्था करना; समपारों पर चौकीदार लगाने की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए यातायात की आवधिक गणना करना; इश्तहारों, सिनेमा स्लाइडों, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर घोषणाओं, रेडियो वार्ताओं के जरिए और ड्राइवरों तथा परिवहन संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके, सड़क उपयोगकर्त्ताओं में शिक्षात्मक अभियान चलाना; समपारों पर अचानक जांच करना आदि अधिकांश राज्य सरकारों ने मोटर वाहन नियमों के अन्तर्गत नियम बनाकर मोटर वाहनों के चालकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे बिना चौकीदार वाले समपार के पास आकर रुक जाएं और केवल तभी समपार को पार करें जब आगे-आगे कंडक्टर चल रहा हो। सड़क उपयोगकर्त्ताओं द्वारा मोटर वाहन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से छापे भी मारे जाते हैं। सभी राज्य सरकारों और संघीय प्रशासनों से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे मोटर वाहन नियमों की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन कराएं।

बम्बई वी०टी० को जाने वाली उपनगरीय रेल गाड़ी में आग लगने की घटना

2099. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

श्री समर गुह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 21 फरवरी, 1976 को मध्य रेलवे की बम्बई वी० टी० को जाने वाली एक उपनगरीय रेलगाड़ी के एक डिब्बे में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो आग लगने का क्या कारण था और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए ;

(ग) क्या दस दिन के भीतर बम्बई की रेलगाड़ी में आग की यह दूसरी घटना है; और

(घ) एसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार ने आगे क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) जी नहीं। तथापि 21-2-76 को चिंचपोकली स्टेशन पर टी 52 अप उपनगरीय स्थानीय गाड़ी के मोटर डिब्बे के उच्च वोल्टता कक्ष के रोशनदान से धुंआ निकलता हुआ दिखाई दिया, जो मुख्य चालन प्रतिरोधक के अधिक गरम हो जाने के कारण था। चूंकि आग नहीं लगी थी, इसलिए किसी के हताहत होने का प्रश्न नहीं उठता।

थर्मल रिले प्राप्त करके उसे परीक्षात्मक रूप में मोटर डिब्बों के उच्च वोल्टता कक्षों में लगा दिया गया है ताकि अधिक गर्मी में बिजली सर्किट पर प्रभाव न पड़े।

पश्चिम बंगाल की मैसर्स मार्टिन एंड हैरिस का अधिग्रहण

2100. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने मैसर्स मार्टिन एंड हैरिस, कोन्नोगोर की एस्प्रिरिन निर्माता कम्पनी का अधिग्रहण करने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या पूर्वी भारत में यह एक मात्र एस्प्रिरिन निर्माता संयंत्र है और वह भी लगभग एक वर्ष से बन्द पड़ा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल का पूर्वी भारत में केवल एस्प्रीन उत्पादन करने वाली कम्पनी को लेने के प्रस्ताव पर अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया गया है। आई० डी० आर० अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत संयंत्र के प्रबन्ध को अन्तिम रूप में लेने के बारे में अन्तिम निर्णय लेने हेतु और अधिक सूचना प्रस्तुत करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मामला उठाया गया है। उक्त सरकार से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्हें अनुस्मारक भेज दिया गया है।

स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट एंड कंपनी, कलकत्ता का कार्यकरण

2101. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एंड कम्पनी, कलकत्ता नाम की औषधि फर्म इस समय इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य कर रही है अथवा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० के प्रबन्ध के अन्तर्गत एक पृथक एकक के रूप में कार्य कर रही है;

(ख) हाथी समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार उक्त फर्म का राष्ट्रीयकरण न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य कर सके ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) :(क) और (ख) आई० डी० आर० अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मैसर्स स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट एंड कम्पनी कलकत्ता का प्रबन्ध सरकार द्वारा ले लिया गया था और उसके बाद भारतीय औषध एवं भेषज लि० इस संयंत्र का प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहा है। यह संयंत्र एक अलग संयंत्र के रूप में कार्य कर रहा है । इस संयंत्र की भविष्य में स्थापना का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

(ग) संयंत्र को सरकारी एजेंसियों अर्थात् राज्य व्यापार निगम और आई० डी० पी० एल० से सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड संभव और यथा कच्चे माल की सप्लाई होती है।

आंध्र में फिलामेंट यार्न फैक्ट्री

2102. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र सरकार को किसी विदेशी फर्म के सहयोग से नायलोन फिलामेंट यार्न फैक्टरी स्थापित करने की अनुमति अभी तक नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं, जैसे देश में नाइलोन यार्न उद्योग का कुल विकास और नाइलोन संयंत्रों की विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने की आवश्यकता विभिन्न संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जांच के अधीन है । निहित मूल विषयों का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

रेग्रर अर्थ कम्पलेक्स, छतरपुर में रेलवे साइडिंग

2103. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु शक्ति आयोग ने दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा डिवीजन में रेग्रर अर्थ कम्पलैक्स, छतरपुर के स्थान पर रेलवे साइडिंग की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने से पहले सर्वेक्षण करना जरूरी है। तदनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे परमाणु उर्जा विभाग के इंडियन रेग्रर अर्थ्स के साथ परामर्श करके सर्वेक्षण सम्बन्धी अनुमानों को अन्तिम रूप दे रही है। सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने और विस्तृत नक्शे तथा अनुमान तैयार हो जाने के बाद रेलवे द्वारा इस प्राइवेट साइडिंग सम्बन्धी निर्माण-कार्य को शुरू किया जायेगा। इस काम पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है क्योंकि इसका सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है।

कर्नाटक राज्य के लिए वर्ष 1976-77 में मंजूर की गई रेलवे लाइनें

2104. **श्री के० लकप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कर्नाटक राज्य के लिए कितनी रेलवे लाइनें मंजूर की गई हैं और इन लाइनों के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) वर्ष 1976-77 में कितनी नई रेलवे लाइनें मंजूर किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कर्नाटक राज्य में पिछले दो वर्षों की अवधि में कोई नई रेलवे लाइन मंजूर नहीं की गई है लेकिन दो लाइनों—हसन-मंगलूर और तोरनागल्लु-मृदुकुल-पेंटा—के निर्माण का काम प्रगति कर रहा है।

(ख) 1976-77 के बजट में किसी नई रेलवे लाइन का प्रस्ताव नहीं है ।

इन्द्रजीत सिंह समिति के सुझाव

2105. **श्री बसन्त साठे** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मद्रास के सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट यूनिट को उस से अलग करने तथा उसे सरकारी क्षेत्र के किसी उचित इंजीनियरिंग संगठन को हस्तान्तरित करने का प्रश्न विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की पृष्ठभूमि क्या है और उस पर अन्तिम निर्णय क्या लिया गया है;

(ग) इन्द्रजीत सिंह समिति द्वारा क्या अन्य सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) से (घ) सरकारी उपक्रमों की समिति की 56वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसरण में एक समिति जिसमें सुविख्यात सर्जन, तकनीकी विशेषज्ञ तथा अधिकारी शामिल हैं, इंडियन ड्रग्स और फार्मास्यूटिक्ल्स लि० की एक एकक सर्जिकल इंस्ट्रुमेंटस प्लांट मद्रास की समस्याओं की जांच के लिए स्थापित की गई थी। समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय संयंत्र के लिए भावी स्वरूप का सुझाव देना था।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (मद्रास) संशोधन आदेश 1976

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (मद्रास) संशोधन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं । जो दिनांक 25 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा नि० 253(ङ०) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10627/76]

वर्ष 1976-77 के लिए इस्पात और खान शिक्षा और समाज कल्याण उर्जा मंत्रालयों संस्कृति विभाग, परमाणु उर्जा विभाग, अन्तरिक्ष संसद, संसददीय कार्य विभाग आदि की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): मैं वर्ष 1976-77 के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :

(एक) इस्पात और खान मंत्रालय

(दो) संस्कृति विभाग

(तीन) संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग

(चार) परमाणु ऊर्जा विभाग

(पांच) अन्तरिक्ष विभाग

(छ) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(सात) ऊर्जा मंत्रालय

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए सख्या एल० टी०** 10628/76]

सूती कपड़ा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिह) : आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सूती कपड़ा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 20 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सं० आ० 1096 में प्रकाशित हुआ था) [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए संख्या एल० टी०** 10629/76]

लोक सेवा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

208वां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता, उत्तरपूर्व) : मैं तूतीकोरिन में नई बन्दरगाह नौवहन और परिवहन मंत्रालय के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महा लेखापरीक्षक के वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) के पैरा 37 पर लोक लेखा समिति का 208वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

संविधान (32वां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (THIRTY-SECOND AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति में रिक्त स्थान भरने के लिये राज्य सभा के सदस्य नियुक्त करने के लिये राज्य सभा से सिफारिश

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, सर्वश्री लाल के० अडवानी, के० चन्द्रशेखरन, सलिल कुमार गांगुली, भूपेश गुप्त, रोशन लाल, ओम मेहता, वी० बी० राजू, मुल्क गोबिन्द रेड्डी और श्रीमती अजीजा इमाम के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर, राज्य सभा के नौ सदस्य नियुक्त करे तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, सर्वश्री लाल के० अडवानी, के० चन्द्रशेखरन, सलिल कुमार गांगुली, भूपेश गुप्त, रोशन लाल, ओम मेहता, वी० बी० राजू, मुल्क गोबिन्द रेड्डी और श्रीमती अजीजा इमाम के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर, राज्य सभा के नौ सदस्य नियुक्त करे तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की मांगें —1976-77—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—1976-77—*contd.*
रक्षा मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे विचार किया जाएगा।

श्री शिवाजी राव एस० देशमुख (परभनी) : विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही देश की रक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। अपने देश की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा प्रथम निवेदन यह है कि देश के रक्षा बजट में गत तीन चार वर्षों में जो वृद्धि की गई है, उससे सशस्त्र अधिकारियों के महंगाई भत्ते में जो वृद्धि हुई है, उसके अनुपात में नए उपकरणों को खरीदने में वृद्धि नहीं हुई है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि किसी भी सरकार के लिए देश की रक्षा करने की व्यवस्था करना ही उसका प्रथम कर्त्तव्य होता है। इस बजट में जो अनुदानों के रूप में मांग की गई है, उसकी धनराशि बहुत कम है। आज देश के चारों ओर जो नए बाह्य खतरें बढ़ रहे हैं उन्हें दृष्टिगत रखते हुए अनुदानों की मांगों में उसी अनुपात से वृद्धि की जानी चाहिए।

हम रक्षा योजना की बात करते है। वह योजना कैसी हुई जिसके अन्तर्गत हम अपने बड़े-बड़े शत्रुओं के विरुद्ध भी कार्यवाही नहीं कर सकते। हमारी सेना का रिकार्ड बहुत सी गौरवशाली रहा है। परन्तु यह बहुत खेद की बात है कि गत तीन चार वर्षों में इसे मूल आवश्यकताओं और आधारभूत उपकरणों से वंचित रखा जाता रहा है। यद्यपि हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं परन्तु तथ्य तो यह है कि हम अभी तक वायुसेना का आधुनिकीकरण करने की स्थिति में नहीं है। आधुनिकीकरण उपकरणों तथा यंत्रों से लैस होने पर जवानों के हौसले बुलन्द हो जाते हैं। इसीलिए मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय को उपकरणों सम्बन्धी की गई व्यवस्था में समुचित वृद्धि करनी चाहिए।

हमें अपने वायुसेना के कार्यकौशल पर अभिमान है। भारतीय वायुसेना के इस समय 45 स्क्वैड्रन हैं। 56 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के लिए इतनी कम वायुसेना का होना अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान द्वारा जो विमान प्राप्त किए जा चुके हैं। उन्हें दृष्टिगत रखते हुए क्या हमारे रक्षा मंत्री, यह कह सकते हैं कि हमारे पास उन जैसे विमान है? यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास फैंटम, एफ० 104 तथा मीरांज जैसे विमान नहीं है। परन्तु इन अभावों के बावजूद भी हम यह दावा करते हैं कि हमारी वायुसेना आधुनिक है, पूर्ण रूप से सुसज्जित है तथा वह आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में पूर्णतया समर्थ है।

चीन ने उत्तरी सीमा पर अनेक हवाई अड्डे बना लिए है। इन हवाई अड्डों से भारत के किसी भी महत्वपूर्ण नगर पर हमला करना काफी आसान है परन्तु क्या ऐसे खतरे का सामना करने के लिए हमारे पास उचित राडार व्यवस्था है? हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार जहां तक नौसेना का सम्बन्ध है, हमारे पास केवल विक्रान्त ही एक विमान वाहक पोत है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विक्रान्त का रिकार्ड काफी गौरवशाली है परन्तु जब हम इसकी तुलना विश्व के अन्य विमान वाहक पोतों से करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी तुलना में हमारा विक्रान्त कुछ भी नहीं है क्योंकि वह अणुशक्ति तथा अणु पनडुब्बियों से लैस है। यदि हमें डिएगो गर्सिया अड्डे के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए अपने नौसेना के बजट में भी उपयुक्त वृद्धि करनी चाहिए। इसी प्रकार हाल ही के तेल संकट के परिणामस्वरूप खाड़ी के देशों ने भी अपने आपको नए शस्त्रों से लैस कर

लिया है जिससे कि परिस्थितियों में और भी परिवर्तन आ गया है। इसी प्रकार यदि किसी समय पाकिस्तान तथा चीन मिलकर आक्रमण करते हैं तो हमें इस स्थिति में अवश्य होना चाहिए कि हम उनके संयुक्त आक्रमण का मुकाबला कर सकें। हमारे रक्षा मंत्री महोदय जो कुछ भी कहते हैं उसे हमें सही रूप से क्रियान्वित भी करना चाहिए तथा अपनी सेनाओं को हर प्रकार के आधुनिक शस्त्रों से लैस किया जाना चाहिए।

तट संरक्षकों की नियुक्ति का कार्य एक अच्छा कदम है। परन्तु यदि हमारे तट संरक्षकों को तट सुरक्षा कार्य के लिए छोटी छोटी किश्तियों से ही सुरक्षा कार्य करना है तो यह कार्य अधिक प्रभावशाली ढंग से नहीं हो पाएगा। अतः हमें इन्हें आधुनिक हथियारों से लैस करना चाहिए। इसी प्रकार तस्करों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी हमें आधुनिकतम यंत्रों को प्रयोग में लाना चाहिए। हमें 3000 से 4000 मील लम्बे समुद्रीतट की सुरक्षा करनी है।

यह ठीक है कि हमारी सेनाओं का रिकार्ड बहुत अच्छा है। वह अपनी बहादुरी के अनेक प्रदर्शन प्रस्तुत कर चुकी हैं, परन्तु केवल यह कहना कि हमारी सशस्त्र सेनाएं किसी से कम नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब समय आ गया जब, हमें इस बात का पूर्ण विश्लेषण करना होगा कि हमारी सेनाओं के पास उपलब्ध उपकरण, हमारे विमान तथा नौसैनिक पोत किस दर्जे के है। रक्षा मंत्री को साहसपूर्वक सदन से यह कहना चाहिए कि यदि रक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण हेतु और धन की आवश्यकता पड़ी तो वह सदन के समक्ष अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करने में नहीं हिचकायेंगे। उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि सेनाओं को देश की स्थल, जल तथा वायु सभी दिशाओं से पूर्ण सुरक्षा के समर्थ बनाया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : कुछ वर्ष पहले की बात है कि मैंने रक्षा मंत्री को इस बात के लिए बधाई दी थी कि वार्षिक प्रतिवेदन में गोपनीयता पर बहुत अधिक बल नहीं दिया गया था तथा उसमें सदस्यों को यथासंभव अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयत्न किया गया था। परन्तु यह खेद की बात है कि इस वर्ष के प्रतिवेदन में सदस्यों को अधिक जानकारी नहीं दी गई है। यह प्रतिवेदन असन्तोषजनक है तथा मेरा सुझाव है कि रक्षा मंत्री को इस पर पुनः विचार करना चाहिए।

सम्पूर्ण प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट होता है कि उसमें गुप्तचर संगठन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। निःसन्देह हम यह तो नहीं जानना चाहते कि यह किस प्रकार कार्य कर रहा है परन्तु हां, हम यह अपेक्षा अवश्य करते है कि प्रतिवेदन में गुप्तचर संगठन के नेतृत्व तथा उसके कार्यकरण सम्बन्धी उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

रक्षा मंत्री द्वारा यह कहा गया है कि हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार की तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि हम किसी भी समय तथा किसी भी स्थिति में उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, मैं समझता हूं कि यह एक अविश्वसनीय सा वक्तव्य है क्योंकि प्रतिवेदन में हमारी सशस्त्र क्षमता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आखिर हमारी मुकाबला करने की तैयारी कैसी है, इसके बारे में सदन को कुछ तो बताया ही जाना चाहिए।

हमारी नौसेना के कमजोर पहलुओं का उल्लेख भी किया गया है। आज दिएगो गर्सिया के नाम पर और [अधिक नौसैनिक तैयारिया करने की बात भी की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक हम अपनी नौसैना को अपेक्षित उपकरणों तथा शस्त्रों से लैस क्यों नहीं पर पाए? हिन्दमहासागर में यदि कोई खतरा उत्पन्न होता है तो हम उसका मुकाबला किस प्रकार करेंगे उसमें हमारी नौसैना किस-प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी? इसके बारे में कुछ न कुछ अवश्य बताया जाना चाहिए।

मैं पहले भी यह कह चुका हूं कि हमारे गुप्तचर संगठन का कार्यकरण प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए क्योंकि इस संगठन पर बहुत कुछ निर्भर करता है तथा पिछले कई अवसरों पर इस संगटन की त्रुटियों के कारण ही हमें असफलताओं का मुंह देखना पड़ा है। अतः इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह कहना नितान्त सही है कि हम अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 3 प्रतिशत भाग ही रक्षा पर व्यय करते हैं। यदि यह पर्याप्त है तो ठीक है अन्यथा उन्हें अधिक धन की मांग करनी चाहिए।

रक्षा पर किया जाने वाला अधिकतर धन विकास कार्यों पर खर्च होता है। उदाहरणतः सीमा-वर्ती सड़कों के निर्माण से उन स्थानों पर जाना सरल होता है जो अभी तक दुर्गम माने जाते थे तथा वहां विकास कार्य चालू किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आदि के कुछ भाग ऐसे हैं जहां हर समय रक्षा प्रबन्ध रखने पड़ते हैं। हमारी वायु और नौसेनाएं अभी उतनी समृद्ध नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिए।

विकास के कुछ कार्यों के कारण भी रक्षा का काम और बढ़ जाता है। बम्बई हाई में तेल के कुओं की रक्षा का भार बढ़ गया है। उनकी सुरक्षा अनिवार्य है। अन्य देशों के रक्षा पर व्यय होने वाले धन के आंकड़ देखने पर रक्षा मंत्री रक्षा कार्य के लिए और धन मांग सकते हैं। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है तथा इस क्षत्र में हमने पर्याप्त प्रगति की है।

हमने अणुशस्त्र न बनाने का प्रण किया है और इसी कारण हमने इस क्षमता का विकास भी नहीं किया। इस कारण हमारा उत्तरदायित्व इस दिशा में और बढ़ गया है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारा रक्षा उत्पादन और बड़े तथा हम इस तरह की कूटनीति अपनाएं जिससे कि हम विश्व में अकेले न पड़ जाए। सन्तोष की बात है कि सरकार सही नीति अपना रही है।

अन्त में, मैं रक्षा अधिकारियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। रक्षा मंत्री इस बात की ओर ध्यान दें, कि रक्षा अधिकारियों को सेना छोड़ने से पहले इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए कि सेना से अलग होने पर उन्हें किसी अन्य क्षेत्र में खपाया जा सके।

Shri M.C. Daga (Pali) : We should be very vigilant in regard to the security of our borders with Pakistan and China in view of the frequent incidents going on there. Of course, it is correct that whenever there was any such incident our defence forces gave a fitting reply. But at the same time it has to be realised that the defence forces alone should not be made responsible for the Defence of the country; all the people should be collectively prepared for it. It must be understood beyond doubt by everyone that only a powerful country could hope to survive and bloom to its full growth and majesty.

It is with this purpose in view that the N.C.C. was introduced. But it is limited to a small section of our students. It is time, Government think of making it compulsory for all the students. That is the only sure way of creating defence consciousness among the people.

When we are spending a huge amount on defence of our country, we have to ensure that it is properly utilised. Unfortunately, we found from various reports that it is not so. For example the Public Accounts Committee have stated in their Report of 1974 that out of the 2587 boats purchased by the Defence Department only 669 boats are in serviceable condition. Again, inregard to the full utilisation of Defance porduction to utilise the spare capacity of the extrusion press procured at a cost of Rs. 665.97 lakhs in foreign exchange have not so far been successful. This kind of wastage should be stopped.

As regards the expenditure incurred on Pakistan's prisoners of war the Defence Minister has in reply to a question said that it would be recovered from that country. We do not know whether this recovery has been made or not. The Defencc Minister should enlighten the House in this regards.

Defence production units have been opened in different parts of the country. But none has so far been opened in Rajasthan. Government should consider this matter.

In Rajasthan there is great shortage of boarder roads. They are not sufficient for the transport of Defence material. Some steps should be taken towards this direction.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

श्री जी० विश्वनाथन (वंडीवाश) :— देश की सुरक्षा का भार वहन करने के लिए हम नए रक्षा मंत्री का स्वागत करते हैं । उन्होंने हमें बार-बार देश की प्रभुसत्ता बनाए रखने का आश्वासन दिया है । विश्व में सब शस्त्रों के निर्माण में होड़ लगी है । दोनों बड़ी शक्तियों का रक्षा व्यय प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है ।

हमारे रक्षा बजट में भी वृद्धि हुई है । 1960-61 में जब कि यह 600 करोड़ रुपए था अब यह 2544.0 करोड़ रुपए है । यह कुल व्यय का 19 प्रतिशत है । यह वृद्धि पाकिस्तान द्वारा अपने रक्षा बजट में वृद्धि करने के कारण तथा विदेशी मदद के कारण हुई है ; सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा है कि 5 बड़े राष्ट्र अपने रक्षा बजट में 10 प्रतिशत की कटौती करें । भारत इसका समर्थन ही न करे वरन् अन्य विकासशील देशों से भी ऐसा करने का अनुरोध करे । रक्षा मंत्री देश के सीमित संसाधनों को ध्यान में रख कर फिर से रक्षा योजनाओं का निर्माण करे । प्रादेशिक असंतुलनताओं की भांति देश की तीनों सेनाओं में काफी असंतुलन है । नौसेना की हमेशा उपेक्षा की गई है । रक्षा मंत्री यह सुनिश्चित करें कि हमें कम से कम दो विमान वाहक पोत अवश्य प्राप्त हों ।

पाकिस्तान को चीन और अमरीका से हथियार प्राप्त हो रहे हैं शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरन्त बाद श्री भुट्टो पश्चिमी देशों से आधुनिक हथियार खरीदने के लिए चले गए थे । हथियार बेचने वाले देश भी बेचने के लिए तैयार हैं क्योंकि वह एशिया के इस भाग में शांति नहीं बने रहने देना चाहते । हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं ।

हम यह भी सुन रहे हैं कि कई शक्तियां बंगला देश को आधुनिक हथियारों को बेचने की इच्छुक है, इन शक्तियों के लिए हथियारों की सप्लाई अपने विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने का एक साधन है लेकिन भारत जैसे विकासशील देश को इसके लिए भोजन, कपड़ा, मकान, दवाइयों इत्यादि को तिलांजलि देनी पड़ती है । इसलिए सभी विकासशील देशों को मिल कर रक्षा व्यय में कटौती सुनिश्चित करनी चाहिए साथ ही हम यह भी नहीं चाहते कि रक्षा मंत्री कुछ कम सतर्क हो जाएं क्योंकि चीन और पाकिस्तान हमारी सीमाओं पर हैं ।

हमने सबसे पहले पंचशील की घोषणा की थी और हम इस पर अमल करते रहेंगे । हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे परन्तु साथ ही अपनी भूमि पर भी किसी को आक्रमण नहीं करने देंगे ।

जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास का संबंध है केन्द्रीय क्षेत्र में कुछ कोटा रखा गया है लेकिन राज्यों में कोई ऐसा कोटा नहीं है । उन्हें ऋण सुविधा नहीं दी जाती और उनके भूखों रहने की नौबत आ गई है । हमें अपने जवानों को यह आश्वासन अवश्य देना चाहिए कि एक बार सेना से निकाले जाने के बाद उन्हें सड़कों पर दर दर नहीं भटकना पड़ेगा । मेरा रक्षा मंत्री से अनुरोध है कि वह इस मामले पर राज्य सरकारों से विचार विमर्श करें । जिला सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं ताकि वह अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर सके ।

हाल ही में बम्बई में तस्करी का माल लाने वाला एक जहाज पकड़ा गया है और हमें पता चला है कि सशस्त्र सेनाओं के कुछ अधिकारियों का भी इसमें हाथ था यह वाकई बहुत दुख की बात है। मंत्री महोदय को इस मामले की जाँच करानी चाहिए तथा दोषी अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Mr. Deputy speaker, Sir, whenever the question of security of the country comes before us we are reminded of those martyrs who had sacrificed their lives for the sake of this country. First of all I pay tribute to them.

Our land forces have established their supremacy in the whole of the world even during the British regime. After independence also they made their mark in the wars against China and Pakistan. Therefore it is not proper to say that the morale of our forces needs to be boosted. This morale is already very high. A point is made that the information given in the Ministry's Report in regard to our defence preparedness is very inadequate and the Defence Minister should come forward with more details in this regard. In our view whatever information is given is quite sufficient and it will not be in the interest of the nation to disclose any more details. The Defence preparedness is something which should always be kept secret. In fact even the information that has been given should not have been disclosed.

It is said that the Air force and Navy should be strengthened. This is no doubt a very valid point. We must improve our radar system so that we can intercept all types of aircraft and do not allow them to enter our territory.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to some basic problem that are being faced by our Jawans. There is a geat need to improve the quality of food and clothes being supplied to them. Many of our Jawans were killed in our war with Pakistan and China. Some of them have become crippled. Government had given assurances to them that they will be given land and they will be provided with a house etc. but those assurances have not been fulfilled. Therefore it is necessary to pay attention to the dependents of Jawans that were killed in war.

As far the question of rehabilitation of the retired personnel is concerned, at present the arrangment is not satisfactory. The private sector do not give any facility to these people. Government should fix a special quota for these people in various services so that they are absorbed there.

The pay of the Jawans is very meagre, in fact a jawan gets less than what a peon gets. It is high time that Government increases not only the pay of the jawans but also their pension. Even if this puts burden on our budget it should be done.

There is no use finding faults with the names of the regiments. There is nothing parochial about it. When we ourselves can use. Surnames indicating our caste with our names what is the harm if the regiments are also named in this manners.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Deputy Speaker, sir, I am grateful that you have given me an apportunity to speak on the defence of the country. I hope the new Defence Minister will perform his duty with greater confidence and the defence of the country well remain safe in his hands. He is a man of determination.

It is a well known fact that we are the lovers of peace and we want peace everywhere But the security of the country cannot be ignored we are known for our policy of disarmament and we have always played a leading role in advocating total ban on nuclear weapons.

We have repeatedly demanded that Indian Ocean should be a zone of peace. Even the U.N.O. has adopted a resolution to this effect. The Soviet Union has also repeated by stated that this area should be allowed to remain a zone of peace. The false propaganda made by the United States against certain countries has been contradicted by those countries and there is no threat or danger from any of them. Therefore, there was absolutely no necessity of any U.S. naval base in the Indian ocean. The evaluation of the situation made in this Ministries report is far from truth and also against our policy and interest.

Our army officers and jawans should be given nationalist training and they should be taught the objectives of socialism. It is hoped that the Defence Minister will pay attention to this aspect that our forces have a clear conception about the values which they have to protect and preserve.

Refrence has been made to the secrecy of defence matters. One has to agree that in the matters pertaining to Defence some secrecy has got to be maintained. It is still not known who are the elements who killed our eight Air Force officers just a few hours before the murder of Mujiburrahman in Bangladesh.

It is said that in certain countries like Egypt, Iran or Pakistan, the defence expenditure has gone up in proportion to their local income. I do not think it necessary to increase the proportion of defence expenditure in this country.

The main objective behind the defence production should be to acheive self sufficiency in the production of military equipment and hardware. We have made great strides in the field of defence production. But it is not necessary to copy other nations in increasing the defence expenditure. However, it is essential to step up our efforts to make our entire sea coast fully secured at the lowest cost.

Reference has been made to the question of ex-servicemen. Government should devise some way, so that they can set up small scale industries in backward areas after their retirement. It will also help in bringing about industrialisation of the country.

Time has now come when the proportion of officers promoted from lower ranks should at least be increased by fifty percent. Then, the disparity between the officers and jawans in regard to mess or means of recreation which is a creation of British Government should also be done away with. Rather it is desireable to create a sense of common brotherhood among them.

The Darbhanga Airport has been constructed for the purpose of defence. The danger from North has not ended. Therefore adequate attention should be paid to this airport which is in a very bad state. It should be connected with railway or a highway.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय यह प्रसन्नता की बात है कि भारत छोटे हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है । कहा गया है कि हमारी राइफलें उत्तम कोटि की नहीं हैं थोड़ी घटिया है । लेकिन हमारी राइफलें चीनी राइफलों की तुलना में किसी किस्म से भी घटिया नहीं है । चीनी राइफलें एक अथवा दो हजार राऊंड के बाद टूट जाती है जब कि हमारी राइफलों से 10,000 राऊंड भी चलाए जा सकते हैं ।

जहां तक इशापुर के राइफल कारखाने का संबंध है वहां पर पुरानी मशीनें लगी हुई हैं और हालांकि उनसे भी वह अच्छा कार्य कर रहे, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस कारखाने की ओर ध्यान दें तथा इसका नवीकरण करें ताकि वहाँ पर भी आधुनिक हथियार बनाए जा सकें ।

कोशीपुर की गन एण्ड शैल फैक्टरी बहुत अच्छा कार्य कर रही है लेकिन उसके नवीकरण की भी आवश्यकता है ।

स्लिप गॉज सेट्स परियोजना भी पिछले तीन वर्ष से मंत्रालय के पास अनिर्णीत पड़ी है । उस समय संयंत्र का मूल्य के बारे में 35 लाख रुपए का अनुमान लगाया गया था । यदि इस संयंत्र की स्थापना कर दी जाती तो इसके द्वारा हमें काफी विदेशी मुद्रा की बचत हो जाती लेकिन घरेलू इस्तेमाल के लिए इन स्लिप गाँजों का आयात अभी भी जारी है अतः स्लिप गॉज संपंत्र की स्थापना शीघ्रतिशीघ्र की जाए । इस संयंत्र की स्थापना से न केवल घरेलु आवश्यकताओं को ही पूरा करने में समर्थ होंगे अपितु विदेशी मुद्रा कमाने में भी समर्थ होंगे ।

जहां तक पिस्तौल परियोजना का संबंध है मुझे याद है कि 1971 में मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री शुक्ल ने कहा था कि हम दो वर्षों के भीतर पिस्तौल बनाना शुरू कर देंगे । जब हुक्सर समिति ने केन्द्र को परियोजना पेश की तो इसकी अनुमानित लागत 1.2 करोड़ रुपये थी । और आज इसकी संशोधित अनुमानित लागत 2.6 करोड़ रुपये है। यदि सरकार पहले ही इसकी मंजूरी दे देती तो 1.4 करोड़ रुपए की बचत हो जाती ।

एक आयात किए गए पिस्तौल की कीमत 10,000 रुपए है । बहुत ऊंचे मूल्य के कारण इसे खरीदना सम्भव नहीं । देश में बने पिस्तौल की कीमत 1200 रुपए है । हमें इस परियोजना को तेजी से चलाना चाहिए, नहीं तो बंद कर देना चाहिए ।

कहा गया है कि अब तक 2774 प्रशिक्षु लिए गए हैं । यह संख्या आयुद्ध कारखानों की संख्या देखते हुए बहुत कम है । आप उन्हें कारखानों में तीन वर्ष का प्रशिक्षण दे सकते हैं । प्रशिक्षण के बाद उन्हें नौकरी भी दें । यदि नौकरी नहीं देते तो उन्हें प्रशिक्षण ही न दें ।

जहां तक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, सेवानिवृत व्यक्ति को पेंशन मिलनी आरम्भ होने में दो या तीन वर्ष का समय लग जाता है । यह विलम्ब कम किया जाना चाहिए । यह पता नहीं है कि पेंशन भोगियों की पेंशन में उपयुक्त वृद्धि क्यों नहीं की गई है ।

बंगलादेश, अमरीका या अन्य देशों से आधुनिक हथियार प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है । बंगलादेश को भारत से या बर्मा, चीन अथवा पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है । सरकार को इस बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए ।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा-पूर्व) : कल चर्चा के दौरान इस बात का पता लगा कि रक्षा कर्मचारियों पर अधिकतम काम करने की सीमा निर्धारित करने से उन्हें 50 रुपए से 200 रुपए प्रति मास का घाटा हो रहा है । इस मामले पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिए । रक्षा मंत्रालय ऊंचे मूल्य वाली वस्तुओं का उत्पादन करने का कार्य सदैव गैरसरकारी पार्टियों को देता है । इन वस्तुओं का उत्पादन रक्षा प्रतिष्ठानों में ही किया जाना चाहिए । यदि इन ऊंचे मूल्य वाले सीमित कार्य को रक्षा कर्मचारियों द्वारा कराया जाए तो उन्हें भी कुछ लाभ होगा । लेकिन उन्हें यह काम नहीं दिया गया है । यह बहुत अनुचित है। रक्षा मंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिए और कुछ करना चाहिये ईशापुर स्थित प्रतिष्ठान में पहले ही लगभग 6000 कर्मचारी सेवानिवृत कर दिए गए हैं । इस तरह विभिन्न प्रतिष्ठानों में अनेक व्यक्ति सेवानिवृत कर दिए गए हैं । लेकिन इससे हुए रिक्त स्थानों को अभी तक नहीं भरा गया है । रक्षा मंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिए ।

रक्षा कर्मचारियों के मान्यताप्राप्त नेताओं को आंशुका या भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत जेल में डाल दिया गया है । इन लोगों के मामलों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए । यदि उनके विरुद्ध तोड़-फोड़ आदि का कोई आरोप नहीं है तो उन्हे तुरन्त बहाल कर दिया जाना चाहिए ।

श्री अर्जुन सेठी (भुद्रक) : इस समय जबकि हम देश की रक्षा के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, हमें अपने देश को होने वाले खतरे की भयानकता का ही निर्धारण करना चाहिये ।

इस विशेष समय पर हमारी सुरक्षा के लिए बढ़ने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए यह हमारे लिये आवश्यक हो गया है कि हमें अपनी सीमाओं की रक्षा की तैयारी का क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ।

पश्चिम बंगाल में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अपनी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति बढ़ाने का सतत प्रयास कर रहा है जबकि उसकी यह शक्ति पहले ही बहुत बढ़ गई है । इसी प्रकार उत्तर में चीन ने हमारी मित्रता और शांति नीति की ओर अनुकूलता से ध्यान नहीं दिया है । चीन झूठे और निराधार आधारों पर भारत के विरुद्ध प्रचार अभियान चला रहा है ।

जहां तक बंगला देश का संबंध है, वहां स्थिरता नहीं है । इससे हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है । अतः देश को भविष्य में होने वाले खतरे से निपटने के लिए हमें अपनी शक्ति और क्षमता बढ़ानी है । और अधिक जवान बहाल प्राप्त करने चाहियें ताकि हमारी पैदल सेना के दस्ते युद्ध के दौरान शत्रु की सीमा में घुस कर शस्त्र प्रहार कर सकें । इसी प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त उपबन्ध करने चाहियें कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना को तैनात करने के लिये वहां उचित सुविधाएं पैदा की जाएं ।

यह भी पता चला है कि पाकिस्तान ने अपने पुराने विमानों को बदल कर उनके स्थान पर दोहरे उद्देश्य वाले मिराज विमान और मिग 19 लड़ाके विमानों का स्कवेड्रन बना लिए हैं । सरकार को फ्रांसीसी जानकारी की सहायता से मिराज बनाने के लिए जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए । इसके बाद हमें अपने समुद्र की टोह लगाने के लिए विमान का विकास करने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि हमारी नौसेना हर तरह से सुदृढ़ हो जाये ।

कुछ वर्ष पहले प्रधान मंत्री द्वारा एक नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन किया गया था। लेकिन बाद में इस केन्द्र को शीघ्र चालू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस केन्द्र को शीघ्र चालू किया जाना चाहिये ।

इसी प्रकार हमें बताया गया कि उड़ीसा में एक छावनी बनाई जा रही है। यदि यह सच है तो रक्षा मंत्री जी को चाहिये कि छावनी बनाने के लिए शीघ्र उपाय करें।

यह सोचना ठीक नहीं है कि सेना में भर्ती के लिए केवल लड़ाके समुदायों या लड़ाकी जातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि देश के सभी भागों से अधिकारियों और जवानों की भर्ती की जाये और सभी राज्यों में भर्ती के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जायें।

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोग्रा) : पाकिस्तान की सैनिक शक्ति में वृद्धि, खाड़ी के देशों द्वारा तेल से प्राप्त धन से आधुनिक हथियारों की खरीद, चीन के साथ अस्थिर सम्बन्ध और बंगला देश की घटनाओं ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम विकास कार्यों पर अपने संसाधन खर्च करने के स्थान पर रक्षा पर अधिक व्यय करें।

सरकार को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करने हैं। लेकिन निर्णय करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। रक्षा पर खर्च किया गया 1 रुपया विकास कार्यों के लिए 1 रुपया कम खर्च करना है। सरकार को शस्त्र खरीदते समय यह ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि उनकी उपयोगिता अधिक से अधिक हो। चूंकि प्रौद्योगिकी का विकास निरंतर होता रहता है। अतः शस्त्रों को शीघ्र ही बदल कर नवीनतम हथियार खरीदने होते हैं। इसलिए रक्षा व्यय का अनुमान लगाते समय कम से कम पांच वर्ष की अवधि को ध्यान में रखना होगा। हमें किसी महाशक्ति से शस्त्र खरीदने के स्थान पर किसी वाणिज्यिक फर्म से शस्त्र खरीदने चाहिये।

हमें हथियार खरीदते समय यह ध्यान भी रहे कि उन हथियारों से हमारी वर्तमान शक्ति और कार्य-क्षमता में वृद्धि हो। कम खर्च करके अधिक लाभ कमाने की नीति अपनायी जानी चाहिये।

रक्षा परिव्यय अनिवार्य तो है परन्तु आर्थिक विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बात भी सोची जानी चाहिए। अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए शांति काल में हम क्या विकास कार्यों का प्रबन्ध कर सकते हैं, इस ओर भी ध्यान दिया जाये।

बहुत से हृष्ट-पुष्ट नवयुवकों को प्रतिवर्ष सेना से निकाला जा रहा है। यदि इन व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाये तो इससे आर्थिक विकास पर काफी अधिक प्रभाव पड़ेगा। सैनिक सेवा को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में प्रयोग में लाने की काफी संभावना है। हमारी सीमाओं पर ऐसे क्षेत्र हैं जो वर्षों तक संवेदनशील बने रहेंगे। अतः सेना से अलग किये जाने वाले व्यक्तियों को इन संवेदनशील क्षेत्रों में बसाया जाये और उन्हें अर्ध-स्थायी सुरक्षित टुकड़ियों में रखा जाये।

हमारे देश में ऐसे अनेक रक्षा उत्पादन संयंत्र हैं जो रक्षा सामग्री की तुलना में नागरिक या असैनिक प्रयोग का सामान अधिक बनाते हैं। यह सुअवसर है जबकि सरकार को इन कारखानों की जांच करनी चाहिए और उन्हें रक्षा उत्पादन व्यवस्था से अलग कर औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन कर देना चाहिए। सम्पूर्ण रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठान की व्यापक प्रणाली विश्लेषण करने उसकी प्रबन्ध व्यवस्था की लेखा परीक्षा करने का समय आ गया है।

सेवाओं में अपेक्षाकृत अधिक तालमेल लाने की आवश्यकता है । इस कार्य के लिए संयुक्त कर्मचारी वर्ग या किसी और रूप में एक संरचना विकसित की जानी चाहिए । लेकिन सेवाओं में हवाई निगरानी करने के बारे में हाल ही में विवाद उठा है । यह ठीक नहीं है कि एक सेवा दूसरी सेवा से विवाद करे और सभी प्रकार के जन सम्पर्कों को उपयोग में लाये ।

सरकार को अधिकारियों और जवानों के संबंधों की जांच करनी चाहिए। उच्च आय वाले अधिकारियों पर सीमा लगानी चाहिए जिससे बहुत लोगों को लाभ हो ।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : I congratulate the Prime Minister for appointing the right man at the right place. The Defence Minister deserves tributes for taking measures to increase the period of active service and the amount of pension after retirement.

There should not be any controversy in regard to the recruitment for the armed forces from the marital or non-marital races. It is not correct to bring in politics in the armed forces. It is in the national interest to select right persons who are able to withstand the tough life of a Jawan. Every body should be provided with the right type of job.

Some reference has been made to the increasing military power of Pakistan. However we should not be unduly perturbed of Pakistan's power. Rather we should be alive to the situation. Our training programmes should be intensified and better facilities should be provided in their mess because as you have stated army moves on its stomach.

During peace times good accommodation should be provided to jawans so that they could keep their families with them. Our army officers should be free from financial worries.

श्री अनन्त राव पाटिल (खेड़े) : उपाध्यक्ष महोदय मैं रक्षा उत्पादन मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि छोटे शस्त्र बनाने के काम में हम आत्मनिर्भर हो गये हैं । देश का सबसे बड़ा आयुध कारखाना पूना में है । यह कारखाना सौ वर्ष पुराना है और इसके अधिकांश उपकरण पुराने और अनुपयोगी बन गए हैं । इस कारखाने का आधुनिकीकरण करना चाहिए और वहां के श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में भागीदार बनाना चाहिए । जहां तक आयुध कारखानों का संबंध है, उनकी प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों को हिस्सा लेने का अवसर दिया जाये परन्तु इन कारखानों में कार्मिक संघ नहीं होने चाहिएं ।

हमारे सीमावर्ती पड़ौसी देशों द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रामक सैनिक तैयारी की जा रही हैं । उनकी क्षमता का सामना करने के लिए हमें अपने रक्षा क्षेत्र में समुचित आयोजना करनी चाहिए । हमारी वायुसेना के पास विमान तथा अन्य उपकरण आधुनिकतम होने चाहिएं । हमारे केनबरा तथा अन्य विमान अब पुराने हो चुके हैं । सन्देह है कि हम उनसे मिराज जैसे विमानों का मुकाबला कर सकेंगे । पाकिस्तान ने फ्रांस तथा अन्य देशों से मिराज और अन्य आधुनिक विमान प्राप्त किए हैं । इस ओर हमें गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए ।

आज हमें उत्तर, पूर्वोत्तर और पश्चिमी सीमा पर खतरा है । पाकिस्तान को सैनिक सामग्री तथा अन्य हथियार केवल चीन से ही प्राप्त नहीं हुए बल्कि फारस की खाड़ी के अन्य देशों के माध्यम से, अमरीका, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों से भी प्राप्त हो रहे हैं। अतः हमें अपनी सेना तथा रक्षा तैयारियों को बहुत अधिक सुदृढ बनाना है। रक्षा परियोजनाओं के लिए संसाधनों की कमी का बहाना नहीं किया जाना चाहिए ।

रक्षा अकादमी में प्रायः धनी परिवारों के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता है और वे सेना में अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अकादमी में प्रवेश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों लिए भी कुछ अनुपात निर्धारित किया जाना चाहिए।

जवान जब युद्ध क्षेत्र से वापस अपने घरों को जाते हैं या सेवा निवृत्त होते हैं तो उन्हें समाज में कोई सम्मानीय स्थान नहीं मिलता। उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए अन्यथा उन नवयुवकों को रक्षा सेवाओं की ओर आकर्षित नहीं कर सकते।

छावनियों की प्रबन्ध व्यवस्था में भी बड़ी गड़बड़ है। छावनी का चेयरमन प्रायः कोई मेजर या कर्नल होता है। लेकिन उप-चेयरमैन गैर-सैनिक होता है। इस कारण छावनी का प्रबन्ध ठीक से नहीं हो पाता। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

लगभग 35 या 40 वर्ष पूर्व रक्षा कार्यों के लिए हजारों एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई थी। उसमें बहुत सी भूमि खाली पड़ी हुयी है और रक्षा कर्मचारी उसे उपयोग में नहीं ला रहे हैं यह भूमि कृषकों को एक वर्ष या एक फसल के लिए किराए पर दे देनी चाहिए ताकि इसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जा सके। इन शब्दों के साथ में अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं।

श्री डी० बसुमातारी (कोकराझार) : रक्षा के दृष्टिकोण से असम एक सामरिक महत्व का राज्य है। किन्तु वहां सड़कों और पुलों की बहुत कमी है। 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात् प्रधान मंत्री पं० नेहरू ने वहां पहला तथा दूसरा राजमार्ग बनाने के आदेश दिए थे। बड़ी धनराशि व्यय करके नदियों पर पुल बनाए गए थे। लेकिन अब सड़कों की उपेक्षा हो रही है जबकि स्थितियां हमारे प्रतिकूल हैं। केवल चीन और पाकिस्तान ने ही हमारे विरूद्ध शत्रुतापूर्ण रवैया नही अपनाया अपितु बंगला देश में भी हमारे प्रति अमित्रता पूर्ण रवैया अपना रहा है। हमें उनकी मित्रता पर विशवास नहीं करना चाहिए और आवश्यक रक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए असम में आश्यक आधारभूत ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। रक्षा मन्त्रालय रक्षा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक हैं। उनका कहना है कि इससे सेवाओं में एकता भंग हो जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण का सिद्धान्त संवैधानिक उपबन्ध है। जब अन्य मन्त्रालयों में इसका पालन किया जाता है तो रक्षा सेवाओं में भी इसका प्रयोग वर्जित क्यों किया गया है। अतः इस आरक्षण की नीति को स्वीकार किया जाना चाहिए।

***श्री एस० राधाकृष्णन** (कुड्डालूर) : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय के लिये नियत राशि पर्याप्त है। लेकिन देश में विद्यमान स्थिति और विश्व की वर्तमान गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय को उतनी राशि उपलब्ध की जानी चाहिये जितनी कि उसे देश की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिये आवश्यक हो। रक्षा मंत्रालय को इतना शक्तिशाली होना चाहिये कि वह किसी भी समय किसी भी लागत पर देश की रक्षा कर सके।

इस बात पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये कि कहीं हमारे हथियार, लड़ाकू विमान, पोत, टैंक तथा अन्य शस्त्र पुराने तो नहीं पड़ चुके। विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि हमारे युद्धप्रिय पड़ौसी देश तकनीकी दृष्टि से उन्नत किस्म के आधुनिक हथियार तथा उपकरण प्राप्त कर रहे हैं। हमें आधुनिक शस्त्रों द्वारा उनका मुकाबला करने की स्थिति में होना चाहिये ताकि हम ऐसे

*** तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर**

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

देशों को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें और भविष्य में हम पर आक्रमण करने का दुस्साहस न कर सकें । बंगलादेश मुक्ति युद्ध के दौरान प्रक्षेपणास्त्रों के बारे में बहुत कहा गया था किंतु आज किसी को भी इस बात का पता नहीं है कि प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण देश में ही हो रहा है या उनका आयात किया जा रहा है । रक्षा के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी गुप्त रखना लोकहित में नहीं होगी । रक्षा मंत्री को हमारी प्रक्षेपणास्त्रों की वास्तविक स्थिति के बारे में हमें अधिक जानकारी देनी चाहिये ।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : यह एक विशेष प्रकार की चर्चा है क्योंकि इसमें अधिकांश माननीय सदस्य रक्षा मंत्रालय को दिये जाने वाले धन में वृद्धि करने के लिये कह रहे हैं।

(श्री० जी० विश्वनाथन् पीठासीन हुये)

(Sri G. Viswanathan in the Chair)

लेकिन ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्रालय अधिक राशि की मांग करने में संकोच कर रहा है।

हमारी राष्ट्रीय परम्परा चिरकाल से ही महत्वपूर्ण रही है और हमारा देश अगले दस वर्षों के अंदर विश्व की एक महान् शक्ति बनेगा । आज के युद्ध जमीन, आसमान तथा समुद्र में लड़े जाते हैं । हमारे सैनिक हथियारों में से हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो कि विश्व के लिए एक नया हथियार है । इसी हथियार के माध्यम से हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की थी । किंतु समय गुजरने के साथ-साथ हमने इस हथियार की उपेक्षा कर दी और इसके बारे में सब कुछ भूल गये । हमारी रक्षा सेनाओं को रक्षा सम्भाव्यता के रूप में अहिंसा की संभावना पर विचार करने के लिए एक कार्य दल नियुक्त करना चाहिए । ऐसे हथियार का उपयोग करने वाला पहला हमारा देश हो सकता है और इससे हम उन सब बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो कि अब तक विश्व की सभी शक्तियों के बीच भ्रांति और टकराव पैदा कर रही हैं।

भूतपूर्व रियास्तों के विलय होने से पूर्व के भूतपूर्व सैनिकों को उतनी ही पेंशन मिलती है जितनी कि उन्हें 1947-48 में मिला करती थी, जबकि वास्तविकता यह है कि तब से अब तक भारतीय सैनिकों की पेंशन कई बार बढ़ायी गयी है । इस ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त वायु सेना स्टेशनों के राडार संचालकों की गत 10-15 वर्षों से कोई पदोन्नति नहीं हुई है । जो लोग लोक सेवा में उनके बाद आये हैं, वे अब उनसे वरिष्ठ हैं । उनके मामलों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मध्य प्रदेश राज्य में सिधी और रीवा जिलों के बीच के क्षेत्र में एक आर्टिलरी फाईरिंग रेंज है । रीवा तथा सिधी को मिलाने वाली एक सड़क आर्टिलरी रेंज होकर जाती है और जब अभ्यास किया जाता है तो इस सड़क पर यातायात पूरी तरह रोक दिया जाता है और फिर रीवा से सिधी तक पहुंचने में 25 किलोमीटर की और अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिये कि जब वहां आर्टिलरी अभ्यास भी करे तो यह सड़क यातायात के लिये बंद न हो।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : India was partitioned in 1947 and a new state of Pakistan emerged on the world map. Pakistan is the product of hatred and communal anger and it was due to this reason that we had to face Pakistan militarily on the Western Sector thrice after independence and the creation of Pakistan. Even after Simla agreement, intentions of Pakistan are appearing to be malacious. Unfortunately Pakistan is falling as an easy prey to the diplomatic strategies of the USA which aims at disturbing peace and tranquillity in the Indian sub-continent. It has been rushing modern arms and ammunition to Pakistan through other countries. The funds allocated for the defence of the country forms 19 per cent of the entire budget. These funds can be augmented in case we face any danger to our freedom and sovereignty.

We are capable of retaliating any attack from Pakistan. Our army consist of brave people and their morale is very high. Our civilian population will also not lag behind in supporting our armed forces in times of peace as also in the time of war.

The USA has established a base in Diego Garcia in the Indian ocean. Their object is to create tension and to interfere in the matters of littoral countries. We should not allow the Indian ocean to become an arena of super power rivalry.

We should also strengthen our naval forces further. The allocation made for the navy is still quite meagre. It should be raised considerably. Navy has not only the responsibility of guarding our coast line but also our vital oil installations which have come up recently in the Bombay High. Our navy should be equipped with the most modern an sophisticated crafts, long range missiles and submarines etc. So that it could perform it task effectively.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : सभा के दोनों पक्षों की ओर से आधुनिक, नवीनतम तथा जटिल हथियार बनाने तथा खरीदने की आवश्यकता की ओर बल दिया गया है।

कहा गया है कि रक्षा के लिये निर्धारित धन अर्थात् 2737 करोड़ रुपये समुद्र में बूंद के समान हैं। देश की रक्षा के लिये जितनी भी अधिकाधिक राशि रखी जाये वह कम ही होगी।

यह बात संतोषजनक है कि प्रत्येक सदस्य ने हमारी नौसेना के विस्तार के पक्ष में जोर देकर बोला है। हमें पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर दो और नौसेना कमांड स्थापित करने चाहियें।

हमें इस बात पर भी विचार करना है कि हमारी तटस्थता की नीति कहां तक सफल हुई है। विश्व राजनीति को ध्यान में रखते हुये हमें अपनी तटस्थता नीति पर विचार करना चाहिये। पाकिस्तान विश्व के अनेक देशों से हथियार जमा कर रहा है और चीन भी अपने रक्षा व्यय की निरन्तर वृद्धि करता जा रहा है। डाईग्ये गार्सिया के नौसेनिक अड्डे के संदर्भ में क्या हम एक आक्रामक युद्ध के लिये तैयारियां क्यों नहीं कर रहे ? हम सुरक्षा के युद्ध की तैयारियां क्यों नहीं कर रहे हैं ? इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए ही हमें अपनी सेना के गठन की ओर ध्यान देना चाहिये।

मिस्र के राष्ट्रपति सादत ने रूस के साथ 10 वर्ष पहले हुई संधि को भंग कर लिया। मिस्र, चीन के बाद दूसरा देश है जिसने रूस को पीठ दिखायी है।

सुरक्षा तैयारियों के मामले में हमें अनुभव करना चाहिये कि विश्व की महान शक्तियों की तुलना में कहां खड़े हैं।

वर्ष 1975-76 के दौरान रक्षा व्यय पर अमरीका ने 90,000 करोड़ रुपये और रूस ने, 1,00,000 करोड़ रुपये व्यय किये थे । हम जल, थल तथा वायु सेना भी आधुनिक हथियारों से लैस हैं ।

अमरीका की सेना में 21 लाख, रूस की सेना में 36 लाख और चीन की सेना में 32 लाख सैनिक है और हमारी सेना में 9.56 लाख हैं ।

इसी तरह अमरीका तथा रूस की नौसेनाओं में भी निरन्तर वृद्धि होती जा रही है । रूस विश्व की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति है । **(व्यवधान)** ।

डियगो गार्शिया की स्थिति कुछ भी क्यों न हो, अमरीका तथा सोवियत संघ दोनों ही किसी न किसी क्षेत्र में समान रूप से शक्तिशाली हैं । एशिया में अब चीन एक महाशक्ति के रूप में उभरता आ रहा है । वह निरन्तर सोवियत संघ से सहायता प्राप्त करता आ रहा है । यह ठीक है कि चीन के पास हमारे विमानवाहक विक्रांत जैसा विमान नहीं है, परन्तु फिर भी उसने अपनी नौसैनिक तथा वायुसेना में अनेक नये विमानों को ले लिया है तथा वह निरन्तर सोवियत संघ से विमान तथा शस्त्र लेता जा रहा है । अतः इन परिस्थितियों में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें सोवियत संघ से पर्याप्त मात्रा में सशस्त्र लेने से भला क्यों संकोच करना है, हमें परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप ही अपने रुख में परिवर्तन कर लेना चाहिए ।

मैं वर्ष 1971 से निरन्तर इस तथ्य का समर्थन करता आ रहा हूं कि अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली देशों को सामूहिक तौर पर एशिया की सुरक्षा के कार्यक्रम के बारे में पहल करनी चाहिए । मैं प्रत्येक वर्ष बजट भाषण में यही कहता हूं कि हमें इसके बारे में पुनः विचार करना चाहिये । प्रतिवेदन के प्रथम पृष्ठ पर ही तनाव का उल्लेख किया गया है, तथा मैं भी अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व इसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । पूर्वी तथा पश्चिमी ब्लाक के बीच विचारों का तनाव पहले ही बना हुआ है । सम्पूर्ण विश्व की तनावपूर्ण स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अब हमें अपनी रक्षा आवश्यकताओं पर पुनः विचार करना चाहिए । कम से कम हमारी नौसेना शक्ति चीन की नौसैनिक शक्ति का मुकाबला करने के सक्षमय तो होनी चाहिए । हमारे नये रक्षा मंत्री को इन सभी पहलुओं का व्यवहारिक अनुभव है तथा वह अपने गतिशील व्यक्तित्व तथा नेतृत्व के लिए भी प्रसिद्ध है । हमें आशा है कि देश रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का उचित मूल्यांकन करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेंगे । मेरा सुझाव है कि उनकी अध्यक्षता में एक रक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिये ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I would like to say something about Cantonment Boards. It is well known to all of us that Cantonment Boards Act of 1924, in ac ordance with which, the Cantonment Boards are being run, is a very old enactment. This Act now requires a complete revision so as to bring it in tune with the changed situation. Now the time has come when the functioning of cantonment Boards has to be democratised. We will have to make some improvement in its functioning for breing more and more people in its fold and for providing them more facilities. The term of Cantonment Boards should be five years. An amending bill should be brought for the same and I wish that Minister should tell us to when he will come out with amending bill.

I may draw the attention of the House to Danapur Cantonment Board. This Board is getting huge amount of taxes but necessary civic facilities are not being provided to the people. This must be looked into. Regarding recruitment offices, I may submit that there is lot of corruption in the offices situated in cantonment areas. Necessary steps should also be taken to eliminate the corruption and corrupt practices prevalent in these offices, and more specially to the office at Danapur Cantt.

Lastly I may mention about the problems of employees of cantonment board. The facilities which are made to other employees should also be made available to cantonment employees also. I hope Minister will look into all the points raised by me.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Today we are discussing very important Demands for Grants and these relate to Ministry of Defence. It is gratifying to note that the Government has dealt firmly with the forces of disruption in the country. Now the present peaceful atmosphere in the country will help us in strengthening our defence arrangement, so as to meet any external threat. It is also gratifying that our defence forces have given a very good account of themselves in conflicts with Pakistan. Every time a befitting reply has been given to Pakistan. The entire nation is grateful to defence forces. Now our new Defence Minister is a very dynamic person and we are quite hopeful that under his experienced leadership our defence forces will prosper and all sort of latest equipment will be made available to them.

Now I would like to say a few things about Pakistan. Now it is everybody's knowledge that Pakistan is busy in acquiring more and more armaments. The Simla Agreement is not being implemented by Pakistan. All sort of military help is being given by China and USA to Pakistan. Sophisticated weapons are being piled up at Diego Garcia which are passing new threats to our security. In view of all these developments, our Defence services should be modernised. More funds may be allocated to Defence Ministry for this purpose. Although India is a peace-loving country without any territorial ambitions, yet the present developments fully demand that our Defence Forces should be strong enough so that no country dared to attack us.

A lot has been said about the recent developments in China. The people are eager to come out of the atmosphere of suffocation prevailing over there. In this content I may point out that in our country also the forces which are against the democratic set up, they are worst than invaders and must be curbed down with an iron hand. We must go in for all type of sophisticated weapons.

It has been rightly pointed out that arrangement of Cantonment Boards is not satisfactory and due attention should be given to them. Some such plan should be chalked out with which the surplus land of Cantonment Boards could be utilized for agricultural purposes without causing any harm to interest of Defence Camps etc.

I do not want to go in for the figures of our Defence expenditure as compared to other countries. But at the same time I want to stress that we must strengthen our Government and all the three wings of services. I also welcome the increase in the pay and allowances of Defence personnels. We must keep our defence people fully contented and satisfied.

Shri Virbhadra Singh (Mandi) : I rise to support the Demands of Defence Ministry which a Ministry of very vital importance for the country. The Demands for the Ministry of Defence are of the order of Rs. 2700 crores which is quite a huge amount, particularly for a poor country like ours. But I may make it clear that if need be we will not hesitate to spend even some more amount for safeguarding the interests of the country. The only thing required to be ensured is that the amount allocated for Defence is properly utilized and the effectiveness of our defence forces is increased. The improper expenditure should be checked and stress be given on economy in expenditure.

A suggestion was made by some Member that we should reduce the strength of our regular army. I think when Defence preparations are being made by our neighbours, it is not the time for accepting any such suggestion. Rather at this juncture when China and Pakistan are busy in equipping themselves with latest armaments, we should strengthen our defence preparedness. With the best development of science and technology, we must keep our Defence forces equipped with latest weapons.

1 LSS/76—6

Now-a-days our country is facing a threat from China and Pakistan. Our Defence strategy should be prepared in such a way so that we may be able to face this threat. We must know as to what type of weapons are possessed by these countries.

I am sorry to point out that adequate attention has not been given to our Navy. Not it is high time for strengthening our Navy. The establishment of Diego Garcia base and the interest shown by a number of countries in the Indian Ocean has actually highlighted the need for making our Navy strong.

During the course of discussions it was Pointed out by some Members that the case of war widows are lying pending since 1971. If it is really so, it is a matter of grace concern. All necessary steps must be taken to dispose off these cases at the earliest.

Lastly I may submit that a good number of people from Himachal Pradesh are serving in Defence forces. Also a good number of ex-servicemen have settled down in Himachal Pradesh. It is a long outstanding demand of these people that a Sanik School be opened there. This demand should be acceeded to.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। रक्षा मंत्रालय द्वारा जो अच्छा कार्य किया गया है, उसकी हम सभी एक मत से सराहना करते हैं। हम अपने नये रक्षा मंत्री का भी पूर्ण समर्थन करते हैं। आज सम्पूर्ण विश्व शक्ति संतुलन के एक अजीब से दौर में से गुजर रहा है तथा सब ओर आधुनिकतम हथियार प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है। इन परिस्थितियों में यदि भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय बजट का 10 प्रतिशत रक्षा व्यय पर खर्च किया जा रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जर्मनी तथा जापान के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि सैन्य दृष्टि से तैयार रहने वाला देश, अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी पूर्ण मुस्तैदी के साथ बढ़ा सकता है। अभी हाल ही में हम ऐसे दौर में से गुजरे हैं जहां कि वियतनाम के लोगों ने आधुनिक शस्त्रों का मुकबला साइकलों पर सवार होकर तथा साधारण सामग्री प्राप्त करते हुए किया। मेरा यह कहने का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि युद्ध के लिए केवल शस्त्र ही सब कुछ नहीं होते, लोगों के हौसले तथा उनके समर्थन का भी विशेष स्थान होता है।

विश्व की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमें ईश्वर में भरोसा रखते हुये भी युद्ध के लिए सदा तैयार रहना चाहिये। प्रतिवेदन में आधुनिक शस्त्रों का उल्लेख भी किया गया है। तथा अब मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। रक्षा नीति और शस्त्र प्रणाली में अब यथार्थता पूर्ण परिवर्तन हो रहा है। सैन्य प्रोद्योगिकी में यह एक नया मोड़ है इसका अर्थ यह हुआ कि लम्बी दूरी वाले अस्त्रों से अब छोटी चीजों जैसे टैंक, पुल और हवाई जहाज इत्यादि को भी मार गिराया जा सकता है।

हमें अब आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना है क्योंकि अगले दशक में वह भावी विचारों का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस नई शस्त्र पद्धति को आहिस्ता-आहिस्ता अणु शस्त्रों में बदला जाएगा। नए हथियारों से दुश्मन को आसानी से पराजित किया जा सकेगा। और वह सस्ते भी पडेंगे हम अणु प्रौद्योगिकी की लागत को जानते हैं। हमें इस अणु प्रौद्योगिकी की लागत का इस नए प्रकार की प्रौद्योगिक क्रान्ति जो कि विदेशों में हो रही है, की लागत से संतुलन करना होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि हम एक छलांग में करूसे प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण शुरू कर देंगे। हो सकता है इस काम में 10 साल लग जाएं लेकिन एक न एक दिन शुरूआत तो करनी होगी। मिग 21 को मिग 23 के समान आधुनिक बनाना होगा। सोवियत संघ सैन्य प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में हमारा मित्र है। हमें इस मामले पर उनके साथ बातचीत करनी चाहिए।

डियागो गार्सिया में एक नौसैनिक अड्डा बनाया जा रहा है । इस बात को अच्छी तरह समझते हुए कि चीन और पाकिस्तान हमारे पड़ौसी देश हैं और उनसे हमें खतरा है, हमें अगले कुछ वर्षों तक अपनी प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने तथा सैन्य तैयारियों को बढ़ाते रहना चाहिए । हमारे पास असीम जन-सम्पदा है । उनमें से कई लोग बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाले तथा अपने कार्य में दक्ष हैं । यदि उन्हें अवसर दिया जाए तो निश्चय ही 20 शताब्दी का अंतिम चरण भारत का ही होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : रक्षा मंत्रालय ने अपंग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कल्याणकारी उपाय किए हैं मैं उनका समर्थन करती हूं । मैं कांग्रेस दल की नेता की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि हम चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए हैं और देश की सुरक्षा को खतरा है। हमारा रक्षा विभाग तभी सशस्त हो सकता है जब जनता उसका पूर्ण समर्थन करे जनता का समर्थन किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है । सरकार का कहना है देश में चारों ओर अनुशासन है । सरकार जिस अनुशासन की दुहाई दे रही है, वह मरघट की शांति है । मातृभूमि की रक्षा हेतु आंतरिक स्थिति में शांति का होना बहुत आवश्यक है । देश में चारों ओर क्या घटनाएं हो रही हैं, इस बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि प्रैस पर अंकुश लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें हाल ही में गुजरात, केरल तथा अन्य स्थानों में हुई अप्रिय घटनाओं के बारे में जानकारी मिली है । हम सब अपनी मातृ भूमि को प्यार करते हैं । ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए ।

गांधी जी का कहना था कि कम से कम ताकत अजमानी चाहिए । मद्रास में राष्ट्रपति शासन के दौरान जितनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया उतना बड़ा प्रदर्शन शायद पहले कभी नहीं हुआ । स्वतंत्रता के दमन हेतु सैनिक शक्ति का प्रयोग उचित नहीं ।

रक्षा मंत्री का कहना है हम दुश्मन का सामना करेंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे । लेकिन क्या यह सबक वह जनता के क्षुब्द हृदय और मस्तिष्क से सिखाएंगे अथवा प्यार से । आप एक ओर तो लोगों का दमन करते हो और दूसरी ओर उनका समर्थन प्राप्त करना चाहते हो । रक्षा मंत्री को निपुण होना चाहिए और उन्हें जनता का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए ।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : Mr. Chairman Sir, I had decided not to participate in this debate but after hearing the speech of the hon. Member, Shrimati Lakshmi kanthamma I have decided to speak few words on the subject. It is a well known & fact, that there are certain elements in the country which want to undo all that has been achieved during emergency. They are completely oblivions of the dangers that are looming large across the borders of our country. We have to be cautious about these elements.

The defence Minister has told us that our defence production is going up and we are attaining self sufficiency in this regard. We have to boost the morale of soldiers and we should not make such speeches that demoralise them. U.S.A. has established a base in Digo Garcia in Indian Ocean which poses a threat to all the littoral countries. The whole South East Asia is in turmoil. In this context it is not only necessary for India to be strong enough to counter any evil designs of her adversaries, but it has also to strengthen the hands of other non aligned countries. Therefore every efforts should be made to strengthen our armed forces.

We should be vigilent against Pakistan who is engaged in building up arsenal of sophisticated weapons. She is getting these arms from U.S.A. West European and Middle East countries. She has established military bases right against our borders. It should be admitted that America is interested in formenting trouble in the sub continent. This should be looked into seriously.

Financial constraints should have no meaning when the question of safegaurding the country's security and territorial integrity is there. No sacrifice should be considered too much for strengthening our defence we are always prepared to meet any eventuality. Whenever there was any aggression on our land the whole nation stood as a man.

With these words I thank you for giving me an apportunity to speak on the subject.

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : सभापति महोदय मैं सभी माननीय सदस्यों का रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए ग्राभारी हूं । ग्रापातस्थिति की घोषणा के बाद हम देश में ग्रनुशासन कायम करने में समर्थ हुए हैं ।

(ग्रध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[Mr. Speaker in the chair]

हमारा एक शांतिप्रिय देश है । हम सहग्रस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं ग्रौर न हमें क्षेत्र विस्तार की इच्छा है लेकिन हमें सभी प्रकार के बाहरी वायु, जल, थल, खतरों का सामना करना है। जहां तक स्थल संबंधी खतरों का प्रश्न है कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमें उत्तर ग्रौर पश्चिम से खतरा है साथ ही हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि हमें वायु ग्रौर जल क्षेत्र से भी खतरा है । पाकिस्तान ग्रपनी नौसेना को मजबूत बना रहा है । 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने न केवल ग्रपनी क्षतिपूर्ति ही की है ग्रपितु ग्राधुनिक शस्त्रों, विमानों, टैंकों ग्रौर फ्रिगेटों को भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है ।

प्राय: प्रत्येक सदस्य ने दियागो गार्सिया का उल्लेख किया है । यह 11 वर्गमील का एक छोटा सा द्वीप है । 1965 में ग्रंग्रेजों ने यह द्वीप मॉरीशस से 30 लाख पौंड में खरीदा । वह इसका संचार ग्रड्डे के रूप में विकास करना चाहते थे। 1966 में यह स्थान पट्टे पर 50 वर्षों के लिए ग्रमरीका को संचार ग्रड्डे के लिए दे दिया गया । लेकिन बाद में दोनों देशों में एक समझौता हुग्रा जिसके फलस्वरूप दियागो गार्सिया को पूर्ण नौसैनिक ग्रड्डे में बदलने की बात मंजूर कर ली गई । दियागो गार्सिया के मूल निवासियों को मारिशस भेज दिया गया है ग्रौर ग्रब इसका पूर्ण नौसैनिक ग्रड्डे के रूप में विकास किया जा रहा है । ग्रमरीका पहले से ही वहां 8000 फुट लम्बा हवाई क्षेत्र बना चुका है ग्रौर वे ग्रब उसका विस्तार कर रहे हैं ताकि हिन्द महासागर के समुद्री सर्वेक्षण हेतु ग्रधिक ग्राधुनिक ग्रौर भारी विमानों को वहां लाया जा सके । हम हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाना चाहते हैं लेकिन बड़ी शक्तियों की उपस्थिति समस्याएं उत्पन्न कर रही है । हमारे प्रयासों ग्रौर विरोध के बावजूद भी बड़ी शक्तियां ग्रपने पोतों को हिन्द महासागर से नहीं हटा रही हैं । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सदस्यों ने ठीक ही सुझाव दिया है कि हमें ग्रपनी नौसेना को मजबूत बनाना चाहिए । यह भी कहा गया है कि बम्बई हाई में तेल का पता लगने के बाद नौसेना की जिम्मेदारी ग्रौर भी बढ़ गई है।

हम इन सब बातों से पूर्णतया परिचित हैं । रक्षा नीति तैयार करते समय इन सब बातों का ध्यान रखा है । हम ग्रपनी नौसेना का सुधार कर रहे हैं देश की रक्षा हेतु ग्रधिक पोतों, फ्रिगेटों ग्रौर ग्रन्य उपकरणों को प्राप्त कर रहे हैं । पहले हम ग्रपने रक्षा बजट का 4 प्रतिशत नौसेना पर व्यय करते थे जबकि इस वर्ष हमने रक्षा बजट का 10 प्रतिशत नौसेना के लिए रखा है । यदि हमें राष्ट्र हेतु ग्रच्छी नौसेना के निर्माण के लिए ग्रधिक धन की ग्रावश्यकता पड़ी तो हम इस उद्देश्य हेतु ग्रनुपूरक मांगें प्रस्तुत करने में नहीं झिझकेंगें ।

पाकिस्तान बंगला देश के बनने से पहले प्रतिरक्षा पर 444.0 करोड़ रुपये व्यय कर रहा था और आज जबकि पाकिस्तान का कोई दुश्मन नहीं है । हिंदुस्तान ने साफ बता दिया है कि क्षेत्र विस्तार में उसकी कोई रुचि नहीं है 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के एक बड़े क्षेत्र पर हमारा अधिकार हो गया था लेकिन बाद में वह हिस्सा हमने उन्हें लौटा दिया । इससे स्पष्ट है कि हमारी प्रधानमंत्री की नीति किसी की भूमि हथियाने की नहीं है । इस तथ्य के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी रक्षा पर 702.0 करोड़ रुपया व्यय कर रहा है इससे पाकिस्तान की बुरी नियत का पता लगता है और हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार रहना है । हम किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने रक्षा तैयारियों के संबंध में आशंका व्यक्त की है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि रक्षा तैयारियों के संबंध में उन्हें किसी भी प्रकार का संदेह नही होना चाहिए। हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य हेतु शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे लेकिन यह दुख की बात है कि पाकिस्तान शिमला समझौते का आदर नहीं कर रहा। पाकिस्तान शिमला समझौते का उलंघन कर रहा है । दूसरे अमरीका ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर से प्रतिबन्ध हटा दिया है। चीन भी पाकिस्तान को आधुनिक शस्त्रों की सप्लाई कर रहा है यह भी चिन्ता का विषय है।

हम बंगला देश से भी अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। हम उनके शुभेच्छु है। हम बंगला देश को समृद्ध देखना चाहते हैं उनके आंतरिक मामलों में दखल देने की हमारी कोई इच्छा नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारा रक्षा बजट जितना होना चाहिए उतना नही है। हम केवल अपनी सीमाओं की रक्षा हेतु अपनी सेना को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित करना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने बजट को बिल्कुल समुचित रखा है। हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं। सारे विश्व में हम अपने कुल राष्ट्रीय उत्पाद की सबसे कम राशि प्रतिरक्षा पर व्यय करते हैं नीचे दिए गए आंकड़ों से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी इजराइल, मिस्र, सोवियत संघ, ईरान, पाकिस्तान अमरीका में प्रतिरक्षा कार्यों पर कुल उत्पाद की क्रमशः 32 प्रतिशत, 22.8 प्रतिशत, 10.6 प्रतिशत 9 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत और 6 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है जबकि भारत में केवल 2.8 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है हम प्रतिरक्षा कार्यों पर इसलिए कम व्यय कर रहे हैं क्योंकि हम देश का विकास करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही मैं यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में संप्रभुता सबसे बढ़ कर है।

हम अपनी नौसेना को भी मजबूत बना रहे हैं। नए जहाज प्राप्त किए जा रहे हैं पुराने जहाजों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। शिपयार्डों का विस्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान को अमरीका चीन और कुछ योरोपीय देशों से अद्यतन किस्म के विमान प्राप्त हो रहे हैं और हम इस बात पर आंख बंद कर नही बैठ सकते। हम अपनी वायु सेना को मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हमारी वायु सेना कमजोर है। हमारी वायु सेना विश्व में किसी भी भाग से होने वाले हमले का सामना करने में पूर्णतया समथ है।

स्थल सेना के आधुनिकीकरण तथा अधिक परिष्कृत उपकरण जुटाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम छोटे हथियारों के मामले में पूर्णतया आत्मनिर्भर हैं और मध्यम तथा बड़े शस्त्रों का भी देश में उत्पादन हो रहा है। हम छोटे, मध्यम तथा बड़े शस्त्रों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हैं।

हमारे रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों विशेषकर, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड और मजगांव डाक लिमिटेड ने रक्षा कार्यों में भारी योगदान दिया है। विशेषकर विभिन्न किस्म के विमानों, हैलिकाप्टरों, आधुनिक बिजली के समान, संचरण उपकरणों, रडार और नौसेना उपकरणों को प्रदान करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। हमारे कर्मचारी बड़ी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। और उन्होंन हमारा उत्पादन बढ़ाया है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हमें आत्म निर्भरता प्राप्त करने में सहायता दी है। इसने कई उपकरणों का डिजाइन बनाया है और अनेक कार्यों में सफलता प्राप्त की है। रक्षा कार्यों में काम आने वाले 400 से अधिक मदों का विकास किया गया है और उनका उत्पादन शुरू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप हमें कई करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। रक्षा कमचारियों की पेंशन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सिपाही से लेकर कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पेंशन बढ़ी हैं। इस वृद्धि का सारा श्रेय प्रधानमन्त्री को ही है।

स्थल सैना में भर्ती के मामले पर बहुत चर्चा हुई है। सेना में किसी भी जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। 1950 में सरकार ने निर्णय लिया था क इन्फैंटरी रेजीमेंटों का नाम एक विशिष्ट समुदाय के नाम पर एक विशिष्ट प्रदेश अथवा राज्य के नाम पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन कुछ परम्परागत रेजीमेंटों के नाम ऐतिहासिक कारणों से बनाए, रखे गए हैं, जसे सिख रेजीमेंट, डोगरा रेजीमेंट, महार रेजीमेंट इत्यादि। हमारी सेना में विशिष्ट वर्गों के रेजीमेंट भी हैं और मिश्रित रेजीमेंट हैं जिनमें सब वर्गों के लोग हैं।

सेना में किसी विशिष्ट समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है लेकिन सब बातों के समान होते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। गत कुछ वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भर्ती में 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। जहां तक कि किसी एक वर्ग तथा मिश्रित वर्ग में महार रेजीमेंट तथा सिख रेजीमेंट जैसी कुछ रेजीमेंट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पूरी तरह आरक्षित है। इन लोगों को शारीरिक स्तर में में भी कुछ छूट दी गई है और अधिकारियों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है।

पहले कुछ राज्यों ने भर्ती के मामले में कुछ असंतोष व्यक्त किया और कहा कि यह भर्ती देश के सभी भागों से की जानी चाहिए । इस पर भली भांति विचार किया गया और अन्त में यह निर्णय किया गया कि भर्ती योग्य पुरुषों को ही इसके लिए मुख्य मापदण्ड समझा जाये और इस मापदण्ड पर विभिन्न राज्यों से उनकी जनसंख्या के आधार पर भर्ती की जाये। किसी को भी अपने मन में यह बात नहीं रखनी चाहिए कि एक वर्ग लड़ सकता है और दूसरा वर्ग नहीं लड़ सकता। प्रत्येक भारतीय एक अच्छा सैनिक है।

अब भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की बात सामने आती है। यह एक गम्भीर समस्या है, क्योंकि लगभग 50,000 व्यक्तियों को सेना से निवृत्त किया गया है। लगभग 30,000 से 40,000 व्यक्तियों को पुनः रोजगार चाहिए। यद्यपि उन्हें अच्छी पेंशन मिल रही है। उन्हें भूमि भी नहीं दी जा सकती क्योंकि हमारे पास इतनी भूमि नहीं है । उन्हें सरकारी तथा गैरसरकारी उपक्रमों में रोजगार दिया जाना चाहिए।

हम उन्हें सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय आरक्षित पुलिस में भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ राज्यों में उन्हें परिवहन विभाग में चालक, वनरक्षक, गृह रक्षक तथा पुलिस में भर्ती किया जा रहा है। जहां तक तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों का सम्बन्ध है, क्रमश: 20 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। राज्य सरकारें इस संबंध में अधिक कार्यवाही नहीं कर सकती हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था हेतु मुख्य मंत्रियों से बातचीत की जायेगी।

सेवा निवृत्त अधिकारियों को गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में रोजगार देने का प्रयास किया जाना चाहिए। हमने लोगों के लिए सेवामुक्ति से पहले और उसके बाद प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है।

इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों को बस चलाने के लिए कुछ रूट आरक्षित किए हुए हैं। हम अन्य राज्यों को भी ऐसा करने के लिए कहेंगे। हरियाणा में इन्हें राष्ट्रीयकृत रोडवेजों में रोजगार दिया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में राज्य सरकारों ने काफी संतोषजनक कार्य किया है। अभी उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए क्योंकि सेवा निवृत्त सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है।

अतः यह सुझाव दिया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों को अर्द्धसैनिक तथा पुलिस में रोजगार दिए जाएं। गैर-सरकारी क्षेत्र में उनके लिए स्थान आरक्षित किए जायें। इन सेवाओं में उनकी भर्ती के लिए उन्हें आयु, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में रियायत दी जानी चाहिए। राज्यों में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों को भरने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया जाना चाहिए।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार ने जहां तक हो सका है किया है, परन्तु यह कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। कोई भी विधवा ऐसी नहीं है जिसे पेंशन न मिलती हो।

आपात स्थिति के दौरान देश के किसी भी भाग में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना का उपयोग नहीं किया गया और न ही इसका उपयोग हड़ताल आदि को तोड़ने में किया गया तथापि सैना का उपयोग प्राकृतिक प्रकोपों में राज्यों की मदद करने के लिए अवश्य किया गया है। इसका उपयोग विशेषकर हिमाचल प्रदेश के भूचाल, तथा जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, और बिहार में बाढ़ राहत के कार्यों के लिए किया गया है।

छावनी अधिनियम में संशोधन किए जाने का जिक्र किया गया है। सरकार इस पर सक्रियता से विचार कर रही है, और हम उस पर ध्यान दें रहे हैं।

एन० सी० सी० के संबंध में महाजनी समिति की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। यह कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में केवल सम्पन्न लोगों के बच्चे ही लिए जाते हैं। यह सच नहीं है। इनमें से 80 प्रतिशत बच्चे 500 रुपए प्रतिमास से कम आय वाले परिवारों में से आते हैं।

यह सन्देह व्यक्त किया गया है कि क्या हम धन का उचित उपयोग कर रहे हैं अथवा नहीं। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी रुपया हमें दिया जाता है, उसे सुचारू रूप से व्यय किया जाता है। सेना को उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कहा गया है कि सेना में बार-बार स्थानान्तरण किया जाता है। पर वास्तविकता यह है कि स्थानान्तरण बहुत अधिक और बार-बार नहीं होते हैं।

यह कहा गया है कि सेना में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए तथा उनमें एकता होनी चाहिए। हमारी सेना में राजनीति के महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं। उसमें एकता है, किसी प्रकार की राजनीति वहां नहीं है। सेना के स्तर को गिरने नहीं दिया जाएगा।

यह सुझाव दिया गया है कि जवानों के परिवारों और जवानों के कल्याण के लिए विशेष कक्ष बनाया जाएं। केन्द्र में पुनर्वास महानिदेशक और राज्य सैनिक बोर्ड तथा जिला सैनिक बोर्ड पहले ही से भूतपूर्व सैनिकों और उसके परिवारों के हितों की देखभाल कर रहे हैं।

बुलन्दशहर में एक भरती केन्द्र खोलने का सुझाव दिया गया है। मैं इसकी जांच करूंगा। जनता का मनोबल ऊंचा किए जाने का उल्लेख किया गया है। देश की जनता का मनोबल बहुत ऊंचा है। उसके नीचा होने का प्रश्न ही नहीं। आपात स्थिति के परिणामस्वरूप राष्ट्र का मनोबल उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

देश का मनोबल बहुत ऊंचा है। 1971 के युद्ध में जम्मू कश्मीर पंजाब आदि के लोगों ने सेना की बड़ी मदद की। उन्हें अपने हाथ से खाना तक पका कर खिलाया।

अन्त में मैं सोवियत संघ का आभार प्रगट करता हूं जिसने आड़े वक्त पर हमारा साथ दिया है। इस उपमहाद्वीप में शान्ति की स्थापना में सोवियत संघ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मैं अपनी सेनाओं के मुख्याध्यक्षों को बधाई देता हूं कि उन्होंने कितनी कुशलता से अपना कार्य किया।

प्रधान मंत्री अपने साहसपूर्ण निर्णयों के लिए बधाई की पात्र हैं। उनके नेतृत्व में हमारी सेनाएं सदैव सीमाओं की रक्षा करती रहेंगी। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut Motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा रक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following demands in respect of Ministry of Defence were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		रु०	रु०
20.	रक्षा मंत्रालय	1,38,97,000	23,88,05,000
21.	रक्षा सेवाएं-सेना	13,74,79,78,000	
22.	रक्षा सेवाएं–नौ सेना .	140,18,53,000	
23.	रक्षा सेवाएं–वायु सेना	426,42,04,000	
24.	रक्षा सेवाएं–पेंशन .	95,46,87,000	..
25.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय . .	..	216,02,17,000

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 7 अप्रैल, 1976/18 चैत्र, 1898 (शक) के 11 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, April 7, 1976/ Chaitra 18, 1898 (Saka).

MGIPRRND—1LSS/76—Sec. I—D—28-8-76—200.